MKS-HMS/11.00/1A

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

Q.No.321

SHRI Y.P. TRIVEDI: Sir, the first question is relating to the shifting of the Office. My first supplementary is like this. This is the Institution which has given us some of the very outstanding movies like "Gandhi", "Salaam Bombay" and others. Now, this Institution has become almost ineffective. Does the Government have any plans to put some money, inject some life into it?

MR. CHAIRMAN: That is not relating to the question.

SHRI Y.P. TRIVEDI: But that is relating to the same Institution.

MR. CHAIRMAN: Yes, that relates to the same Institution, but you have asked a specific question. Please read part (a).

SHRI Y.P. TRIVEDI: No, no, Sir. But whether the Government has any plans to put some money into this Institution so that it can make some television movies like "Gandhi" and others so that we cannot have to, thereafter, go on seeing embarrassing television shows like "Sach Ka Samna".

MR. CHAIRMAN: Trivediji, it is a very valid question, but not coming out of this. ...(Interruptions)...

DR. KARAN SINGH: Sir, the question of shifting may be arising out of the performance of the Institution. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Let the question be answered.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Will the hon. Member, please, repeat the question?

श्री सभापति : आप question repeat कर दीजिए।

SHRI Y.P. TRIVEDI: Sir, this Institution has become ineffective. ...(Interruptions)...

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, it is true that the NFDC which was founded in 1975 and, then, shifted with the merger of two other Corporations, in 1983, started functioning and produced some very good movies, 200-300 movies, as my hon. Colleague mentioned, by well-known, established, renowned film directors. In recent days, it has seen not very happy times, and the Government has advanced working capital loans, aggregating to almost Rs.20 crores for 2005-06 and 2006-07. We are thinking of giving them more equity, and Rs.6.5 crores have been released for 2008-09, for the Eleventh Plan, so that they can take up a greater number of films by regional directors, first-time directors, up to Rs.2 crores, or whatever the nearby figure. In the meantime, Sir, as a Ministry also, we have written to all the hon. Union Cabinet Ministers and Chief Ministers. They all have a high budget for their publicity components, and we have asked them to use the facilities available in the NFDC, the infrastructure and the expertise so that they could get work and the State Governments could get good films too.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Second supplementary, please.

SHRI Y.P. TRIVEDI: Sir, this sub-titling lab was shifted to Chennai. Does the Government have any plan to shift it back to Mumbai?

SOME HON. MEMBER: "Sub-title" makes this sub-title!

MR. CHAIRMAN: I don't see the sub-title!

SHRI Y.P. TRIVEDI: Sir, sub-titling lab.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Sir, at the moment, the Government is not thinking on this issue.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Rajeev Shukla.

(Followed by TMV/1B)

-MKS-TMV-DS/1B/11.05

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, I would like to thank the hon. Minister for making it clear that the NFDC is not being moved to Delhi. The NFDC has become a merely trading body. For the last 5-6 years it has been sourcing the movies to the Doordarshan only. That has been the major job of the NFDC. I don't think that it has been created for that purpose. I think that it should be converted into a National Film Finance Development Corporation. Will she consider this proposal?

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, it is true that the NFDC used to get films for Doordarshan. But that is stopped some time ago. That is why the NFDC has to be supported and strengthened. They have the infrastructure. They have a large number of employees. Some of them have taken VRS. With a more comprehensive body, as I mentioned earlier in my response, we are trying to source work so that the NFDC's talents can be used to the optimum capacity.

DR. K. MALAISAMY: Sir, the Minister has admitted that there is no proposal to shift the NFDC. But my question is different. Assuming, for the sake of argument, that there is a proposal to shift it from one place to another...

MR. CHAIRMAN: That is hypothetical.

DR. K. MALAISAMY: ... or fixing a place for the purpose of locating an office or organisation, I am inclined to ask: What could be your parameter or basis for it, whether it is discretion-driven or demand-driven or for any other consideration which can't be explained by you in public?

MR. CHAIRMAN: I suspect that is a hypothetical question.

(Ends)

प्रश्न संख्या - 322

श्रीमती माया सिंह: सर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि मैंने जो सवाल पूछा था, उसका answer मंत्री जी ने बड़े घुमा-फिरा कर दिया है और कहा है कि जलवायु परिवर्तन और मृत्यु के बीच कोई सीधा संबंध प्रमाणित नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि वातावरण में उड़ेली जा रही कार्बन और जहरीली गैसों ने धरती के ओजोन कवच को इतना कमजोर कर दिया है कि सूरज की घातक किरणों ने भी इसे भेद डाला है। इसके कारण फसलों की पैदावार में कमी हो रही है, गरमी का प्रकोप बढ़ रहा है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं और चक्रवाती तूफान आ रहे हैं। मंत्री जी को भोपाल गैस त्रासदी के बारे में और मुम्बई में अभी जो ज्वार-भाटा उठा, उसके बारे में जानकारी हो गई और यह भी कहा जा रहा है कि मालदीव और लक्षद्वीप समुद्र के अंदर चले जाएंगे। हर व्यक्ति इससे चिंतित है, भयभीत है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि इसके बारे में वह क्या कर रहे हैं और क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री जयराम रमेश: सभापति महोदय, जलवायु परिवर्तन का क्या असर होगा, यह प्रश्न हिन्दुस्तान से संबंधित है। Global Warming का जो effect है, इस पर अपने जवाब को मैं हिन्दुस्तान तक सीमित रखना चाहता हूँ। इसके बारे में सरकारी संस्थाओं द्वारा 2003 में पहला assessment किया गया था और उसका नतीजा यह निकला कि उसका कोई clear effect दिखाई नहीं दे रहा था। Assessment में यह था कि कई जगहों पर rainfall बढ़ेगा और कई जगहों पर rainfall कम होगा। उस assessment से और कई ऐसे नतीजे निकले थे। अभी हमने दूसरा assessment शुरू किया है, जिसमें 18 महीने लगेंगे। हमारी 127 वैज्ञानिक संस्थाएँ इस assessment से जुड़ी हुई हैं। इसका क्या असर होगा, इस पर विस्तृत रूप से assessment हो रहा है। 2010 के अंत तक हम ये नतीजे publish करेंगे और तब हमें यह पता चलेगा कि हिन्दुस्तान के अलग-अलग प्रांतों में इसका क्या असर होगा? आज हम यही कह सकते हैं कि पिछले 100 सालों में minimum temperature बढ़ा है, लेकिन यह कहना कि Climate Change की वजह से मॉनसून में परिवर्तन आ रहा है, मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल - अभी conclusive scientific evidence पाया नहीं गया है।

श्रीमती माया सिंह: सर, मेरा second supplementary यह है कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 30 जून, 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई थी और उसमें कार्रवाईयों का उल्लेख किया गया था। मैं जानना चाहती हूँ कि वे कार्य योजनाएँ क्या हैं जो जारी की गई थीं और उन पर अब तक सरकार के माध्यम से क्या कदम उठाये गए हैं? क्योंकि नई प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण के कारण प्राणघातक संयंत्रों का यह जो प्रादुर्भाव हुआ है और कारखानों से जो जहरीली गैसें निकल रही हैं, उनका असर भी तो मनुष्य के जीवन पर पड़ता है!

(1सी/एकेए पर आगे)

aka-vk/1c/11:10

श्री जयराम रमेश : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने पहले सप्लीमेंट्री में ozone depletion की बात कही थी, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ozone depletion और green house gases, ये अलग-अलग हैं। Ozone depletion में हमने बहुत सफलता हासिल की है और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि Ozone Depletion Accord, जो मॉंट्रियल Accord है, उसके मामले में हिन्दुस्तान ने बहुत कदम उठाए हैं और ozone depleting chemicals का phase out में हम बिल्कुल schedule पर हैं। लेकिन, आपका प्रश्न greenhouse gases के संबंध में है, खास तौर से carbon dioxide पर है। उसके संबंध में पिछली 30 जून को, जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रीय कार्य योजना का ऐलान हुआ था - National Action Plan on Climate Change और इस National Action Plan on Climate Change के तहत सरकार ने आठ मिशन्स की घोषणा की थी और 24 ऐसे initiatives हैं, जो अलग-अलग मंत्रालयों, अलग-अलग आर्थिक activities से संबंधित हैं। हमारे President Address में भी इसका ज़िक्र हुआ है और यह कहा गया है कि इस वर्ष के अंत तक इन आठ मिशन्स के implementation की शुरुआत हो जाएगी और इसका असर आपको अगले चार-पांच साल में देखने को मिलेगा।

प्रो0 राम गोपाल यादव : सभापति महोदय, हमारे वायुमंडल में 99% तो Oxygen और Nitrogen है, केवल 1% Carbon dioxide, nitrous oxide वगैरह, जिनको

greenhouse gases कहते हैं। इन greenhouse gases का उत्सर्जन पिछले 10 वर्षों में जितना हुआ है, उतना इससे पहले के 100 वर्षों में नहीं हुआ है। आप देखिए ग्राफ उल्टा चला गया है, पहले horizontal graph था, जो अब vertical हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जनना चाहता हूं कि जब हमारे Scientists भी और सारी दुनिया के Scientists भी यह मान रहे हैं कि greenhouse gases का उत्सर्जन बहुत नुकसानदायक है, तो G8 में अभी जब प्रधान मंत्री जी गए थे, क्या इस संबंध में कोई आश्वासन अमेरिका ने दिया है कि वह Carbon dioxide के उत्सर्जन के लिए अपने industrialisation को कुछ reduce करेगा और जो developing countries हैं, उन पर इस बात के लिए दबाव नहीं डालेगा कि वे इस मामले में ज्यादा आगे आकर कोई कार्रवाई करें?

श्री जयराम रमेश : सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि Carbon dioxide emissions न केवल हिन्दुस्तान के लिए परन्तु सारे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा है और करीब 65% जो green house gases के emissions होते हैं, वे Carbon dioxide के होते हैं और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, ज्यादातर Carbon dioxide emission हमारे ऊर्जा, बिजलीघर, coal based power plants से आते हैं। इसको कंट्रोल में रखने के लिए हम power generation के क्षेत्र में नई-नई technology का इस्तेमाल कर रहे हैं - Super Critical Technology है, coal gasification technology है। यह सब हम राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत लागू कर रहे हैं और हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है, प्रधान मंत्री जी की ओर से हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हमारी per capita emission जो होती है, वह विकसित देशों से कभी आगे नहीं होगी। यानी कि विकसित देशों की आज जो per capita emission है, हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, उसी सीमा के अंदर हम per capita emission में रहेंगे। आपने G8 Statement का जिक्र किया है। उसमें हमने कोई commitment नहीं लिया है। G8 Statement, जो L'aquila, Italy में किया गया था, उसमें कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्रियों ने 2050 तक हमारा क्या aspirational उद्देश्य होना चाहिए, उसका जिक्र किया था। उस स्टेटमेंट

में कहीं यह जिक्र नहीं है कि हम विकासशील देशों पर दबाव डालेंगे और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान किसी दबाव में नहीं आएगा। अगर कोई दबाव है, अगर हम पर कोई pressure है कि हम emission reduction target लें, मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, हमारी सरकार की ओर से, प्रधान मंत्री जी की ओर से और हमारे मंत्रालय की ओर से भी, कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, हम कोई ऐसा कानून या समझौता स्वीकार नहीं करेंगे, जो हमारे विकास पर बाधा लगाए।

('1d/nb' पर जारी)

NB/1D/11.15

श्री जयराम रमेश (क्रमागत) : यह बिल्कुल साफ है। हमारे यहां पिछले दिनों जब अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हिलेरी क्लिंटन जी आई थीं, उनको भी मैंने स्पष्ट कर दिया था कि हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, लेकिन हम किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे, जहां हमारे जैसे विकासशील देशों पर legally binding emission reduction cut होगा।

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सभापति जी, मंत्री जी ने कहा कि food quality और quantity पर भी indirectly इस climate change का फर्क पड़ता है, directly नहीं पड़ता। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि साइंटिस्ट्स इसके ऊपर काम करने में लगे हुए हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या वे साइंटिस्ट्स इस aspect को भी देखेंगे, agricultural seeds and their sowing पर भी क्या वे रिसर्च करके कुछ नए तरीके किसानों को बताने का प्रयत्न करेंगे?

श्री जयराम रमेश : जैसा कि मैंने कहा कि 2003 में पहला assessment किया गया था, वह पहला assessment मोटे तौर पर था, लेकिन अभी हम detailed assessment कर रहे हैं और दिसंबर, 2010 तक इसके खत्म होने की उम्मीद है। इस comprehensive assessment के तहत agriculture, health sector, irrigation sector पर इसका क्या असर होगा, यह हम मालूम करने में लगे हुए हैं और हमारी जो 127 वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, उनसे हम यह काम करवा रहे हैं। यह एक comprehensive assessment होगा और

पहली बार हम कुछ विश्वास के साथ कह पाएंगे कि हमारे देश में मानसून पर, हिमालय के ग्लेशियर्स पर climate change का क्या असर हो रहा है। चूंकि हमारे पास अभी कुछ ज्यादा scientific evidence नहीं है, इसलिए इस बारे में अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं है। अभी एक अनुमान है, एक भय है, आशंकाएं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि विज्ञान के आधार पर दिसंबर, 2010 तक हम इस बारे में दावे से कुछ कह सकते हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय मंत्री जी, आपने अभी जो टिप्पणी की, उसमें और अमरीका की विदेश सचिव के साथ टेलीविजन पर आपकी जो टिप्पणी आई थी, इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। आपने बार-बार कहा है कि हम अपने दायित्व को समझते हैं, लेकिन अपनी प्रगति पर हम कोई भी वैज्ञानिक बंधन स्वीकार नहीं करेंगे। क्या आप देश को और दुनिया को यह प्रामाणिकता से बता रहे हैं? आपके देश में भी आपने कहा कि आप स्वयं इसके लिए वैज्ञानिक शोध कराने वाले हैं। आज दुनिया में भारत के खिलाफ जो एक प्रकार का campaign चल रहा है कि भारत emission norms को follow नहीं कर रहा है, भारत के ग्लेशियर्स ढीले पड़ रहे हैं, मानसून में बदलाव हो रहा है, तो इसके कारण दुनिया में भारत के खिलाफ एक अजीब प्रकार का विपरीत भाव बन रहा है। जब आप यह कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन legal binding को follow नहीं करेंगे, इसके बीच का जो अंतर्निहित अंतर्विरोध है, इसको प्रामाणिकता से स्पष्ट करें।

श्री जयराम रमेश : मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें बिल्कुल भी अंतर्विरोध नहीं है। मैंने यह कहा है कि हमारे National Action Plan के तहत हमने जो मिशन की घोषणा की है, उनमें 5 या 6 मिशन ऐसे हैं, जो adaptation की बात करते हैं। 2 या 3 मिशन ऐसे हैं, जो mitigation की बात करते हैं, जब हम energy efficiency की बात करते हैं, energy efficient power plant की बात करते हैं, energy efficient buildings की बात करते हैं, तो वह mitigation होता है। हमारा stand यह है कि हम mitigate करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी योजना के तहत। हम किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे .... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : अब आपने सही बोला।

श्री जयराम रमेश : हम अपनी योजना के तहत, अपनी पार्लियामेंट को confidence में लेकर .... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : मंत्री जी, क्षमा करिए, लेकिन यह बात पहले से आनी चाहिए थी .... (व्यवधान)

श्री सभापति : इन्होंने कह दिया है।

श्री जयराम रमेश : मैं पहले से यह कह रहा हूं कि मैं जब से इस मंत्रालय में आया हूं, मैं 29 मई से यह कह रहा हूं कि हम अपने बलबूते पर, हमारी योजना के तहत, हमारी पार्लियामेंट को confidence में लेकर यहीं mitigate करेंगे, किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार हम कोई legally binding mitigation स्वीकार नहीं करेंगे।

(समाप्त)

1E/GS पर आगे

1e/11.20/gs-ks

प्रश्न संख्या : 323

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : सर, 17वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे के मुताबिक हर वर्ष बिजली की खपत बढ़ेगी। जैसा कि जवाब में लिखा है कि वर्ष 2010-11 में बिजली की खपत 906.32 बिलियन यूनिट, वर्ष 2011-12 में 968.66 बिलियन यूनिट और वर्ष 2016-17 में 1392.01 बिलियन यूनिट बढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो अल्ट्रा मेगा पावर का प्रोग्राम बनाया था, उसके जो प्रोजेक्ट हैं, उनको कहां-कहां लगाएंगे और कब तक लगाएंगे?

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Mr. Chairman, Sir, the hon. Member desires to have ultra mega power plants at different places in the country for increasing the energy supply. Five projects are going to come up; one is about to commence in Gujarat; another in Andhra and Tamil Nadu; and one more, for which certain requirements, including the MoU, etc. are being fulfilled, is going to come up. We would like to go in for more and more ultra mega power plants in the country, Sir.

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हर राज्य में बिजली के अलग-अलग रेट्स हैं। जो प्राइवेट इदारे हैं, वे बिजली के रेट बहुत ज्यादा वसूल कर रहे हैं। आप क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे कि सारे देश में बिजली के रेट्स एक-समान हों ?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि..।

श्री सभापति :नहीं, आपने एक सवाल पूछ लिया है।

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : सर, मेरा (बी) प्रश्न है।

श्री सभापति : नहीं, (बी) प्रश्न नहीं होगा।

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : सर, वह इसी के साथ है। सर, जो गरीब लोग हैं, जो एक यूनिट से पांच यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, क्या आप उनको कम रेट पर बिजली मुहैया करवाएंगे ?

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Electricity charges are fixed according to State regulations. That is the policy under the Electricity Act, according to which, States are competent to decide their rates. Different States have different rates. The hon. Member desires to have economical rates for electricity, which is, of course, desirable; that is why the Government of India, the hon. Prime Minister and the Ministry also wishes that we generate more and more power and that we match the demand. Sir, rates for electricity are going to be lower in the coming times.

श्री राशिद अल्वी : सर, हम दुनिया के अंदर 7th largest producer हैं energy के, लेकिन consumption में हमारा नम्बर पांचवा है। दुनिया के अंदर जो energy per capita हम consume करते हैं, that is the lowest. इसके बावजूद 50 परसेंट पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या प्लानिंग है कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस नहीं है, वहां तक आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचाएंगे ? जो हमने न्युक्लियर एग्रीमेंट किया है, वह इसी बुनियाद पर किया है कि हम देश के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जल्द से जल्द पहुंचाएंगे, वह कब तक हम कर पाएंगे ?

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Sir, the hon. Member wishes every household in India to get electricity. Under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana, Government aims at providing electricity to every household and free electricity to every BPL household by 2012. There was a huge gap when we became Independent because the power generated was very limited. Now, in this Five Year Plan, we envisage power production of about 78,000 MW. That is the way we are going to go ahead.

Q. NO. 323 (CONTD.)

DR. C. RANGARAJAN: Sir, capacity addition during the Tenth Plan fell short of the target that was fixed for the Tenth Plan. I want to ask the hon. Minister whether capacity addition during the Eleventh Plan is taking place according to the schedule or whether there is a shortfall even there.

SHRI BHARATSINH SOLANKI: The hon. Member is concerned about the shortfall and the new projections. We had problems with hydro power, coal and other things. Our Ministry is looking into it seriously and we hope that we will be able to reach very close to the Eleventh Plan target.

(Followed by 1f/tdb)

TDB-ASC/1F/11.25

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, I want to know from the hon. Minister as to how much energy shortage is there in Tamil Nadu today and how the Central Government is going to help Tamil Nadu to meet this energy shortage.

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Sir, the supplementary put by the hon. Member does not arise out of the main question. The hon. Member should put a separate question for it.

MR. CHAIRMAN: This is not related to the main question. ...(Interruptions)...

(Q. Nos. 324 & 325 - hon. Members absent)

प्रश्न संख्या : 326

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, मैंने माननीय मंत्री जी के उत्तर को देखा है, उनका उत्तर स्पष्ट नहीं है। माननीय मंत्री जी कृपया यह बताएं कि क्या सेट-टॉप बॅक्स पर 5 प्रतिशत ड्यूटी लगाई गई या नहीं लगाई है? क्योंकि आपका उत्तर है, 'No decision has been taken by the Government or by the Telecom Regulatory Authority of India'. जहां तक हमें जानकारी है कि सेट-टॉप बॅक्स पर 5 प्रतिशत ड्यूटी लगाई गई है। मुझे यह भी

पता है कि आपके विभाग ने यह अनुशंसा की थी कि यह ड्यूटी नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि देश में digitisation का काफी विस्तार हो रहा है, इसलिए यह लगाई गई है। जो ऑपरेटर्स हैं, वे यह कह रहे हैं कि इसके कारण डेढ़ सौ से दो सौ रुपए सेट-टॉप बॉक्स की कीमत बढेगी, तो हम वह कीमत उपभोक्ताओं से वसूलेंगे। इससे तो उपभोक्ता परेशान होंगे। मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि उनको रेग्युलेशन में पावर है क्या सरकार TRAI के साथ बातचीत करेगी, ताकि इस संबंध उपभोक्ताओं की परेशानी न बढ़े, सरकार इसके बारे में क्या कोई रास्ता सोच रही है?

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, मैं माननीय सांसद रवि शंकर प्रसाद जी को यह बताना चाहती हूं कि वे मुझसे पहले इस मंत्रालय में मंत्री रहे हैं और वे स्वयं यह जानते हैं कि TRAI इस मामले में दखल नहीं देती है और जो 90 से 125 रुपए पर सेट-टॉप बॉक्स पांच परसेंट कस्टम ड्यूटी के कारण कीमत बढ़ी है, इससे broadcasters को स्वयं तय करना है कि उसको किस तरह अपने में एब्जॉर्ब करेंगे या उपभोक्ताओं पर लागू करेंगे।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, मैं इसी सवाल को दूसरी तरह से प्रस्तुत करना चाहूंगा, आप मुझे इसकी अनुमति दें। TRAI का यह भी दायित्व है कि वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे, आप उनके रेग्युलेशन को कृपा करके विनम्रता से पढ़ें। यदि उपभोक्ता परेशान होता है, तो सरकार TRAI के सामने जा सकती है, broadcasters को बुलाकर इसका निदान कर सकती है। मैंने यह पूछा था कि क्या आपकी सरकार इस दिशा में कोई पहल कर रही है?

श्रीमती अम्बिका सोनी : सर, अभी कुछ दिन पहले ही यह पांच परसेंट ड्यूटी लगाई गई है। कुछ MSOs और broadcasters ने यह ध्यान दिया है कि शायद वह सौ रुपया पर सेट-टॉप बॉक्स बढ़ाएंगे। उन्होंने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं किया है, लेकिन अगर उपभोक्ता पेरशान होंगे, तो आवश्यक तौर पर मंत्रालय उनका हित TRAI तक जरूर ले जाएगा या जो भी फोरम होगा, हम उस पर जाएंगे। मैं माननीय सांसद महोदय को यह बताना चाहती हूं कि हमने यह जरूर मांगा था कि Countervailing Duty है, उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। इस मुल्क में जिस तरह से digitisation बढ़ता जा रहा है, मेरे पास सभी आंकड़े मौजूद हैं, यदि मैं वे आंकड़े यहां पर प्रस्तुत करूं, तो सदन यह जानकर बहुत खुश होगा कि हम digitisation की ओर बढ़ रहे हैं। जो हमारे यहां indigenous producers हैं, उन्होंने भी अपना एक संगठन बनाया है। मेरी उनसे दो बार बातचीत हुई है। आज वे इस स्थिति में हैं कि वे अपनी indigenous प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। उनमें से एक तो एक्सपोर्ट भी कर रहा था। इनके अलावा कोई और भी हैं, जो इस दिशा में यह समझते हैं कि पांच परसेंट कस्टम ड्यूटी में जो 100 रुपए बढ़ेंगे, इससे उनको अपना उत्पादन बढ़ाने में और प्रोत्साहन मिलेगा। मैंने उनको न सिर्फ अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है, मैंने उनसे एक टाइम फ्रेम रेस्पांस मांगा है कि दो साल के अंतर्गत डिमांड को मीट करें, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए कीमत कम करें, ताकि लोगों को इम्पोर्ट करने की आवश्यकता न पड़े और देश में बना सेट-टॉप बॉक्स कम कीमत पर उपलब्ध हो सके। इससे रोजगार भी ज्यादा उपलब्ध होंगे और उपभोक्ता भी संतुष्ट होंगे।

(क्रमश: 1G/LP पर)

MCM-KGG/1G/11-30

श्री शिवानन्द तिवारी : सभापति महोदय, मैं माननीया मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि जब तक वह स्थिति नहीं आती है कि हमारे यहां का इंडिजिनस बॉक्स देश की जरूरत को मीट नहीं कर पाता है, उससे पहले जो हम आयात कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसके बारे में माननीया मंत्री जी ने कहा कि अगर उपभोक्ताओं को परेशानी होगी तथा कीमत बढ़ेगी और बढ़ी हुई कीमत उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ेगी तो उनकी परेशानी बढ़ेगी। तो

इन्होंने कहा है कि अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है कि जो बढ़ा हुआ दाम है, उसकी कीमत कौन बियर करेगा? मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कीमत बढ़ाई जाए या उपभोक्ताओं से ली जाए, इससे पहले इंटरवीन करके ट्राई के साथ बातचीत करके कि बढ़ी हुई कीमत उपभोक्ताओं को नहीं देनी पड़े, क्या ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी?

श्रीमती अम्बिका सोनी : मान्यवर, यह सवाल अभी उठता नहीं है, क्योंकि जो ब्रोडकॉस्टर्स हैं, जो डी0टी0एच0 - एम0एस0ओ0 हैं, जो सैट टॉप बॉक्स प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने भी अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। आप भी मार्केट फोर्सेज से परिचित हैं, कई डी0टी0एच0 प्लेयर्स हैं जो स्वयं मार्केट को विन ओवर करने के लिए, कंज्यूमर्स को विन ओवर करने के लिए निर्धारित कीमत से भी कम चार्ज कर रहे हैं। तो अगर हमने कुछ ऐसा pre-empt कर दिया तो जो आज कम दाम में मिल रहा है, शायद वह भी रुक जाए। तो मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर, मंत्रालय के तौर पर, जैसा मैंने कहा कि मैंने दोनों तरफ के लोगों से बात की है, टाइम फ्रेम रेस्पांस मांगे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से वोल्यूम बढ़ता जा रहा है, 100 फीसदी वोल्यूम बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में सेट टॉप बॉक्स जो डिजिटाइजेशन के लिए अनिवार्य हैं, सरकार की तरफ से भी बहुत ऐसे कदम उठाए जाएंगे इस दिशा में और उपभोक्ताओं को यह कम कीमत पर मिलेगा।

(समाप्त)

(Q.Nos. 327 & 328 : Hon. Members absent)

Q.No. 329

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Sir, I went through the answer. The Minister in Q.No. 323 in this House has said that he admitted that there was shortage of power in our country; I mean, Sir, energy; there is a lot of power in our country. In his answer to this particular question, he has said that he admitted that there was shortage of manpower, machinery and equipment. What is the Government doing to bridge this gap while you admit that there is a shortage and that there is going to be more demand for energy? Here, you say that there is a shortage of manpower, contractors and machinery. What are you going to do to bridge this gap?

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Mr. Chairman, Sir, the hon. Member has asked a very important question regarding how we will be matching the demand. One of our precious PSUs, Bharat Heavy Electricals Limited was capable of manufacturing equipment worth 10,000 MW which is going to increase its capacity by December 2009 to 15,000 MW, and another 5,000 MW more by 2011-12. Along with that, to match the demand, we have made an open policy. We talked about ultra mega projects and we are going to have captive merchant power plants. The Planning Commission, the Prime Minister and our Ministry wish to go further up so that we generate more power. For that, our Ministry and the Minister has invited the joint venture companies, invited people from all over. So, NTPC and BHEL are going to go in for a collaboration; an MoU has been signed. Then L&T along with MHI, Toshiba, JSW...

डा0 (श्रीमती) नजमा ए0 हेपतु ल्ला : वह तो आपका लिखा हुआ आंसर है, वह तो मैंने पढ़ लिया है।

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Madam, what I am trying to say is, we are in the process of building up the capacity on a higher side, to match our demands of the 11th Five-Year Plan.

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Sir, just now, very eloquently our Environment Minister answered about the Mission on greenhouse gases in our country. He also mentioned in his reply about the power. He also mentioned in his reply that basically the problems arise because of the power generation in our country.

(Contd. by kls/1h)

KLS/LP/1H-11.35

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA (CONTD): On the one side, we have this problem, and on the other side, the Environment Ministry would come in the picture. We have hydroelectric power and for this a lot of land is taken over by dams and bridges. Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government would have any policy, in consultation with the Ministry of Environment and Forests, to overcome the crisis of shortage of power in our country. Not even 50 per cent of the power, which we promised to have in the previous Five Year Plan, has not been generated. We have not been able to bridge that gap and, at the same time, new demands are coming up. It is a very comprehensive answer but this answer does not give any results. This is what you are doing but I want to know about what you have achieved by taking all these actions.

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Mr. Chairman, Sir, by consulting the Ministry of Environment and Forests, we sort out the problems regarding

our hydro projects, thermal projects, etc. We are looking at the present and future laws and also the issue of carbon emission and all that. That is why we are going in for 'supercritical' and that is the way we will be able to reach the target, and also we will able to work along with the Environment Ministry.

SHRI JESUDASU SEELAM: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister is very keen that we should increase the capacity. Sir, we had the occasion to review the functioning of the BHEL. The NTPC and BHEL joint venture could be taken on a massive scale because it is mentioned that hydropower projects have not been adversely impacted. It is not correct, Sir. Even the targets in hydroelectric production have come down. This is only a short-term plan, which they have indicated, but as we go along, we need lot many types of equipment, forging material, contractors, and manpower, which is also falling short. What is the long-term plan because by 2020 your requirements are going up? This joint venture accounts for only short-term supply. What is the long-term plan to meet the power demand by 2020?

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Mr. Chairman, Sir, as I mentioned, we are going to increase capacity by inviting indigenous companies also. We are going to train people. That is why NTPC and other companies are training young boys of this country. We are coming up with technology institutions also. So, everything put together, naturally, it is a long-term process. It is a plan, which is going to take three to four years minimum time to get implemented or commissioned. So, we are in the process of doing things in all the directions. As rightly mentioned by the

hon. Member, we will be requiring more equipment, higher technology, young boys working for these power plants and we will also be required to solve the problem of carbon emission and all that. In that direction, we are going ahead.

श्री महेन्द्र साहनी : माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि बिहार ऐसा पिछड़ा राज्य है, जहां बीस, बाइस घंटे बिजली नहीं होती है। क्या इस संबंध में बिहार सरकार ने एथनॉल बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है, जो अभी तक पेंडिंग है, जिस पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं हो रहा है? एथनॉल बनाने के बाद हमारे यहां बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा जिसे बिहार राज्य दूसरे राज्यों को भी दे सकता है। मैं इस संबंध में मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री भरतसिंह सोलंकी : सभापति जी, माननीय सदस्य इस बारे में सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब बाद में दूंगा, परंतु यह सवाल इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री प्रकाश जावडेकर : सभापति जी, माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं this is all rhetoric because every year we are listening that we have planned this much but we do not achieve. Every year the demand is increasing and we are not adding to our generation even to the extent of additional demand of that year.

(Contd by 1J)

SSS-SC/1J/11.40

SHRI PRAKASH JAVADEKAR (CONTD.): So, every year, gap is increasing. China is producing one lakh mega watt per year and we are not able to produce 5000-mega watt per year. That is the reality. My question is: While taking into account the real challenge of the sector and the need of growth, will the Ministry take all efforts in a mission mode? You have ordered contracts for hydro-generation to various

private players in Arunachal Pradesh. Nobody has started commissioning. No plant has been commissioned. Nothing is being constructed there and there are many issues to be sorted out with Nepal and Bhutan. Is the Government really serious? In a time bound manner, is it going to implement a mission mode and put quarterly targets?

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Mr. Chairman, Sir, the concern of the hon. Member is definitely very serious and that is why whatever he mentioned, -- about environment, about Arunachal Pradesh about our transmission line, our grid -- on all sectors, we have a time bound programme. He rightly mentioned about the Eleventh Year Plan and capacity edition and that is why we made an open policy. We had a meeting with the Power Ministers of the State where we discussed about all the problems and how together we could start it out and the process is very positively going ahead. (Ends)

MR. CHAIRMAN: Question No. 330.

(Q. No. 330 - Hon. Member absent)

Question No. 331.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I have a point of order. Sir, four questions which are listed today by Members are not present. Now, this is really very, very unfair. Therefore, Sir, you must ask.

MR. CHAIRMAN: It is unfair to whom?

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, please give notice to Members who are not present when such important questions are raised. Do they not have a responsibility? Why? What is the reason behind it? Sir, they should request you for permission to be absent. Otherwise, it is totally wrong.

MR. CHAIRMAN: If a person is absent he or she foregoes the right.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, there are occasions when Members have been in the House and...(Interruptions)... No, it is very wrong.

श्री कलराज मिश्र : मान्यवर, जिसका अगला प्रश्न है, उसको पूछ लेने दीजिए। वृंदा जी, आप इस संबंध में बाद में कहिएगा।..(व्यवधान)..

श्री सभापति : बैठ जाइए प्लीज़। इंटरप्ट मत कीजिए। ..(व्यवधान).. Are you suggesting disciplinary action against hon. Members?

श्री कलराज मिश्र : जिनका प्रश्न है, उन्हें पूछ लेने दीजिए। ..(व्यवधान)..

SHRIMATI BRINDA KARAT: No, I said, Sir,...(Interruptions)...

MR.CHAIRMAN: All right, we will discuss that question separately. (Interruptions) Please, please...(Interruptions)...

DR. K. MALAISAMY: Sir, my suggestion is...

MR. CHAIRMAN: Dr. Malaisamy, give me your suggestions later, after the Question Hour. I will take that on board. (Interruptions) How can that be supplementary? Question No. 331.

प्रश्न संख्या 331

श्री कलराज मिश्र : मान्यवर, मेरे प्रश्न के "ग" और "घ" भाग के संबंध में मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें कहा है कि "11वीं योजना अवधि के दौरान देश में वास्तविक विद्युत उत्पादन, वर्ष 2008-09 के सिवाय, सामान्यतया निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हुआ। लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी रहने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं...।" महोदय, मैंने कमी के कारणों के बारे पूछा था। मंत्री जी ने इसके कारण बताए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में जो कारण आपने बताए हैं, जो बाधाए बतायी हैं, वे बाधाएं कैसे दूर की जाएंगी? यद्यपि आपने इसके उपाय बताए हैं, लेकिन उसकी समयबद्धता क्या है, क्योंकि ये कारण तो बराबर बने रहेंगे। अगर अगले साल भी हम यह सवाल पूछेंगे तो शायद यही कारण बताए जाएंगे। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन कारणों के निवारण के लिए क्या आपने कोई समयबद्ध योजना बनायी है?

श्री भरतसिंह सोलंकी : सभापति महोदय..(व्यवघान)..

श्री कलराज मिश्र : सर, शिन्दे साहब इसका जवाब दे दें, वे सदन में मौजूद हैं।

श्री सभापति : मौजूद हैं, आप इन्हें सुन लीजिए।

श्री भरतसिंह सोलंकी : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एक मॉनिटरिंग कमेटी है, जिसके साथ मिलकर हम इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट लैवल पर या अन्य जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं के संबंध में दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ विचार-विमर्श करके काफी प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी से commissioning की तरफ जा रहे हैं।

(1के-एकेजी पर क्रमागत)

AKG-NBR/1K/11.45

श्री कलराज मिश्र : सर, मैंने समयबद्धता, time bound के बारे में प्रश्न पूछा था, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया।

मान्यवर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में कुल विद्युत उत्पादन कितना है और उसके साथ ही साथ demand कितनी है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि मांग के अनुरुप कुल विद्युत उत्पादन कितना है और वह मांग को पूरा कर पा रहा है या नहीं

कर पा रहा है और अगर नहीं कर पा रहा है, तो मांग को पूरा करने के लिए हम कब तक उतना विद्युत उत्पादन कर लेंगे?

श्री भरतसिंह सोलंकी : सर, आज हमारा उत्पादन 1 लाख 50 हजार मेगावाट है और हमारी shortage 15 हजार मेगावाट है। हमारी डिमांड निरंतर बढ़ती है और बढ़ती जा रही है। इसलिए target के साथ नए प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं। इसलिए हमने अपनी पॉलिसी को open किया है। Captive Merchant Power को allow किया है। इस open policy में हम और भी आगे जाने वाले हैं। Coal based, gas based, hydro और हमारे सभी power sectors में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी डिमांड को जल्द-से-जल्द पूरा कर सकें।

डा. कर्ण सिंह : सभापति महोदय, हम अपने देश में जो भी कर रहे होंगे, लेकिन जब तक नेपाल के साथ हमारी संधि नहीं होगी, तब तक हम जो बढ़ोतरी चाहते हैं, वह बढ़ोतरी नहीं होगी। नेपाल के साथ कई दशकों से बात चल रही है, लेकिन पंचेश्वर इत्यादि की बात आगे नहीं बढ़ रही है। उससे नेपाल को भी लाभ है और भारतवर्ष को भी लाभ है। नेपाल में अनेक परिवर्तन हुए हैं, तब भी बात आगे नहीं चल रही है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि वे स्वयं या हमारे कैबिनेट मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जो हमारे मित्र हैं, अथवा विदेश मंत्री से बात करके नेपाल के साथ बिजली के सम्बन्ध में जो संधि है, वह शीघ्रातिशीघ्र करेंगे?

श्री भरतसिंह सोलंकी : माननीय सभापति जी, बड़ी अच्छी बात है और अगर यह संधि जल्द-से-जल्द हो जाए, तो दोनों देशों का फायदा है। हमारी उनसे चर्चा चल रही है। जल्द-से-जल्द इस बात को कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए हमारी कोशिश अभी जारी है।

SHRI SYED AZEEZ PASHA: Sir, the Government's slogan is, 'Power for all by 2012.' I would like to know from the hon. Minister whether the target is achievable. If not, what are the hindrances, problems and difficulties in realising this slogan and what steps the Ministry is visualising to take in the immediate future.

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Mr. Chairman, Sir, out of the target of reaching 1.25 lakh villages, we have already reached to 62,000 and odd villages. There are hindrances with regard to terrain and in some areas there is Naxalite problem which we are all aware. That is why the Government of India has allocated Rs. 39,000 crores and we still, in Phase-II, require an additional Rs. 30,000 crores. Besides, for execution and reaching to 1.25 lakh villages, we are working with the States and different agencies and we will be reaching the target by 2012.

SHRI BHARATKUMAR RAUT: Sir, reply given to part (e) of the question by the hon. Minister is vague. If you read the reply to part (e) of the question, all the points are so vague that it does not give us any direction in which way the Government is moving.

MR. CHAIRMAN: Please put your supplementary.

SHRI BHARATKUMAR RAUT: Yes, Sir.

I would like the Government to come out with more, appropriate and accurate reply. At point (v) of the reply to part (e) of the question it was stated, "Utilization of unutilized capacity of gas-based stations on liquid fuel." What does the Government mean by that? Is there any concrete suggestion on that?

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Sir, in any project, wherever we required to top up or increase the generation and put it into our grid i.e., along with the utility/regulation by the State, we are trying to increase the capacity.

(Ends)

Q.NO. 332

MS. MABEL REBELLO: Sir, the hon. Minister in his reply has said that 201 coal blocks up to May, 2009, have been allotted and only 25 coal blocks have started production. This shows that hardly 12 per cent of coal blocks have started production. The hon. Minister also says that he went to the States and discussed the issue.

(CONTD. BY USY "1L")

-NBR/-AKG/SCH-USY/11.50/1L

MS. MABEL REBELLO (CONTD.): I would like to know what the progress is; and, how he has managed to get the companies, who have been allotted coal blocks. How has he motivated them to start production in the cancelled blocks, allotted to them?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति महोदय, माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में ऊर्जा उत्पदन की 55% आवश्यकता कोल के द्वारा ही पूरी की जाती है। कोल के प्रोडक्शन और कोल की आवश्कताओं के गैप को देखते हुए भारत सरकार ने कोल ब्लॉक्स को एलॉट करने की एक प्रक्रिया शुरू की, जिसके तहत लगभग 201 कोल ब्लॉक्स एलॉट किए गए। इसमें कोई शक नहीं कि माननीय सदस्या ने यह चिंता जाहिर की है कि लगभग 25 कोल ब्लॉक्स ही अभी तक इफैक्टिव हुए हैं और जिनमें ऑपरेशन शुरू हुआ है। बाकी कोल ब्लॉक्स में अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। जब हमने बारीकी के साथ इसका अध्ययन किया तो इसमें सबसे बड़े दो हर्डल्स सामने आए। एक हर्डल लैंड एक्विज़िशन का है और दूसरा पर्यावरण मंत्रालय की क्लीयरेंस का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लैवल पर भी होता है और सैंट्रल गवर्नमेंट के लैवल पर भी होता है। इस संबंध में हमने पर्यावरण मंत्री जी से बात की और मुझे खुशी है कि तीन-तीन, चार-चार और पांच-पांच साल से लटके हुए मामलों में हमारे पर्यावरण मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया कि हर कीमत पर हम पर्यावरण की क्लीयरेंस छ: महीने के अंदर-अंदर दे देंगे। पिछले दो महीने के अंदर

हमने जिन-जिन राज्यों में दौरा किया है, इस दौरान मैं पश्चिमी बंगाल गया, झारखंड भी गया तब वहां के मुख्य मंत्री और वहां के गवर्नर से हमने बात की ..(व्यवधान)

सुश्री मैबल रिबैलो: वहां मुख्य मंत्री हैं ही नहीं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैंने कहा कि वहां के मुख्य मंत्री और वहां के गवर्नर से हमने बात की। मैंने सही रिप्लाई किया है। उनसे हमने कहा कि पर्यावरण के संबंध में आप जल्दी क्लीयरेंस देने की प्रक्रिया शुरू करिए। अगर तीन-तीन, चार-चार और पांच-पांच साल तक पर्यावरण की क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी, तो जिस मक़सद से हमने कोल ब्लॉक्स ऐलॉट किए हैं, हमारा वह मक़सद पूरा नहीं होगा। इसी तरीके से हमने स्टेट गवर्नमेंट्स से यह बात भी की कि लैंड एक्विज़िशन की कार्यवाही को पूरे तरीके से अंजाम देने का कार्य स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है, उसमें यूनियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। हमें दोनों राज्यों से इस चीज़ का आश्वासन मिला है। जहां-जहां और कोल माइनिंग होती है, पार्लियामेंट के सैशन के बाद मैं उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स से भी मिलूंगा और उनसे भी यही अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण क्लीयरेंस और लैंड ऐक्विज़िशन की कार्यवाही को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे कि हमने जो ब्लॉक्स एलॉट किए हैं, उनका उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा सके और डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप है, उसे हम पूरा कर सकें।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Prasanta Chatterjee.

MS. MABEL REBELLO: My second supplementary, Sir?

MR. CHAIRMAN: You are only associated with the question. You did not ask it. (Interruptions) I am afraid, if the main questioner is absent that right cannot be delegated to someone else. (Interruptions) No.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, illegal mining in the abandoned coalmines is rampant in Jharkhand and at many other places. There is a great nexus between the coal mafia and others. And, this problem is very much linked to the number of accidents that take place there and the resultant loss of lives, apart from other issues. So, my question is

this. How does the Government take care of this serious problem? Who will provide funds for filling up of abandoned coalmines? It is very necessary to fill up the abandoned coalmines.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, हमारी कोल कंपनीज़ के द्वारा एबान्डंड कोल माइन्स को फिल करने की प्रक्रिया बराबर की जाती है और उनकी फिलिंग कर दी जाती है, लेकिन जैसा हमारे माननीय सदस्य ने पूछा है, उनकी जिज्ञासा है और यह बात सही भी है कि हमारे कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में इल्लीगल कोल माइनिंग तेजी के साथ जारी है। हमने मुख्य मंत्री जी के साथ और गवर्नर साहब के साथ जो मीटिंग की थी, उसमें भी इस बिंदु को उठाया था कि जब तक इल्लीगल माइनिंग नहीं रुकेगी, तब तक उचित कदम नहीं उठाए जा सकते हैं और कोल का प्रोडक्शन वास्तव में नहीं बढ़ सकता है।

1m/psv पर जारी

-SCH/PSV-PB/1M/11.55

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल(क्रमागत): हमें वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और झारखंड के गवर्नर साहब ने यह आश्वस्त किया था कि हम इल्लिगल माइनिंग को रोकने के लिए कदम उठाएँगे। झारखंड के गवर्नर साहब ने यह कहा था कि हम इंडस्ट्रियल सेक्योरिटी फोर्स ...(व्यवधान)... मैंने झारखंड का गवर्नर कहा। झारखंड के गवर्नर और पश्चिमी बंगाल के चीफ मिनिस्टर कहा।

सर, हमें झारखंड के गवर्नर साहब ने यह आश्वस्त किया कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर हम स्टेट की इंडस्ट्रियल सेक्योरिटी फोर्स भी बना रहे हैं और वह करीब-करीब ट्रेंड होकर तैयार हो गई है, हम इल्लिगल माइनिंग को रोकने के लिए उस फोर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने हमसे यह भी कहा कि आपको अगर आवश्यकता हो तो आप सी0आई0एस0एफ0 की तर्ज पर हमारी स्टेट की सेक्योरिटी फोर्स भी हमसे लीजिए और इल्लिगल माइनिंग को रोकने के लिए जो भी प्रभावकारी कदम आप उठाएँगे, उसमें हम आपको पूरा सहयोग देंगे। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर से भी मेरी बात हुई। सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ पर हमारी माइनिंग हो रही है, वहाँ की सुरक्षा करना तो

हमारी सी0आई0एस0एफ0 का दायित्व है, जिसके लिए हमने सी0आई0एस0एफ0 को सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रखा है, लेकिन कोल फील्ड्स बहुत लम्बी-चौड़ी है। कानून-व्यवस्था और पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। ...(व्यवधान)... मैडम, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हम अभी इल्लिगल माइनिंग की बात कर रहे हैं। कोल फील्ड्स बहुत बड़ी होती है। जहाँ माइनिंग हो रही है वहाँ तो है ही, इसके अलावा उससे दस गुनी ज्यादा कोल फील्ड्स होती है, जहाँ पर कोल उपलब्ध होता है। इल्लिगल माइनिंग को रोकने के लिए जब तक स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सहयोग केन्द्र सरकार को नहीं प्राप्त होगा तब तक हम इल्लिगल माइनिंग को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। ...(व्यवधान)... येचुरी जी, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हमारे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी से बहुत ही कोऑपरेटिव रुख अपनाया और उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकारियों को यह निर्देश करेंगे कि सी0आई0एस0एफ0 के साथ पूरे तरीके से तालमेल रखें, कोल कम्पनीज़ के साथ की पूरे तरीके से तालमेल रखें और इल्लिगल माइनिंग को रोकने के लिए जो भी कड़े-से-कड़े कदम उठाए जा सकें, वे उठाए जाएँ। आपको ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...(Interruptions)... Please, we are running out of time. Don't interrupt.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: फिलिंग की जहाँ तक बात है, तो जैसे ही माइनिंग का काम खत्म होता है वैसे ही वहाँ पर फिलिंग कर दी जाती है। लेकिन, फिलिंग किए गए क्षेत्रों में अगर इल्लिगल माइनिंग करने वाले फिर से इल्लिगल माइनिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वह एक प्रॉब्लम हम लोगों के सामने खड़ी होती है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही हम स्टेट्स का दौरा कर रहे हैं और हम आपको, माननीय सदस्य को, आश्वस्त करते हैं, कि हरेक क्वार्टरली हम चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे और मिल कर उनसे इस मामले में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम थेफ्ट भी रोकने में कामयाब होंगे और इल्लिगल माइनिंग पर भी कहीं-न-कहीं कुछ-न-कुछ परसेंट अंकुश लगाने में जरूर कामयाब होंगे।

श्री नतुजी हालाजी ठाकोर: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह सवाल करना चाहता हूँ कि गुजरात सरकार को जो कोयला दिया जा रहा है वह पूर्वी क्षेत्र से दिया जा रहा है। वह दूरी 16 सौ किलोमीटर की है। उसके हिसाब से परिवहन-क्षेत्र का जो खर्च है, वह बढ़ जाता है। गुजरात सरकार की बार-बार रजुआत के बावजूद भी हमें पश्चिमी क्षेत्रों से कोयला नहीं दिया जा रहा है। इसके क्या कारण हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, गुजरात सरकार हो या कोई दूसरी सरकार हो, जिस कोल कम्पनी से जिसको कोयला अलॉट हुआ है, उन कोल कम्पनीज़ से उस स्टेट को कोयला जा रहा है। गुजरात एक कोस्टल स्टेट है। गुजरात में बहुत-से लोग कोल का इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। आपने जिस मामले में हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उस सम्बन्ध में हमें गुजरात सरकार का भी एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। हम यह देख रहे हैं कि जिन कम्पनीज़ से गुजरात गवर्नमेंट कोयला मांग रही है, क्या उनके पास इतना कोयला है कि वह गुजरात सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके? अगर ऐसा होगा तो हम उनकी मांगों पर जरूर विचार करेंगे।

श्री आर0सी0 सिंह: सर, जिन कम्पनीज़ को आउटसोर्सिंग करने के लिए सरकार अधिकार दे रही है, वे क्या माइनिंग रूल्स, रेगुलेशंस और वर्कमैन का जो वेज़-एग्रीमेंट होता है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के पास है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, जिनको भी आउटसोर्सिंग की अनुमति दी जाती है, उनको सरकार अपनी शर्त पर, अपने कानून पर और अपने विधान की शर्तों पर ही आउटसोर्सिंग की अनुमति दे सकती है। अगर वे सरकार के किसी भी कानून का वॉयलेशन करती हुई पाई जाएँगी, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

श्री आर0सी0 सिंह: सर, बैक फिलिंग एक भी कम्पनी नहीं कर रही है।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN IN THE CHAIR)

PAPERS LAID ON THE TABLE

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:

(a) Two Hundred and Twenty-fourth Report of the Law Commission of India on Amendment of Section 2 of the Divorce Act, 1869 enabling Non-domiciled Estranged Christian Wives to seek Divorce.

Two Hundred and Twenty-fifth Report of the Law Commission of India on Amendment of Sections 7, 7A and 7B of Industrial Disputes Act, 1947 making Advocates Eligible to man Labour Courts and Industrial Tribunals.

श्री कांतिलाल भूरिया : उपसभापति महोदय, मैं आप की अनुमति से वर्ष 2009-10 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के संबंध में परिणामी बजट की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखता हूं।

SHRI SUBODH KANT SAHAY: Sir, I lay on the Table

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (4) of Section 619A of the Companies Act, 1956:

(a) First Annual Report and Accounts of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM), New Delhi, for the year 2007-08, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

II. Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (I) above.

III. A copy (in English and Hindi) of the Outcome Budget for the year 2009-10 in respect of the Ministry of Food Processing Industries.

SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL: Sir, I lay on the Table, a copy

each (in English and Hindi) of the following Papers:

(i) Annual Report of the National Statistical Commission (NSC), New Delhi, for the year 2007-08.

(ii) Action Taken Report on the recommendations of the National Statistical Commission (NSC), New Delhi, for the year 2007-08.

(iii) Outcome Budget for the year 2009-10 in respect of the Ministry of Coal.

(iv) Outcome Budget for the year 2009-10 in respect of the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Minority Affairs) and the National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) Limited, for the year 2009-10.

SHRIMATI KRISHNA TIRATH: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:

(i)(a) Annual Report and Accounts of the Central Social Welfare Board, New Delhi, for the year 2006-07, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(ii)(a) Annual Report and Accounts of the Rashtriya Mahila Kosh, New Delhi, for the year 2007-08, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I lay on the Table, under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Environment and Forests:

(1) G.S.R. 158 (E), dated the 9th March, 2009, publishing the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2009.

(2) G.S.R. 512 (E), dated the 9th July, 2009, publishing the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2009.

SHRI JITIN PRASADA: Sir, I lay on the Table

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Petroleum and Natural Gas under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:

(1) G.S.R. 381 (E), dated the 3rd June, 2009, publishing the Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobile) Amendment Order, 2009.

(2) G.S.R. 382 (E), dated the 3rd June, 2009, publishing the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Amendment Order, 2009.

II. A copy (in English and Hindi) of the Outcome Budget for the year 2009-10 in respect of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Sir, to lay on the Table

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Power, under Section 179 of Electricity Act, 2003:

(1) No.L-7/143/158/2008-CERC, dated the 24th February, 2009, publishing the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading license and other related matters) Regulations, 2009.

(2) No.L-1(1)/2009-CERC, dated the 30th March, 2009, publishing the Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled Inter-change charges and related matters) Regulations, 2009.

(3) No.L-1(2)/2009-CERC, dated the 30th March, 2009, publishing the Indian Electricity Grid Code (Amendment) Regulations, 2009.

(4) No.L-7/105/121/2007-CERC, dated the 29th May, 2009, publishing the Open Access in Inter-State Transmission

(Amendment) Regulations, 2009.

(5) No.L-7/143/158/2008-CERC, dated the 2nd June, 2009, publishing the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading license and other related matters) (Amendment) Regulations, 2009.

(6) No.L-1(5)/2009-CERC, dated the 2nd June, 2009, publishing the Conduct of Business (Amendment) Regulations, 2009.

(7) No.L-7/145(160)/2008-CERC, dated the 17th June, 2009, publishing Corrigendum regarding the CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009.

(8) No.L-7/145(160)/2008-CERC, dated the 17th June, 2009, publishing Addendum regarding the CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009.

II. A copy (in English and Hindi) of the Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Power) and the Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, for the year 2009-10.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:

(1) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Information and Broadcasting) and the Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL), for the year 2009-10.
(2) Outcome Budget for the year 2009-10 in respect of the Ministry of Information and Broadcasting.

(Ends)

STATEMENT RE. IMPLEMENTATION OF THIRTY-NINTH REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): Sir, I make a statement regarding status of implementation of recommendations contained in the Thirty-ninth Report of the Department-related

Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment.

(Ends)

MATTERS RAISED WITH PERMISSION OF CHAIR

FLOODS IN GUJARAT

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात): उपसभापति महोदय, इस बार आधे देश में सूखा पड़ा है। हमारे गुजरात में बहुत बारिश हुई है। वैसे जुलाई के महीने में सिर्फ 15-20 परसेंट बारिश होती थी, लेकिन इस बार पिछले 10 दिनों में 60 परसेंट से ज्यादा मानसून की बारिश हमारे यहां हो गयी है।

उपसभापति महोदय, भेरावड़ और हमारे जितने सागर तट हैं, उन में 50 फीसदी से ज्यादा, यानी कि 1000 मिली मीटर से ज्यादा एक साथ, एक दिन में बारिश हो गयी है। महोदय, मुंबई में तूफानी मौजा की जो बैठ है, गुजरात के नौसारी, सूरत में उस का भी बहुत प्रकोप हो गया है। इस कारण गुजरात में बहुत भारी नुकसान हुआ है। महोदय, हमारे यहां जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मांगरौर, वैरावर, मारिया, सूत्रापाड़ा में एक दिन में 8-8 सौ मिली मीटर बारिश हुई है। इस सब से हमारे यहां बहुत भारी नुकसान हुआ है। महोदय, वहां घरों के अंदर 5-5 फुट पानी भर गया है, रास्ते सब टूट गए हैं जिस कारण करीबन 22 गांवों से संपर्क टूट गया था। वहां मिलिट्री को भी भेजना पड़ा। इस सब के कारण हमारे यहां बहुत नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण पोरबंदर और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में dewatering की भी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है।

(1ओ/डीएस पर क्रमशः)

-hms/ds-hk/12.05/1o

श्री विजय कुमार रूपाणी (क्रमागत): वहाँ एनडीआरएफ की दो टीमें भेजी गई थी। भारतीय वायुबल और भारतीय सेना को भी वहाँ राहत के काम के लिए भेजा गया था। जामनगर जिले के लालपुर में 17 जुलाई को करीबन एक दिन में 800 मिली मीटर से ज्यादा बारिश हुई है। वहाँ 20 इंच से ज्यादा बारिश एक साथ हो गई है, जिससे वहाँ के 50 से ज्यादा गांव अतिवृष्टि के कारण ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुँच गये हैं। इससे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान हुआ है। वहाँ एसआरपी और एनडीआरएफ के विशेष दलों को भी भेजा गया है। वहाँ से करीबन 7,800 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित किया गया है। वहाँ पर करीब दो हेलिकॉप्टर्स द्वारा 70,000 से भी ज्यादा फूड पैकेट्स के वितरण का कार्य राज्य

सरकार को करना पड़ा है। इस तरह इस natural calamity की दृष्टि से वहाँ पर इसकी तुरंत घोषणा होनी चाहिए। वहाँ गुजरात सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलिफ मिले, ऐसी हमारी डिमांड है ...(समय की घंटी)... मैं इस सभा में आप सब का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ।

(समाप्त)

श्री उपसभापतिः इससे बहुत-सारे लोग एसोसिएट कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र): सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान): सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करती हूँ।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी (उत्तराखंड): सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश): सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

श्री परिमल नथवानी (झारखंड): सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

(समाप्त)

METRO RAIL SERVICES FROM TOLLYGANGE TO GARIA IN KOLKATA

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (WEST BENGAL): Mr. Deputy Chairman, Sir, it is learnt that the hon. Minister for Railways has decided to inaugurate the Kolkata Metro Railway Services' extension portion between Tollygange to Garia on 23rd August, 2009. The announcement to this effect has already been made by the Minister herself without consulting the Government of West Bengal, which is sharing 33 per cent of the total cost of this project. It is a fact that the people of Kolkota are demanding the extension of the metro services from Tollygange to Garia and the completion of project is a very welcome step. The Government of West Bengal extended its full cooperation to fulfil the demand of people and up to 31st March spent so far Rs.221.46 crore for

this project. Even the Government of West Bengal shares the 33 per cent of the escalated cost of this project. Initially, the project cost was Rs.696 crore, then subsequently revised to Rs.907.69 crore and then further revised to Rs.1032.76 crore. The 33 per cent cost is borne by the State Government. The State Government also arranged to rehabilitate 500 families which were residing on the banks of Tolly Nallah. Not only that, the State Government allotted land for construction of metro rail services without any cost. But the hon. Minister for Railways simply forgot all these facts before declaring her inaugural programme as a pooja gift. Even in hurry, she appeared to be forgotten that the stretch of metro railway is yet to be cleared by the Commissioner of Railway Safety which is a mandatory one. Sir, we request the Government to intervene and not to repeat such things.

(Ends)

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, I associate with the Special Mention made by the hon. Member.

RESERVATION FOR GUJJARS OF RAJASTHAN

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान): उपसभापति महोदय, मैं एक अत्यंत संवेदनशील इश्यू की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर एक बार फिर बड़ी गंभीर और विस्फोटक स्थिति बन गई है। मैं यहाँ उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, जो देश और प्रदेश को पिछली बार इसके कारण क्षति हुई थी। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, उसे यह जानकारी होगी कि पिछली बार विधान सभा में सर्वसम्मति से, जिसमें रूलिंग पार्टी भी थी और अपोजिशन भी था, वह अपोजिशन जो कि आज सरकार में बैठा है, यह तय किया गया था कि गुर्जरों को 5 प्रतिशत और सामान्य श्रेणी के अति निर्धन लोगों को

14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। इस पर लम्बी बहस हुई। इस मुद्दे पर विपक्ष की भी पूरी सहमति थी। महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उस समय विधि विभाग से भी इसकी सहमति ली गई थी और जो संशोधित प्रस्ताव आया, वह विधान सभा में सर्वसम्मति से पास किया गया।

(1पी/एकेए पर क्रमश:)

KSK/AKA/12.10/1P

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (क्रमागत) : किन्तु आज ऐसा लगता है कि सर्वसम्मत प्रस्ताव पास होने के बाद भी उस पर राजनीति की जा रही है। वे लोग जो उस वक्त विपक्ष में थे, आज सरकार में बैठे हैं, उस समय कहा करते थे कि सामान्य रूप से इसका हल हो जाएगा। मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर तत्कालीन सरकार ने एक आयोग का गठन किया था - श्री जसराज चोपड़ा आयोग, और उसने भी यह कहा था कि निश्चित रूप से इस बात को ..(व्यवधान)..

डा0 प्रभा ठाकुर : सर, मैं कहना चाहती हूं कि पांच साल ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, don't intervene in between.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरा समय ले रही हैं। ..(व्यवधान)..

डा0 प्रभा ठाकुर : पांच साल रहे, इन्होंने क्या किया ..(व्यवधान).. इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : प्रभा ठाकुर जी, आप क्यों खड़ी हो रही हैं। ..(व्यवधान).. बैठिए। ..(व्यवधान)..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वे मेरा समय ले रही हैं। ..(व्यवधान)..

डा0 प्रभा ठाकुर : इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : प्रभा ठाकुर जी, आप सदन का टाइम ..(व्यवधान).. आपको जवाब देने के लिए नहीं कहा गया है। ..(व्यवधान).. आप मैम्बर को बोलने दीजिए। ..(व्यवधान)..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया, विपक्ष की सहमति हो गई ..(व्यवधान).. आज जब स्थिति ऐसी पैदा हो

गई है तो कहा जा रहा है कि इस पर दस्तखत नहीं किए जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि महामहिम इस पर दस्तखत क्यों नहीं कर रहे हैं, वे जाने या भगवान जाने। किन्तु, मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले पर केन्द्र सरकार इंटरवीन करे, तुरंत उस पर निर्णय ले, अगर निर्णय नहीं लेगी तो इसका परिणाम क्या होगा, यह हमने पिछली बार देखा है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विस्फोटक स्थिति न बने। अभी कल ही मीटिंग हुई थी, पड़ाव डाल रखा है, अगले 24 घंटे के लिए उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और उसके कारण क्या परिणाम होंगे, इसके बारे में केन्द्र सरकार जानकारी करके इसको ठीक करे।

(समाप्त)

श्री कलराज मिश्र : *

श्री रामदास अग्रवाल : *

डा0 प्रभा ठाकुर : *

श्री कलराज मिश्र : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record...(Interruptions). आप बैठ जाइए। ..(व्यवधान).. मिश्र जी, आप बैठ जाइए। आप जवाब मत दीजिए। ..(व्यवधान)..

डा0 प्रभा ठाकुर : *

श्री रामदास अग्रवाल : *

श्री उपसभापति : आप बैठिए। ..(व्यवधान).. आप बैठिए। There is no provision for this. Please, sit down. आप बैठिए रामदास अग्रवाल जी। Now, Shri Bharatkumar Raut.

---

* Not recorded.

SHRI BHARATKUMAR RAUT (MAHARASHTRA): Mr. Deputy Chairman, Sir, I wish to bring to the notice of the House some grievances which are being faced by the employees of Air India and Indian Airlines. I am associated with this as Bharatiya Kamgar Sena Union. Sir, on the last 22nd, yet another circular came from the Executive Director (Finance) of Air India stating that the CMD had directed that the PLI norms for the company were to be reviewed and parameters needed to be revised, hence deferring the PLI of Air India employees for the month of July, 2009 up to 20th August. Sir, just last week, the Civil Aviation Minister mentioned on the floor of this House that there would not be any retrenchment, no lay-off, and he also promised that the salary, that had already been deferred, would be paid. Within three days, another circular comes stating that PLI will be deferred further. What is PLI? It is Productivity Linked Incentive given to the employees. Technically, hon. Civil Aviation Minister was right. Wages and salaries have been paid. But, the PLI has been deferred. Now, what is the importance of the PLI? Let me tell you that the PLI of ground staff is almost 50 per cent of their gross emoluments, and 65 per cent of the gross emoluments in case of flying staff. If a person, who is in ground staff, earns Rs.1000, then, Rs.500 come from PLI. It means, you have deferred 50 per cent of their salary; and 65 per cent in case of cabin crew. Have we become so pauper that we cannot even pay the salaries of the employees? If PLI constitutes this much portion of the total emoluments, that actually means deferring their salaries and wages. So,

employees have every right to earn their PLI on the stipulated time and date. For India Airlines, the flying allowance is actually meal allowance. If some flying staff goes to London, or other stations, how will he eat and from where?

(continued by 1q/gsp)

GSP-NB/12.15/1Q

SHRI BHARATKUMAR RAUT (CONTD.): Sir, this is the important thing. (Time-bell) Sir, I want you to use your good offices and pressurise the Ministry to see that the salaries are paid on time and not deferred.

(Ends)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR (MAHARASHTRA): Sir, I associate myself with the views of hon. Member on this important issue.

RE. PATNA WOMEN MOLESTED AND STRIPPED OFF

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : उपसभापति जी, दो-तीन दिन पहले पटना में अचानक एक ऐसी घटना घटी, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद आज तक इस तरह की शर्मनाक घटना बिहार में नहीं हुई है, बिहार की राजधानी में नहीं हुई है। एक औरत को होटल से निकाला गया, सरेआम सैकड़ों आदमियों के बीच में, वहां पर ट्रैफिक पुलिस थी, कुछ दूरी पर पुलिस स्टेशन भी था, टी.वी. सीरियल वाले शायद पहले से खड़े थे, उन लोगों के बीच में एक औरत के कपड़े खोले गए, उसको नंगा किया गया .... (व्यवधान) यह भयानक है। मुझे कभी-कभी लगता है कि यह राज्य सरकार, अपने आपको सुशासन की सरकार कहती है?

महोदय, 15 सालों तक बिहार में हमारी सरकार चली, * सरकार चली, तो इन लोगों ने कहा कि जंगल राज है। जब यह घटना घटी तो * ने कहा कि ..... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप किसी का नाम मत लीजिए ... (व्यवधान) आपको तो रूल्स मालूम हैं ..... (व्यवधान) शिवानन्द जी, बैठिए, नाम निकाल दिया गया है ... (व्यवधान)

---

* Not Recorded

श्री राजनीति प्रसाद : महोदय, सरकार के मंत्री ने कहा कि * कृष्ण भगवान की तरह उस औरत की रक्षा करने के लिए ..... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप नाम मत लीजिए, आपको जो बोलना है, केवल वह बोलिए, अच्छा विषय है, आप बोलिए ..... (व्यवधान)

श्री राजनीति प्रसाद : जब यह घटना घटी, तो पुलिस ने कहा कि उस महिला का चरित्र अच्छा नहीं था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हम लोग इस घटना के बारे में endorse करते हैं? यह इतनी शर्मनाक घटना है। हम लोगों की सरकार को जंगल राज कहा गया, लेकिन आज बिहार की स्थिति इतनी गंभीर है कि वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थापना नहीं है। वहां पर हर दिन मर्डर हो रहा है, वहां पर हर दिन रेप हो रहा है और यह जो घटना घटी है, यह इतनी शर्मनाक है कि ..... (व्यवधान)

श्री शिवानन्द तिवारी : ये क्या बोल रहे हैं? ये सदन में असत्य बोल रहे हैं ..... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र मोहन : ये सदन में असत्य बोल रहे हैं .... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : ठीक है, वे उनके विचार हैं, आपके नहीं, आप बैठिए ..... (व्यवधान)

श्री शिवानन्द तिवारी : ये साबित करें कि पटना में हर दिन मर्डर हो रहा है, हर दिन रेप हो रहा है ..... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : अब उनको क्या बोलें, हम बोल सकते हैं क्या? आप बैठिए ..... (व्यवधान) आप भी बोलते हैं, वे भी बोलते हैं ..... (व्यवधान) आप बैठिए ..... (व्यवधान) देखिए, वे आपकी बात नहीं करेंगे, अपनी बात करेंगे, आप लोग बैठ जाइए ..... (व्यवधान) रूडी जी, आप बैठिए ..... (व्यवधान) उनको परमिट किया गया है, वे जो बोलना चाहते हैं, If it is not unparliamentary, he has every right to say that. (Interruptions) आप बैठिए ..... (व्यवधान)

श्री अली अनवर अंसारी : उपसभापति जी, हमारी सरकार ने इसकी निंदा की है ..... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : अंसारी साहब, बैठिए ..... (व्यवधान) देखिए, यह सही नहीं है, Nothing will go on record. (Interruptions)

श्री अली अनवर अंसारी : *

---

* Not Recorded

श्री उपसभापति : विप्लव जी, यह क्या बात है? आपसे किसने कहा है बोलने के लिए ..... (व्यवधान) मैंने उनको परमिट किया है, इसलिए वे बोल रहे हैं ..... (व्यवधान) Viplove ji, what is this? It is not the way. (Interruptions)

श्री अली अनवर अंसारी : * (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record. (Interruptions)

श्री अली अनवर अंसारी : *

श्री उपसभापति : देखिए, वे आपकी बात करेंगे क्या?

श्री शिवानन्द तिवारी : * ... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र मोहन : * .... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : अगर ये असत्य बोल रहे हैं, तो आप उनके ऊपर प्रिविलेज मोशन लाइए, अगर वे असत्य बोल रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दीजिए .... (व्यवधान)

1R/SC पर क्रमश:

SK-SC/1R/12.20

श्री उपसभापति (क्रमागत) : आप क्या बात कर रहे हैं? इनको बोलने के लिए अलाऊ किया गया है, इन्हें बोलने दीजिए। ..(व्यवधान)..

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: * (Interruption)

श्री उपसभापति : रूल्स को नहीं समझ सकते..(व्यवधान).. एक मिनट..(व्यवधान).. जयन्ती जी, आप बैठिए। आप खत्म कीजिए। ..(व्यवधान)..

श्री शिवानन्द तिवारी : *

श्री उपसभापति : यह क्या बात है? ..(व्यवधान)..

---

* Not Recorded

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: *

श्री उपसभापति : * शब्द को निकाल दीजिए। ..(व्यवधान).. जयन्ती जी, आप बैठिए। ..(व्यवधान).. शिवानन्द जी, एक मैंबर को जब बुलाया गया है, उसका ज़ीरो ऑवर एडमिट हुआ है, जीरो ऑवर चेयरमैन साहब देखने के बाद एडमिट करते हैं।..(व्यवधान).. हो सकता है कि मैंबर आपके ..(व्यवधान).. सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। वे जो बोलना चाहते हैं, अगर वह अनपार्लियामेंटरी है तो उसे हम कार्यवाही से निकाल देंगे, वरना उनको अपने विचार रखने दीजिए, इसमें आपको क्या आपत्ति है?..(व्यवधान)..राजनीति प्रसाद जी, अब आप खत्म कीजिए।..(व्यवधान)..

श्री राजनीति प्रसाद : मैं एक और बात कहना चाहता हूं।..(व्यवधान)..

श्री विनय कटियार : *

श्री उपसभापति : कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, मैंबर का सवाल है। आप बैठिए। ..(व्यवधान).. Nothing will go on record. (Interruptions) आप बैठिए।..(व्यवधान).. आप बैठिए न।..(व्यवधान)..

श्री राजनीति प्रसाद : अंत में मैं कहना चाहता हूं..(व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप जो कह रहे हैं, Nothing will go on record. I have not identified you. (Interruptions) आप बैठिए।..(व्यवधान)..

श्री राजनीति प्रसाद : सर, अंत में मैं कहना चाहता हूं..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. This is over. (Interruptions) Your three minutes are over. We will now take up the Motion for Suspension of Rule 272. (Interruptions) Motion for Suspension of Rule 272. (Interruptions) Mr. Minister, (Interruptions)

---

* Not recorded

श्री राजनीति प्रसाद : सर, मुझे बोलने नहीं दिया गया तो तीन मिनट कैसे हो गए?..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : बस, अब हो गया।..(व्यवधान)..

प्रो0 अलका क्षत्रिय : *

श्री उपसभापति : आपको नोटिस देना चाहिए था। क्या आपने यहां नोटिस दिया है? आपने नोटिस नहीं दिया है। यह क्या बात है? ..(व्यवधान).. आप बैठिए। आप बैठिए न। ..(व्यवधान)..

SOME HON. MEMBERS: Sir, we all associate ourselves. (Interruptions)

श्रीमती वृंदा कारत : सर, जो वहां पर हुआ ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आप असोसिएट कीजिए।..(व्यवधान)..

SHRIMATI BRINDA KARAT: * (Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no (Interruptions) By intervening you can't take (Interruptions). Without notice you can't speak. (Interruptions)

SHRI SITARAM YECHURY: We associate ourselves, Sir. (Interruptions)

SHRI D. RAJA: We associate ourselves, Sir. (Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Mr. Rajniti Prasad has said. (Interruptions)

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, we have only associated. (Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you can associate.

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) : सर, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्ध करती हूं

प्रो0 अलका क्षत्रिय (गुजरात) : सर, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

सुश्री सुशीला तिरिया (उड़ीसा) : सर, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

---

* Not recorded

डा0 प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : सर, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री राजनीति प्रसाद : सर..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajniti, I have called the Minister. (Interruptions) It is over now. I have said that it is over. (Interruptions)

श्री राजनीति प्रसाद : सर, हमें तीन मिनट बोलने नहीं दिया गया। (समाप्त)

श्री उपसभापति : आपके तीन मिनट हो गए हैं। मंत्री जी, आप बोलिए। Nothing will go on record.

MOTION FOR SUSPENSION OF RULE 272

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, I beg to move:

"That the Rule 272 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States in its application to consideration of the Demands for Grants of the related Ministries/Departments for 2009-10 by Department-related Standing Committees be suspended".

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I want to say one thing. We will accept your request for suspending the Rule for this year only if the Government gives an assurance that for the rest of its tenure it is not going to come with the similar suspension motion.

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Absolutely, Sir. This is not the intention of the Government to do away with the examination of demands by the Standing Committees. Only because this year we could not constitute the Standing Committees in time, we are seeking their permission for this.

The question was put and the motion was adopted.

(Ends)

(Followed by 1S-ysr)

DISCUSSION ON WORKING OF MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (CONTD.)

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI A. RAJA): Sir, I express my gratitude to the hon. Members who participated in the discussion on the working of the Ministry of Communications and Information Technology. The deliberations were fruitful.

Discussions in Parliament reveal not only certain facts but also policies, objective and goal of the Government in a particular sector. I recall the words of Justice V.R. Krishna Iyer. He said, "Parliament is a grand inquest of the nation, the great auditor and the Ombudsman of the Executive, the final arbitrator, policy monitor, and destiny designer of the country." I do believe that the discussions held here must coincide with the definition that has been offered by Justice V.R. Krishna Iyer. As a Minister I do agree with what has been observed in the same Parliament by our mentor, Dr. C.N. Annadurai, when he was a Member of this House. He said, 'the highest is not above the law, the humblest is not beneath the law.' With this in mind, I want to convince those who made arguments, of course, some allegations, before Parliament on the working of the Ministry.

Sir, when I was entrusted with the task of running this Ministry in May, 2007, I wanted to learn quickly and rapidly the developments that were taking place. I do feel that I have done something in the Ministry which subject me to clarifications and criticism that have been offered, including those made by the Leader of the Opposition.

I am very glad that the Leader of Opposition for whom I have high regards as one of the top legal brains in the country is sitting here, not just for taking part in the discussion. I am also happy because my senior colleague, Mr. Arun Shourie, is present here whose presence is inter alia connected with the arguments going to be put forward by me while convincing other Members of Parliament.

Sir, I think that some of the arguments that have been made by the Members of Parliament were free from party prejudices and predilection and some were prejudices of political entity. I want to weigh both without any prejudice in my mind.

Sir, I had three Departments when I assumed this charge and it is still with me. Let me deal with them one by one. Since May, 2007, when I took charge as the Minister of Communications and Information Technology, some of the major achievements of this Government by making proactive policy decision are these.

As the hon. Members are aware, the Department of Posts is the largest postal network in the world which provides postal facilities within the reach of every citizen in the country at affordable prices. These include delivery of letters, e-mail, small savings, money remittances, provisions of life insurance and other core functions.

Sir, second to the Railways, the Postal Department is one of the biggest Department in the world having huge infrastructure. Due to rapid development in other areas of information technology and other private courier services, the profit which was earned by the Postal Department has dwindled. It is quite natural that to withstand in a competitive environment, something afresh must be done. The

Government has anticipated new developments in this sector and it is well aware that the Postal Department cannot be used exclusively for commercial interests.

(Contd. By VKK/1T)

-YSR/VKK-VNK/1t/12.30

SHRI A. RAJA (CONTD.): Of course, it has its own commitment towards the people, those who are living at the lowest ebb of the society in the remote areas. The service of the Postal Department cannot be ignored and even it cannot be equated with the other private courier services. Of course, through the non-Plan expenditure, every year, more than Rs.1000 crores or even more, is being compensated by the Government of India through the Finance Ministry as supplementary because the postal network has to be kept alive. But, that does not mean that the Government is totally inactive or inert in having a re-look at the working style of the Postal Department. For the first time, we took the decision. We have 1,55,000 post offices in the country. These 1,55,000 post offices, if at all the business is coming down, cannot be closed in one stance. So, we wanted to switch over the business to some other areas; we wanted to treat the local post offices in the remote areas as the outlet of the nationalised banks; we wanted to sell the gold coins with quality on a par with the Indian standards; and, we wanted to have other services. We are even talking with private banks like ICICI Bank. If they want to avail of this infrastructure, revenue can be accrued for this Department and we can come out of the deficiency which is being incurred now, up to the tune of Rs.1000 crore and more. Sir, one of the major initiatives that has been...(Interruptions)...

श्री उपसभापति : देखिए, आप इन्हें बोलने दीजिए ..(व्यवधान)..

SHRI A. RAJA: No, no. It will be used. Some incentives will be given.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Madhu, please don't interrupt the Minister in between. It derails his thoughts.

SHRI A. RAJA: Sir, we can start savings bank account on behalf of the State Bank of India. We will operate the savings account. Out of which, some percentage can be given as commission. That's all. We are not going to privatise the Postal Department. How the deficiency, the loss incurred by the Department, can be managed is the point. That's all. Even we are not intending giving profits through privatisation. It is not the question of privatisation at all. The point is, how the infrastructure available in every nook and corner of the country can be used when the other technology is coming into the Department. We have to withstand the competitive environment. That is the motive of the Government.

Sir, the major initiatives have taken place in the Department. In the Eleventh Plan, we announced that major post offices in the country will be computerised. Accordingly, we have allotted Rs.2700 crores which has been earmarked for IT induction in the postal operations. Out of this fund, so far 9684 post offices have already been computerised till March 2009. About 1274 post offices have been linked through a web area network and a National Data Centre has been set up for this purpose.

Sir, I am continuing in the same Ministry from the last Government. The last Government announced an innovative scheme called Project AERO. In a competitive world, not only the content of the article is important but the visibility of the article must also be impressive. So, in all the post offices running in the rural areas at the

taluka level, block level or in the old buildings, we wanted to give them a business model and give them a good visibility with the new equipment and IT instruments. So, we launched Project AERO. Last year, we modernised 500 post offices across the country selectively in all the States without any discrepancy by spending more than Rs.80 crores. This year, we have earmarked another 500 post offices which will be taken up under this project.

Sir, coming to the queries raised by the hon. Members, great concern was expressed that new post offices are not at all being opened. As I stated, every year, the Department is incurring a loss of Rs.1000 crores or more. But, the Government has committed that within the Eleventh Plan, we are going to start 3000 post offices across the country for which papers have been mooted and these are being discussed in the Finance Ministry.

(Contd. by RSS/1u)

RSS/1U/12.35

SHRI A. RAJA (CONTD.): I do hope the commitment that has been made by the Finance Ministry for the Eleventh Five Year Plan that 3000 post offices are going to be opened in the country soon will be fulfilled. For constraint of time, I am not able to go by each and every name of the Member. Of course, some of the Members spoke about the recruitment in the Postal Department. Deep concern was expressed with regard to the extra departmental workers working in the rural areas and it was suggested that they should be regularised and new post offices should be opened. When the post offices are opened, those persons

who are living in the locality, they must be appointed. These are the queries which have been raised by the Members of Parliament.

Mr. Jha raised the question that no recruitment has taken place in the Department of Posts since 1984. Sir, it is known to all that the recruitment of the new services is being governed by the Department of Personnel and Training. Only 5 per cent of the vacancies can be filled up according to the Department of Personnel and Training. Without prior approval of the Department of Personnel and Training and without the prior approval of the Ministry of Finance, we cannot fill up all the vacancies which are available. However, efforts are being made, and we are in touch with the Finance Ministry. The Postal Department should not be compared with other departments. This service is very essentially needed for the people and the rule that has been made generally for other departments, we cannot take shelter under that rule in the Department of Posts. The discussion is on, and I do hope that the exemption will be obtained from the Ministry of Finance, and in the course of time, we will appoint all the postmen against all the vacancies wherever it is essential.

He has raised another question that compassionate appointment cases must be considered. It is universally accepted in the country that only 5 per cent of vacancies can be filled up on compassionate ground. Even if direct recruitment is there, we cannot defeat the direct recruitment simply because some people are waiting on the basis of compassionate ground The recruitment in the other areas cannot be curtailed according to the guidelines issued by the Department of Personnel and Training, and we will ensure that the 5 per cent that has

been earmarked on compassionate ground will be strictly followed, the seniority will be strictly followed. I can give this assurance to you. Similarly, he raised another question that the Assured Career Progression scheme has not been applied to the Department of Posts. The Assured Career Progression scheme has been implemented, consequent upon the recommendations of the Fifth Pay Commission, modified Assured Career Progression scheme, as recommended by the Sixth Pay Commission, is also under implementation. GDS are holding civil posts, but they have not analysed this aspect. This was the allegation made by him. GDS, the extra-departmental postmen, those who are working in the villages, according to our census, are spending only five hours or four hours or three hours; legal impediments are there. When a person is working for five hours or four hours per day, he cannot be regularised. We appointed one-man Committee under the chairmanship of Mr. Natarajan Murthy, who had worked in the Postal Department earlier, to find out how their betterment can be ensured. He made a recommendation that some incentives must be given to the persons who are working in the extra departmental post offices. It is seriously considered by the Finance Ministry, and I hope, the Finance Ministry will clear this proposal. Thereafter, we will give some emoluments and some incentives will be attracted by these people.

Sir, Mr. Nayak spoke about his constituency...(Interruptions)

SHRI SITARAM YECHURY: The EDP people work for eight hours!

SHRI A. RAJA: Maybe, they work for 8 hours. Sometimes, they work for 4 hours and 3 hours. The Supreme Court judgment is there which says that the regularisation cannot be done unless they are being recruited as the full-time workers. That is the judgment.

SHRI SITARAM YECHURY: But they have been working for many years.

SHRI A. RAJA: I am fully concerned with them. I will be the first person to support the cause of the GDS. At the same time, this subject is not exclusively within my domain. For this purpose, I have to interact with the Ministry of Finance.

PROF. P.J. KURIEN: Increase their emoluments.

SHRI SITARAM YECHURY: That can be done.

SHRI A. RAJA: For that purpose, I appointed one-man Committee under the chairmanship of Natarajan Murthy, who was an officer in the Postal Department. He knew all the nitty-gritty of the department. He recommended some emoluments and incentives. It is being actively considered by my Ministry and the Finance Ministry. I will support the cause of the GDS.

SHRI SITARAM YECHURY: If the Finance Ministry is creating a problem, please elicit our support. We are with you. Please get their emoluments increased.

SHRI A. RAJA: We will do it.

PROF. P.J. KURIEN: This is a very genuine problem. You prevail upon the Finance Ministry and get it done.

(CONTD. BY 1W)

SHRI A. RAJA: Sir, some of the suggestions have been made by Mr. Hassan for strengthening the rural postal network. The suggestions are well taken. Similarly, I have already submitted to the House that the density of the post office is not commensurate with the norm of opening a post office. That has been highlighted by Mr. Chandan Mitra. I do agree with the concern expressed by him so far as the post office is concerned. Of course, these norms are being implemented wherever it is possible. Because of the financial crunch we are not able to open post offices wherever the people need them. It has been referred to the Finance Ministry. They accepted that in the Eleventh Five Year Plan, 3,000 post offices will be, definitely, opened. Before the end of the Eleventh Five Year Plan, I assure you, the post offices will be established, wherever required, as per the recommendations made by the Finance Ministry once it is cleared.

Similarly, Mr. Sudarsana Natichappan, said that the bonus on NSS it has been reduced. You may be aware, Sir, that the rate of interest, whoever be the person, whichever be the Department, so far as Government Departments are concerned, on the deposits, on the Government money, will be decided by the Finance Ministry. So, the Finance Ministry fixed the rate of interest on deposits, under the Small Savings Schemes, as five per cent. We are pursuing the Finance Ministry to consider, if possible, giving them, in the course of time, more incentives. Similarly, the commission of small saving agents has been reduced. These are also being governed by the Ministry of Finance.

On the revival of postal services in the rural areas, Mr. Ranjit Prasad has also spoken. Most of the Members are deeply concerned

about the establishment of rural post offices. I assure this House that the persons who are....(Interruptions)...

SHRI RAJNITI PRASAD: Sir, my name is not 'Ranjit Prasad! It is 'Rajniti Prasad'!

PROF. P.J. KURIEN: His name is Rajniti Prasad!

SHRI A. RAJA: I am sorry, Sir.

SHRI SITARAM YECHURY: 'Rajniti' means 'politics'; 'Political Prasad'!

SHRI A. RAJA: Sir, even some of the names I will leave. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He never wants to use 'rajniti'!

SHRI A. RAJA: So far as the Postal Department is concerned, this does not mean that the Member's voice is being marginalised or is going to be ignored by the Ministry, or by the Minister. I will take a complete microscopic study done, by going through all the speeches which have been delivered here. So far as the Postal Department is concerned, we launched the 'Project Arrow'; we computerised the ten thousand post offices for which a huge amount has been given by this Government.

Now, I come to the Department of I.T. Sir, in the Department of Information Technology, the credit of this Government stands on the new schemes which have been announced. Broadly, I can speak about the two schemes. In the Eleventh Five Year Plan, the National E-governance Programme that has been announced by the Prime Minister of India, in the last Government, and it is being implemented by spending more than Rs.6,000 crores. In the first phase, we are going to create State Data Centres in every State Headquarter. Then, the District Headquarter will be connected; then, the Block Centres will be

connected by e-governance, the complete e-governance, and, ultimately, across the country, one lakh Common Service Centres are going to be opened. Out of these, 40,000 Centres have already been opened across the country. The motto of the National E-governance Programme is that the administration should be paperless. We want that within a couple of years, up to the taluka level, the paperless Government must be ensured. After that, we want to create these Common Service Centres where the land records can be obtained by the villagers, those who are living in the village itself. Rail tickets and air tickets, all family details, and even the other departmental needs of the people will be put in the Common Service Centres so that a person need not have to travel to the District Headquarters or the Taluka Headquarters. Whatever be the need of the documents, including the revenue records, family cards, railway ticket booking and all other bookings will be held within the Common Service Centres. Then, it will be connected with the block level, the State level and the district level. The motto of the Government is to ensure that within two years, in the district level, there should be a paperless Government. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Madhu, let him reply.

SHRI A. RAJA: Yes, that is our motto. We are attending to that.

(Contd. by TMV/1X)

SHRI A. RAJA (CONTD.): Of course, we are lagging behind a little bit in the National E-governance Programme because it is not exclusively and directly implemented by the Central Government. We are depending upon the State Governments. The persons who are going to run the Common Service Centres with private participation have to be identified and it is being taken up with the State Governments through due process. Some of the State Governments are pro-active. There is a little bit of delay on the part of some of the State Governments -- I am not accusing any State Government -- because of want of personnel and other things necessary to establish the Common Service Centres.

Sir, another important scheme, that is, the semi-conductor policy, has been announced by the Department of Information Technology. India is largely dependent on foreign countries, so far as manufacturing hardwares is concerned. Of course, even in the case of a small handset of mobile, most of the parts are being imported from abroad, assembled here and then sold here. So, the Government wants to have its own electronic hardware manufacturing hubs. We have announced the Special Economic Zones. As Members are aware, in the case of Special Economic Zones, 20 per cent incentives, tax holidays, etc., have already been announced. Notwithstanding the SEZs which have been given income-tax concessions and other incentives, the Government wants an exclusive policy for semi-conductor and it was announced by the previous Government. The previous Government received proposals worth Rs.1,56,000 crores. This Government, as soon as I took over charge of this Ministry again, within a week, cleared and gave in-

principle clearance to 8-10 projects worth more than Rs.75,000 crores. These projects are going to be implemented very soon. So, this is a major policy decision that has been taken by the Government in the Department of Information Technology.

Sir, while I mention the major achievements, I must also go through the Members' needs also. Of course, I was surprised when Mr.Jha mentioned it. I am thankful to Mr. Jha. He mooted a very important point. I do feel very sorry that our own Annual Report was not put on the website. This has been highlighted by him. I thank him for the reference that he had made. I had immediately asked the officers to put the Annual Report on the website. With regard to the other areas, he pointed out that the allocation by the DoIT for masses, gender, SC, ST and manpower development had remained unchanged over the years. I checked it. Yes, it is true that the allocation for Plan schemes under this domain is unchanged. The reason behind this is that we have other Plan schemes for manpower development and the Department has many other institutions like C-DoT, DOEACC, etc., which run manpower development programmes. We are going to align with the State Governments on how manpower development programmes can be implemented at the State level since we do feel handicapped in implementing this directly. We know that the students who get degrees from the universities and other institutions are not able to get jobs because once they leave the institutions there occurs a gap in the case of the rural people, the SCs, the STs and the OBCs and they are not able to update their skills. As they are not able to update their skills, they are not able to get jobs. This is a very important point.

We will take up these issues with the State Governments in course of time.

Similarly, Mr. Hassan has mentioned about the national knowledge network and e-grandhalaya. Of course, it is unusual to ask this question. When the Budget is increased, Members must be happy. Here, it is otherwise. Last year, it was Rs.100 crores. This year, it is Rs.600 crores. He asks: Why was there a hike without any justification? The hike is because the Technical Advisory Committee has recommended the design document of NKM. The high level committee approved the proposal of the TAC for a new project which costs Rs.5,990 crores.

(Contd. by 1Y/VK)

VK/1Y/12.50

SHRI A. RAJA (CONTD): In order to complete the new project in a phased manner, Rs. 600 crores have been given by the Government. There is another important area. Of course, I missed to mention the achievements of the Government. We are deeply concerned about cyber crimes. We amended the Information Technology Act, 2000 keeping in mind its greater significance. The number of cyber crimes was going up. Of course, our personnel, including the police officers were not competent to deal with and investigate cyber crimes. They were not aware under what provision of the law those people had to be booked. There were some grey areas in the Information Technology Act, 2000 and there were some issues which were not at all addressed during those days. Then there was no mention of many other crimes.

As soon as the crimes are identified, those crimes must be investigated and accordingly corresponding provisions should necessarily be made. The Government felt the necessity. Accordingly, in our last tenure, we amended the law. We strengthened the Indian Computer Emergency Response Team in the Department of Information Technology and together with industry associations like the Confederation of Indian Industry, NASSCOM, Data Security Council of India and software players like Microsoft has developed a website exclusively for this purpose. Various types of materials like posters, handouts, stickers, calendars, guidelines and animation videos on creating awareness aimed at school children, teachers and parents have been designed and hosted on the websites. Important issues have been addressed. This question was put by Shri Shantaram Laxman Naik. He also raised one important point that software should be developed in all regional languages. That is very important. He stated that software must be developed in all regional languages, without any discrimination. We are glad to announce that already 16 CDs have been made available in Hindi, Tamil, Telugu, Marathi, Urdu, Punjabi, Oriya, Kannada, Assamese, Malayalam, Gujarati, Sanskrit, Bodo, Dogri, Maithili and Nepali. Software CDs are available in all these 16 languages. In the case of balance six official languages, it will be done by September, 2009. So far as Bangla is concerned, of course, it is ready for launch. Sir, these are all the major achievements.

Some of the hon. Members expressed their concern about the loss in business of C-DoT. Of course, C-DoT was started way back in the year 1996 to design, develop and transfer the technology of digital switching system to indigenous manufacturing. It was started with good

intentions but after liberalisation and globalisation, there is no preference for indigenous developed technologies. Therefore, C-DoT has suffered a lot because of globalisation and liberalisation. We wanted C-DoT to enter into the business of technology consultancy and attention on products of national importance. We wanted it to work as application service provider to international companies. I do hope that some business will be brought back to the basket of C-DoT and it will be revived in due course of time.

Now I come to telecom. Concerns were expressed with regard to the performance of BSNL and MTNL. Sir, due to constraint of time, I would like to summarise it broadly. Two allegations have been made against the performance of BSNL and MTNL. One is, its market share is coming down and the subscriber base is not picking up.

(Contd. by 1Z)

RG/12.55/1Z

SHRI A. RAJA (contd.): Sir, before going into the details of business modalities of the BSNL and MTNL, I must submit that the BSNL and the MTNL are pubic sector units, and PSUs have their own impediments and handicaps on some of the areas. We cannot tell ourselves that the BSNL and the MTNL should be treated on a par with Airtel, Vodafone, that is, exclusively for commercial uses. The BSNL is the only operator which is serving 5,65,000 villages in the country, through its mobile operations, or, at least, the Village Panchayats with its telephone network. This is the only PSU connecting all the people, including those living in the hilly areas and in the rural areas. And, we have our own difficulties on certain issues, which I can partially share with the

Members of Parliament. For example, when we talk of expansion of the BSNL, it is a corporate affair. Whether it is for value added services, or, for other small works, we have to float tenders; we have to consult the Ministry of Finance; and we have to go to the Management Board. It is only after we go through all these processes, that we can install any capacity building. Now, Sir, when my predecessor was there in office, a tender was floated for covering more than 23 million villages, which would fulfil the anticipated growth and anticipated needs for the next five years. Unfortunately, a company, which had participated in the tender, went to the Court. Accordingly, at the time of issuance of Advance Purchase Order, the company could obtain a stay on the entire tendering process for more than one-and-a-half years. What I want to impress upon the House is that if for one-and-a-half years, the expansion work is totally halted, for reasons best known to the person, who filed the case, and the Court of law, how can we expand the system in the rural areas and in the urban areas where the competitive atmosphere is too high and sensitive? Similarly, in other areas also, we have the security reasons. Some Chinese companies are selling their products to the private operators. In critical areas, -- my predecessor is here, and he must be aware of these things -- especially, in the border areas, we have the advice from the Home Ministry not to go in for Chinese companies." In the absence of Chinese companies, we have to bargain and negotiate exclusively with one or two companies, which might have quoted higher rates as compared to the prices which the private operators would have quoted in other tenders. So, the negotiation process will take a long time. We cannot interfere directly

with the PSUs. So, all these days, the administrative delays, inevitable delays, causes some sort of jeopardised approach on the part of the BSNL and the MTNL. However, some hon. Members, who spoke the other day, said that when the BSNL was earning a revenue of Rs.1000-1500 crores in the past, its revenue has now shrunk to Rs.100 crores. I do not know from where this figure of Rs.100 crores has been obtained. In spite of being in a competitive environment, we earn around Rs.500 crores and more. I do admit that there are some difficulties. These difficulties and the legal points must be appraised very carefully. It is not a question of direct equation with other companies. At the same time, the services being rendered by the BSNL and the MTNL cannot be ignored.

Sir, I do not want to go into issues like how many telephone connections are there, what our share is, etc. Now, on the telecom side, I want to deal with an area where...(Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Before you go to the other point, several hon. Members have raised about congestion and call drop. People get irritated when they have to call between 11 o' clock and 1 o' clock.

SHRI A. RAJA: I will come to that. This problem is not universal. Please bear with me. This may be there in some areas in Delhi, or, in the thickly populated areas...(Interruptions)

(Continued by 2A)

SHRI A. RAJA (CONTD.): Sir, I will come to you. (Interruptions) Broadly, I share with you the difficulties being faced by BSNL. But, in spite of that, believe me, the quality of service is being maintained and monitored by the TRAI. According to the TRAI report, the quality of service of BSNL and MTNL is not universally bad. They have maintained the quality of service. But there are various reasons; I had a specific reason.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Universally, not; nationally, yes.

SHRI A. RAJA: Universally means not in the sense of... (Interruptions) It is not common. I am saying it in that sense.

एक माननीय सदस्य: ऐज़ कंज्यूमर, हम लोगों को लग रहा है कि सर्विस ही खराब है।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Could you yield for a second?

SHRI A. RAJA: Sure.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: To help ourselves; not for criticism.

SHRI A. RAJA: If, at all,, it is criticism, I will take it in a positive sense, Sir, not in the negative sense.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Deputy Chairman, Sir, three or four years back I had raised this issue in the House. The then Minister had told us that there weren't enough towers and so the congestion was increasing. Just now you said that it was in cities like Delhi. No. In our own city of Chennai, you try to call between 11 o'clock to one on any day any time from the BSNL, you will find congestion, you will find call-drop; sometimes you get really irritated. I agree with you that BSNL has been doing a good job. There is no second opinion on that. I don't think anybody here has a second opinion on that. (Interruptions)

Yes, we all support you on BSNL. At the same time, you know we are consumers; if the facility is not good, you switch over to other people, like you shift from Air India to other airlines. So, keep this in mind as to how to remove that congestion, how to ensure that call-drop isn't there. The third point is, they don't say 'congestion'; they say, "यह नम्बर गलत है"! These are the points. Just take note of them.

SHRI A. RAJA: Sir, in Delhi, we are also facing another peculiar problem. The Department of Urban Development and the Department of Home do not permit us to install more towers in certain areas due to various reasons.

SHRI T. K. RANGARAJAN: Are private operators being permitted to do that?

SHRI A. RAJA: No. They are also not being permitted. These guidelines have been issued recently. For example, in South Avenue, we cannot erect any tower.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, there will be no lunch hour today. This is just for information.

SHRI A. RAJA: Of course, Sir, this point is well-taken. At the same time, I would like to say that in some areas in Bihar, we have come to know, towers are being manned by BSNL men. We checked a specific case and we found that the tower was being operated with the help of a diesel engine since there was no electricity. As we know, some of the areas in Bihar do not have electricity. Some times, due to the scarcity of diesel, these towers do not get activated, for small durations of half-an-hour or an hour. A person who travels across the tower will find out that when the tower is not activated, there are no signals. Those

signals are not there, not because of BSNL's fault, bust just because the diesel has not been put there at the right time. This happens in certain areas. However, the concern of the... (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN) IN THE CHAIR

I just wanted to share this incident with the House. There are other reasons too. The main reason is that we have not been able to expand our capacity because of court cases. (Interruptions) Yes, I am admitting that it is because of court cases. I must share this with the House; earlier all BTS and other instruments were procured through a centralised tender, one tender for the whole country. For the first time, I have divided it into four or five zones. Now, zonal-wise tenders will take place. If a person has a grievance in one zone in regard to a tender, let it be there but the whole process should not come to a halt. So, we invited another tender for 93 million telephone connections which will meet the requirements for another four or five years. Negotiations are going on. The APO is going to be issued shortly. Once these 93 million connections are installed, I hope there will be no problem in the BSNL commercial activity for the next four years and the telephone connections will be upgraded.

SHRI T. K. RANGARAJAN: But why is it happening in Chennai? There is so much of congestion!

SHRI A. RAJA: Sir, if there is anything specific, please let me know. I will look into it personally.

(Contd. by 2b/tdb)

TDB/2B/1.05

SHRI A. RAJA (CONTD.): Sir, now I turn to spectrum.

DR. V. MAITREYAN: Sir, before that, there is the issue of proposed privatisation of the BSNL. He has not touched that. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Let him finish.

DR. V. MAITREYAN: I am raising this issue because he has completed his reply on BSNL. ...(Interruptions)...

SHRI A. RAJA: Of course, he is right. The BSNL is a Mini-Ratna Company. We wanted to have a new corporate style. I have already assured whether it is going to be privatised to the trade-union leaders who met me in this regard. I assured them that it is not the question of disinvestment or privatisation of the BSNL. At the same time, some sort of new modalities can be inculcated in the business model of the BSNL, if it is possible, we can go for a 10 per cent or 20 per cent IPO. The preferential shares can be given to those workers who are working in the BSNL. It was only a healthy decision which was held there. I met directly the leaders of trade-unions to find out some ways so that the BSNL can be upgraded with commercial values without losing its own entity as a PSU. So, discussions were held there. That is all. Nothing has happened. No...(Interruptions)...

DR. V. MAITREYAN: Mr. Minister, your Secretary has gone on record mentioning that 10 per cent disinvestment has been listed. Only the timeframe should be decided by the Finance Ministry.

SHRI A. RAJA: Where is the question of 'has been listed'? By saying, 'has been listed', you are referring to 'past perfect'. 'Has been' is 'past perfect'. ...(Interruptions)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Then, why is your Secretary saying it in the Press? ...(Interruptions)... It has been reported in the Press that 10 per cent disinvestment...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): This cannot be allowed. ...(Interruptions)... Brindaji, please take your seat. ...(Interruptions)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: How is it that he is allowed to make such statements in the Press? ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN: Now, listen; you address the Chair.

SHRI A. RAJA: I am standing before you in Parliament. The Minister is saying it in Parliament; why are you afraid of the Secretaries and all?...(Interruptions)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Can you stop him from doing such things? ...(Interruptions)... He has given that statement in the Press.

SHRI A. RAJA: I will take care of it. ...(Interruptions)... That was the categorical assurance given by me to the trade-union leaders. Your own CPM trade-union leader met me. ...(Interruptions)... He met me.

SHRIMATI BRINDA KARAT: That is why, Sir, we are surprised. Following that, the Secretary says 10 per cent disinvestment in the BSNL. ...(Interruptions)... Who has given the Secretary the authority to speak? ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN: See, no cross-discussion should be there between you both. ...(Interruptions)...

DR. V. MAITREYAN: Sir, we are seeking certain clarifications. ...(Interruptions)... We are seeking some important clarifications.

SHRI A. RAJA: Sir, I have already clarified it. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Clarifications can be sought after the Minister's reply. ...(Interruptions)... I will allow you. ...(Interruptions)... I will allow you also, after the Minister's reply. ...(Interruptions)... Now, Mr. Minister.

SHRI A. RAJA: Sir, now I come to spectrum. Sir, no Minister in the Telecom Ministry has met such a new era which invited more criticism in the past. Why? Is it something different with Raja?

THE VICE-CHAIRMAN: You only address the Chair. ...(Interruptions)... No comments, please. I will allow you after the Minister's reply.

SHRI A. RAJA: Sir, I want to recall my memory, when Shri Rajeev Chandrasekhar wrote a letter, in the year 2007, when the spectrum issues were discussed in the Ministry, if my memory is correct, I quote, "I will be the first person to think over the auction of spectrum provided the laws and rules framed in this Ministry and approved by the Cabinet permit." Am I correct? ...(Interruptions)... What is meant by spectrum? I apprised the media, I apprised those people in the industry who are interested to know as to what is meant by 1G, what is meant by 2G and what is meant by 3G. Even the All India Radio is being operated with a spectrum; even police wireless is being operated with a spectrum. All the State Governments are paying money as 'spectrum charge' for the police wireless, 1G. See, spectrum cannot be equated in one slot, 1G, 2G, 3G. Sir, 3G spectrum cannot be compared with 2G, 2G spectrum cannot be compared with 1G.

Sir, let me now brief about the chronological events that happened in the Ministry so far as the spectrum process is concerned. When the mobile telephone came to India, the Government of India used to give

licence and the spectrum on auction process. The existing operators who got some of the areas out of the auction route, they got licence and spectrum way back in 1993.

(Contd. by 2c-kgg)

kgg/2c/1.10

SHRI A. RAJA (contd.): They failed miserably on two scores, which are very essential and important on two scores, which are very essential and important; one is, they were not able to give the real tele-density in the country as expected by the Government; the second is, the auction price was not paid by the operators on the ground that the business was not viable. So, the business is not viable, tele-density was not picking up; hence, a Group of Ministers was formed. Then, they came out with National Telecom Policy, 1999. What we achieved today, irrespective of the political entity; we worked as a Council of Ministers in the Government headed by Shri Atal Behari Vajpateeji where the National Telecom Policy, 1999 came into existence.

Sir, not for political reasons, I must record in the House that because of the National Telecom Policy, 1999, the telecommunication revolution is happening now. There is no hesitation or reservation for me to accept it. The National Telecom Policy, 1999 was approved by the Cabinet. As I told the other day, when the Leader of the Opposition was also in the Cabinet, National Telecom Policy, 1999 says, 'The auction route failed on two scores---tele-density and revenue for the Government; both have miserably failed.' The National Telecom Policy, 1999 was devised for two mottos; one is the affordable cost, the second is enhancing the tele-density. So, they decided to bring a new guidelines

by virtue of National Telecom Policy, 1999. National Telecom Policy, 1999 clearly says, 'The number of operators will be decided every three years.' How many operators are going to be in the country would be decided by TRAI. Then, the spectrum charges would be announced periodically by the TRAI. So, the National Telecom Policy, 1999 permitted the industry to go in for the revenue route from the auction route; how much revenue to be collected will be decided by the TRAI. How many operators are going to be permitted? It is with the TRAI. The TRAI, needless to say, is a statutory body.

Sir, that is why I shared with Parliament, no Minister has come across with such contacts because of TRAI recommendations. When I entered into the office, the TRAI recommendations came, of course, three-four months prior, to me. It was ready on my table where the TRAI said, 'There should not be any capping.' In this country, Sir, only for a few operators, four or five, 2G spectrum is available. Somebody wanted to name me, during the formation of the Government, that Raja is Spectrum King! Yes, with all my sincerity, I would like to admit that I am the spectrum king, the first in the country, in the Department; because, I only disclosed how much spectrum was available, and I am the first Minister to put that on the website.

Sir, only 100 MW of space is available in 2G. When I assumed charge, 300 million telephone connections were there. 300 million telephone connections were being operated only within 30 to 35 MW. Of course, the remaining 40 MW was with the Defence. The remaining 20 MW, invariably, was available in the country. When there is a scarce resource available on your hand, you are permitting only 4 operators.

What is the formula devised by them? We will wait to reach a certain subscriber base; as soon as we reach X-million connections, the spectrum is in my armpit, I will give it to you as soon as you reach the subscriber base. Till then, there should be no competition! It is like having only 4 shops in a village. It is saying like, 'Biscuits are there, you eat these biscuits, then you come back to the same shop and do not go to a new shop'! There is no provision for a new shop. Is it a competition? It is not my idea, mooted by Raja in the Ministry.

Fortunately or unfortunately, I got the TRAI recommendations for healthy competition. All right. I went through all the records. Of course, I am a district court lawyer. The arguments that have been advanced by the Supreme Court lawyer, I am having high regards; I admit, he is one of the top legal brains in the country. What I wanted to impress upon the House is, as a Minister in the Ministry, I paid my due legal diligence in the issuance of licences, in the issuance of spectrum. What does the law say? All the technologies earlier--one is the cellular mobile, one is the landline; new technologies may come. So, there are several licences before National Telecom Policy, 1999. All these licences were unified into one and it was called in the nomenclature of 'unified access licence'.

(Contd. by kls/2d)

KLS/2D-1.15

SHRI A. RAJA (CONTD): So, Unified Access Licence says that you can get one licence, you can operate any technology- you go for landline, you go for CDMA, and you can go to GSM. If at all tomorrow a new technology may come, of course, 3G is going to come, in spite of that there will be no specific or exclusive another licence for the 3G. So, the

licence is one. We gave it. As he put it, it was derived by TRAI that 1650 will be the licence fee as prescribed by the TRAI. Sir, the argument seems to be very legitimate and plausible when we are hearing the argument. The argument advanced by the Leader of the Opposition and others is that the price which was quoted in 2001, 1650 for the licence fee, is being kept alive by Raja or by the DoT, still even after the escalation in the other areas. Yes, nobody can say this cloth, which I got in 2001, cannot be available on the same price in 2009. Where is the gap? ...(Interruptions)... I am coming. Similarly, about spectrum, the question is very legitimate. ...(Interruptions)... I am coming. ...(Interruptions)... That is why I am only answering the questions. ...(Interruptions)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Which is the shop, you please tell us. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Be patient, he is trying to explain. ...(Interruptions)...

SHRI A. RAJA: I am giving the answer. ...(Interruptions)... Sir, all the arguments are here but about one thing I do not attribute motives on the part of the Leader of the Opposition, of course, he levelled his argument on one side. I can't say that wilfully or wantonly he omitted the other side of the argument. What has been recommended by TRAI is this. Let me quote some of the provisions of the TRAI. Sir, NTP, 1999, para 3.1.1 says, 'the entry of more operators in service area shall be based on the recommendation of the TRAI who will review this as required and not later than every two years.' So, according to these 'two years', the recommendation came to me. 'The cellular mobile

operators would be required to pay one time entry fee, the basis of determining the entry fee and the basis for the selection of the additional operators would be recommended by TRAI. Apart from the one time entry fee, the operators would also be required to pay licence fee based on the revenue share.' This is NTP, 1999. How much revenue share you have to collect will be decided by TRAI. What TRAI recommended was that the entry fee of fourth cellular operator- of course, rightly observed by the Leader of the Opposition - would be what was the amount which was auctioned last time, it will be the entry fee. It further says that the entry fee must be nominal. Since you are going for the revenue share, the TRAI is empowered to give new figures periodically how revenue should be collected more and more. Sir, as I put it earlier, by way of licence fee and spectrum fee having migrated from the auction to the revenue route, we assessed yesterday, it is Rs.68,000 crores putting together which we collected. People are telling that Rs.1 lakh crore is the loss. In 2007-08 alone, the Government earned revenue out of spectrum charge and the licence charge to the tune of Rs.23,000 crores. How? It is based on the subscriber base. I can say in the layman sense that one call, which is being terminated by an operator, will have three paise or four paise, for example, to the Government. When the subscriber base goes up, the revenue will also go up. ...(Interruptions)... SHRIMATI BRINDA KARAT: You have increased revenue from this nobody is denying that. You have got Rs.68,000 crores but how does that idea explain or justify the fact that you still kept the cost too low for eight years? So you have not answered your question about the shop. ..(Interruptions)...

SHRI A. RAJA: That is why the revenue is being accrued out of this 1650 every years.

SHRIMATI BRINDA KARAT: This is what is going to happen. The subscriber base in any case is going to increase. ...(Interruptions)...

SHRI A. RAJA: 'Subscriber' means, it is inter alia connected. ...(Interruptions)... We are collecting money not only on subscriber base but on licence also. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, are you yielding to these queries? ...(Interruptions)...

(Followed by 2E)

SSS/2E/1.20

SHRI A. RAJA: I will come to you. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Minister, continue please. Mr. Minister, are you yielding to the queries? (Interruptions)

DR. CHANDAN MITRA: What...(Interruptions)...

SHRI A. RAJA: I will come to you. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Are you yielding to these queries in between? Tell me.

DR. V. MAITREYAN: The recommendation of Rs. 1650 was given to TRAI in 2001. Four months after you took charge you said that the file came to you on TRAI recommendation. That was in 2001. You didn't get a fresh recommendation on TRAI as on 2007.

SHRI A. RAJA: TRAI recommended, 'Go for new operators'. That is my submission. When TRAI gave the recommendation to go for new operators, they did not revise the entry fee on the reason that we are accruing the revenue on the basis of licence fee also.

SHRIMATI BRINDA KARAT: The point that I am making is...

SHRI A. RAJA: I think, I am not able to...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, you finish your speech and then, you give them time. There cannot be an interaction like this. You finish your speech. I will give you time. (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If he is willing to yield and it is a healthy debate and we are eliciting information, that way, it is good for the House.

THE VICE-CHAIRMAN: If the Minister is yielding, I have no objection.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Then why is the Chair curtailing it?

THE VICE-CHAIRMAN: No, I don't want two to three people putting questions at the same time. If one Member is asking and the Minister is yielding, I have no problem. But I have a problem if two to three people put questions at the same time.

SHRI ARUN SHOURIE (UTTAR PRADESH): Mr. Raja has been kind enough to yield and because he has taken my name twice, I may just ask on this very point. Mr. Raja is taking shelter under the TRAI recommendations. So, my questions are specific to that. One is, would he please be prepared to disclose to the House the letters which the Chairman of TRAI wrote to the Secretary, Telecom protesting against the Telecom Department's assertion and the present Minister's assertions that TRAI recommendations were being followed. I know for a fact that these communications were sent and I would be very eager to learn from the Minister whether those documents would be brought to the

House in support or in contradiction of what the Minister has just stated that...

MR. A. RAJA: I will send it to you.

SHRI ARUN SHOURIE: One second. The second point, Sir, what my friend Arun Jaitley and Doctor has asked about is about 2001 recommendation being invoked in 2007 is not being answered. But what Mrs. Karat was just now really asking was not about the subscriber. We all understand about revenue share, but, whether in valuing the spectrum that subscriber base will really affect the current value of that assessment or not. When that has increased 20 fold, then, naturally spectrum becomes exactly the scarce resource which you are mentioning much more valuable and therefore, the question arises whether the Minister would be prepared to take the House into confidence in regard to the companies allocations to which really created the problem which was Unitech and Swan. Finally, you just now said about the Chinese company and the security advice that was given. You just now said that actually then the decision was not along the border but the objection which the intelligence agency raised on record -- whether it is a fact or not, I know it to be a fact but you will confirm it -- Intelligence agencies in writing and in the meetings raised the objection that there has been many, many recorded instances in which software and hardware and such things were implanted in them which could be triggered to paralyse networks and therefore, such equipments should not be allowed to a particular country. I don't know whether this was just after all something which is disrupted in Nasik.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): No, don't go for a speech.

SHRI ARUN SHOURIE: No, one question Sir. He just now said border. If it is disrupted in Nasik where we have an air base, in Pune, in Jamnagar. It is as effective as in Pithoragarh on the border of China. So, how did the Department then disregard the Intelligence agency which is a question which he has to clarify.

(Followed by NBR/2F)

-SSS/NBR-NB/2F/1.25.

SHRI A. RAJA: Sir, I wanted to put it like this. The question is: Whether the building can be given on outright sale, or, keep the deposit at lower level and get high monthly rent. That is the question. Sir, 2001 recommendations say to keep the entry fee nominal. When 2004 recommendations came to go in for new operators, it has suggested revenue-sharing in which percentage has to be high i.e., from 2 per cent to 3 per or from 3 per cent to 4 per cent. They did not give any recommendation. To enhance the entry fee, since it has been categorically observed in 2001, we let the entry fee be nominal. The building can be given at lower deposit and you enhance the rent year-after-year. That is the recommendation of the TRAI. So, we went for that and, accordingly, we are collecting money.

But, as I already shared with you, what is the tele-density today? In 2004, when the NTP, 1999, came into existence, it was hardly 7 per cent or 8 per cent. Now, it is 39 per cent. I or this Government cannot take exclusive credit for this. Sir, it is because of NTP, 1999, because

of shifting to revenue-sharing mechanism, the tele-density has gone up to 39 per cent today.

Sir, another question came about the spectrum. Licence is this. As I have already said, nobody knows that the spectrum is being given free of cost. Sir, 6.2 spectrum, initially, coupled with the agreement, was signed by the licence-holder. I got the licence by paying Rs. 1650 crores. The moment I got the licence, I am having my own contractual right over 6.2 -- initially, it was 4.4 then it could go up to 6.2 -- free of cost. There is a perception in the minds of the people and in the media. Of course, my friend, Mr. Maitreyan, has referred the CVC. Sir, all these aspects, whether it is the common man, whether it is the media, or, with due respect to the hon. Members, Members or the officials in the Government, have been kept in their mind. He referred the C.V.C. Of course, I discussed with the Chief Correspondent and the Chief Editor of two leading national dailies to apprise what is meant by spectrum, what is meant by licence, how the Ministry is working, how the Department is working on the spectrum issue. It took me three hours. Thereafter, they have convinced. It does not mean that I call all the newspapers which have been motivated with some political perception and convince them.

DR. V. MAITREYAN: But, Sir, the C.V.C. was not convinced.

SHRI A. RAJA: Who said that it is not convinced?

DR. V. MAITREYAN: Sir, the C.V.C. itself has gone on record saying that it is not convinced.

SHRI A. RAJA: You are not the Chief of the C.V.C...(Interruptions)...You are not the C.V.C...(Interruptions)...No, no. I am not yielding ...(Interruptions)...

DR. V. MAITREYAN: Sir, the C.V.C. has gone on record saying that it is not convinced with the clarifications given by the department.

SHRI A. RAJA: It is quite natural...(Interruptions)...The former Ministers are here...(Interruptions)...

DR. CHANDAN MITRA: Sir, the High Court has said that the spectrum is sold as cinema tickets.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, you continue.

SHRI A. RAJA: Sir, the hon. Leader of the Opposition has made a point...(Interruptions)...Let them be patient. I do not know. A P.I.L. is pending before the court. I am having the details. I know the dates. I know how the P.I.L. is proceeding. I also know that the P.I.L. is going to be heard by September 15. I do not know whether remark made by the Members in the Parliament is either ratio decidendi or arbiter dictum of the judgment. I do not think either any judgment or order has been passed. But, he spoke something. That is why, in legal language, I am submitting to the hon. Leader of the Opposition that I do not know the remarks that have been passed, as alleged by him. Also, I do not know whether the remark made here is either ratio decidendi or arbiter dictum of judgment. I cannot comment upon that. But, I can come to the C.V.C.

THE VICE-CHAIRMAN: You make your point. Don't worry about that side.

SHRI A. RAJA: I am coming to the C.V.C. Sir, the C.V.C. is a part and parcel of the Government. He is not competent to say whether the C.V.C. is satisfied. He is not the C.V.C. But, I just wanted to mention on thing. The question itself starts like this. It does not mean that I am convincing the C.V.C. from here. I am speaking before Parliament. The question says, 'there are media reports that some licences are selling their equity at high values.' All these speculations, all these questions, whether they are from the C.V.C. or it is from the common man on the streets or whether it is from lawyer or Parliament, with due respect to all, I would say are being emanated from the media. That is why I wanted to convince the House and not worried about what is happening or what has appeared in the media reports.

(CONTD. BY USY "2g")

-NBR-USY/2G/1.30

SHRI A. RAJA (CONTD.): Sir, now, I come to the first-come-first-serve policy. Everybody is thinking that the first-come-first-serve policy is a new policy that has been introduced by me. As I submitted before the House, before the Unified Access Service Licence (UASL) was given, there were several licences -- for mobile, for landline, for other basic services, like, the internet, etc., etc. So, before the NTP 1999, there were multiple types of licences. All these licences were unified into one by the NDA Government. The vision was correct. Of course, tomorrow, there may be some new technology. All technologies must be brought under one umbrella. So, they put it and the NTP 1999 came into existence. Then, as per the UASL, the first licence was during the NDA Government. After that, if my dates are correct, the licences were

issued when Shri Arun Shourie was the Minister. It was, in fact, decided by the then hon. Minister, Shri Arun Shourie, in 2003 that all new UASL would be issued on first-come-first-serve basis and the spectrum will also be allotted in the same manner, subject to the availability. But the precipitation in the mind is that the first-come-first-serve policy has been designed and invented by me. I am not shifting the burden on some other Minister. I am just mentioning the chronological events. The first-come-first-serve policy for the spectrum licence was observed on the file by my predecessor, Shri Arun Shourie; and, thereafter, by Mr. Dayanidhi Maran. Why? I have discussed it with the Law Ministry also. When you recruit a person, there are two options. From commonsense point of view, I am telling you. Say, you have to appoint a Deputy Collector. One option is to go for a competitive exam, that is, open competition, notwithstanding any age, notwithstanding any region, notwithstanding any other thing. You can go as per merit. But in the absence of open competition, the option left is, you go by seniority. That's why my predecessor, Shri Arun Shourie, had imported the first-come-first-serve policy during his tenure. There was nothing wrong in that. (Interruptions)

SHRI ARUN SHOURIE: But the point is this. Did I ever change the date like you did? (Interruptions) First one date is given, say, 1st October. Then, suddenly, this cut off date is changed to 25th September. (Interruptions) There was free for all in the Sanchar Bhawan, my friend. (Interruptions) First you give 01st October as the cut off date. Then, all of a sudden, you change it to 25th September. (Interruptions) You give me any precedence where such a thing had

occurred either in my tenure or anybody else's tenure, including Mr. Dayanidhi's tenure. (Interruptions

SHRI A. RAJA: I am coming to each and everything one by one. (Interruptions)

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I think, the basic issue, raised in the House, is not being addressed. (Interruptions) If something is being sold at the prices of 2001, in the year 2007, without assuming the velocity of the market. (Interruptions) What are you saying? We, the Members of Parliament, also have.....(Interruptions) The fact is that the very same material...(Interruptions)

SHRI TIRUCHI SIVA: He is not yielding. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): This way, I won't be able to hear anybody. (Interruptions) No; no. Please sit down. (Interruptions) I am not allowing you. (Interruptions) No more interruptions please. (Interruptions) Mr. Minister, you please address the Chair. (Interruptions) Don't get distracted by any interruption. (Interruptions)

(Contd. by 2h)

PB/2H/1.35

THE VICE-CHAIRMAN: Please do that.

SHRI A. RAJA: Right, Sir. I will come to that one by one. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN: Only what the Minister is saying would go on record.

SHRI A. RAJA: I will come to that one by one. Why are you jumping ...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I told you to please look at the Chair and address the Chair. Why don't you address the Chair? That is the problem.

SHRI A. RAJA: Sir, the issue of first-cum-first-serve is very important.

THE VICE-CHAIRMAN: That is correct. But address the Chair.

SHRI A. RAJA: Sir, the first-cum-first serve policy was adopted as soon as we migrated to NTP 1999. I assumed the charge on 16th May, 2007. Just see, till April 5, up to my predecessor, Mr. Dayanidhi Maran's time, right from Arun Shourie's time, how many licences were issued? Fifty-one licences were issued on the first-cum-first serve basis. It has been observed in each and every file, in all 51 files. Just 20 days previous to my taking charge, invariably all Ministers, invariably all officers concerned, observed categorically on the file that this licence was being issued on first-cum-first-serve basis. What is wrong with Raja? So far as the rule is concerned, it was not devised by me. Even I am not attributing any motive on the part of the Ministers. That is why I justified it in other manner. There are two options; either go for competitive exam or for the employment seniority.

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Minister, I am telling you to look at the Chair and address it. You don't have to look back. ...(Interruptions)... No; no; please, please ...(Interruptions).

SHRI TAPAN KUMAR SEN: *

THE VICE-CHAIRMAN: That will not go on record. ...(Interruptions)... That will not go on record. I will allow you in the end.

---

* Not Recorded.

SHRI A. RAJA: Sir, my sincere submission is, licences were issued on first-cum-first-serve basis on the same rate, just ten days prior to my assumption of the charge. They were issued on the same rate in 2001. Just 15 days prior to my taking charge, 51 licences were issued in all; but no question was asked against them. Had it been asked, Parliament could have thought over it, and, if necessary, a Group of Ministers could have been appointed to see whether it was possible or not. However, as a lawyer, I am fully satisfied with the legal measures that had been taken by the NDA Government. I am standing here as a Cabinet Minister in the UPA Government. That is different. But as a lawyer, I applied my mind. Sir, I am coming again to 25th September. Sir, the TRAI recommendation says, 'there should be no capping; you issue as many licences which are needed by the country.' On 25th September, we issued a Press Note saying that 'those who are having the intention to apply for the Telecom, they can apply.' At that time, neither the Minister nor the Secretary of the Ministry or any other officer in the Ministry could foresee that such a huge number of applications would come. When we issued the Press Note on 25h September for inviting new applications, there were some pending applications also. The TRAI recommendations came in the Ministry on 25h September. In other words, I can say, the moment I got the TRAI recommendation asking for going for new operators, they filed applications. The applications were received. Even an interpretation can be given. Of course, the PIL is pending in the High Court. An interpretation can be offered why the Department has received these applications. That is a different matter. That is a matter of argument before the Court. What I

wanted to impress upon the Parliament is, why we had chosen 25th September. Three hundred applications cannot be processed, cannot be given licences. Suppose we have to issue three hundred licences, even three hundred people may not be eligible. There could be twenty or twenty-five. Even twenty-five is too high a figure for this country. So, we wanted to have a reasonable restriction. Now, how can we demarcate it? The reasonable restriction is, demarcate the applications originally pending before calling new applications. These applications were pending before the call for new applications was made by the Press Note. All right, the Press Note was issued with due diligence. I may submit before the House that the issuance of new licences, dual technology and the allotment of new spectrum were challenged, before it was given, by the Cellular Operators Association of India. The moment they came to know that the Ministry is going to give new operators the wide spectrum, the Cellular Operators Association of India, of which Airtel, Aircel, Vodafone, Idea, etc., are members, filed a case in the TDSAT saying that no new licence should be given, no new technology should be given and no spectrum should be allotted where the case is filed in the TDSAT.

(Contd. by 2g/SKC)

2j/1.40/skc

SHRI A. RAJA (Contd.): The Solicitor General of India appeared before the TDSAT, which is headed by a retired Judge of the Supreme Court, and said that these people wanted to curtail healthy competition; these people wanted to maintain a cartel; this is the TRAI recommendation; this is the policy of the Government; this is the policy of NTP, 1999, and

so, there should not be any stay. Of course, there was a stay for ten days. For ten days there was a stay, which was given by the Court orally, saying that no licenses should be issued, no spectrum should be allotted. After hearing the argument, TDSAT said, no stay can be granted; it is policy of the Government; let them go. The petition was dismissed. Then they filed an appeal in the Delhi High Court. The Delhi High Court heard the matter whether the date, 25th September, was correct or not. The Delhi High Court upheld the decision taken by the Government as correct. The only point I wanted to personally share with my learned friends was whether as a Minister of the Telecom Department I showed due diligence in choosing the date of 25th September. Sometimes I get disturbed when I am told where is transparency. I maintained utmost transparency in the Ministry. How? I issued a Press Release; whether it is first-come-first-serve policy or how licences are to be issued. The discretion if, at all, exercised by the DoT, the Department of Telecom is not a Government discretion, as observed by the judges. Judges observed in one case that discretion exercised by the Executive or the Judiciary at the lower level, should not be considered to be Government discretion. This Press Release speaks much. The Department issued a Press Release on 10th January. Where is the question of concealing facts or something else? The Press Release says, "In the light of the Unified Access License Service guidelines issued on 14th December, 2005 -- undoubtedly, in the Government headed by the NDA... (Interruptions)

DR. V. MAITREYAN: NDA was not there in 2005; it was Dayanidhi Maran... (Interruptions)

SHRI A. RAJA: I amend it; I amend it. The guidelines by the Department regarding number of licenses to service area a reference was made to TRAI on 13.04.2007. The TRAI, on 28.08.2007, recommended that no cap be placed on the number of access service providers in any service area. The Government accepted this recommendation of TRAI. Government means, after deliberations the Telecom Commission also, where the Telecom Commission is being represented by Secretary (Finance), Secretary (Industry) and other officers. Hon. Prime Minister also emphasized on increased competition while inaugurating India Telecom, 2007. Accordingly, DoT has decided to issue letter of intent to all the eligible applicants on the date of application who applied up to 25.09.2007. Now, what law says, and even Article 14 of the Constitution, as the Leader of the Opposition is aware, is that the classification going to be done by the State must be reasonable and not class legislation. What has been prohibited by the Constitution is class legislation, not the reasonable classification. This is a reasonable classification, according to us, that has been deliberated upon in this Ministry. Thereafter, nothing was done surreptitiously or in a stealthy manner. We issued this Press note. It says, 'UAS license authorises a license to roll out a telecom access service using any digital technology which includes wire line, wireless, GSM, CDMA services. They can also provide internet telephony. For this, UAS license has to obtain another license, that is, wireless operating license". Then, the third paragraph is very important. DoT has been implementing a policy of first-cum-first-serve for grant of UAS licences under which initially an application which is received first will be processed first and, thereafter,

if found eligible, will be granted LOI, and then, whosoever complies with conditions of LOI, will be granted UAS license. So, how are we going to give licenses? It is on the basis of first-come-first serve policy. It is there in the Press Note. We have chosen 25th September in the Press Note. My only submission before the Parliament is that neither the cut-off date was imposed by the Ministry nor the policy for giving licences was adopted in a stealthy or secretive manner. Of course, it is challengeable. Anybody could challenge the Press Note. Anybody could challenge the decision of the Government. That is different. What I wanted to impress upon the House is that nothing has been done in a clandestine, surreptitious or stealthy manner. To that extent, I am sure.

(Followed by hk at 2k)

HK/2k/1.45

SHRI ARUN SHOURIE: You have said that the High Court upheld the change from 1st October to 25th September. Is that correct?

SHRI A. RAJA: Which one?

SHRI ARUN SHOURIE: You have just told us that the High Court..(Interruptions).. My friend Arun Jaitley says that that specific point was quashed by the Court. So, please don't mislead..(Interruptions)..

SHRI A. RAJA: In one case, the order against the TDSAT has been upheld. Then after a long time, maybe six or seven months, one among the operators, namely, S-Tel, filed another case in the Delhi High Court suppressing the fact that another judgement is there. He got an order that his application should be considered, ignoring the press note. That is why I am telling that press note is challengeable, PIL is pending and cases are pending. ..(Interruptions)..

SHRI ARUN SHOURIE: But he is saying that the High Court quashed it.

SHRI A. RAJA: It is in the COAI matter. There are two cases. Cellular Operators Association of India filed a case in TDSAT -- miscellaneous petition for stay. That was appealed to the High Court; that was denied by the High Court for which they preferred a Supreme Court appeal. That is pending. That process is something different. Notwithstanding the Cellular Operators Association of India, another proceeding has been initiated by some other operator suppressing the fact that there is a judgement for which we filed an appeal. That is why I am telling that legal positions are there. I am not a competent person to say what has been done is judicially right or wrong. That is different. Again and again, I wanted to submit before the House whether the due diligence was applied by the Ministry or by the ..(Interruptions)..

SHRI ARUN SHOURIE: You have said that High Court approved the change. But Jaitley's recollection is that High Court quashed that change. Please tell us what is the truth. ..(Interruptions)..

SHRI A. RAJA: There are two conflicting judgements. On 25th September, dual technology, additional spectrum and all these issues ..(Interruptions)..

SHRI ARUN SHOURIE: Between 1st October to 25th September, you claimed that the High Court had approved it. ..(Interruptions)..

SHRI A. RAJA: There is a judgement both against the Government and in favour of the Government. It is being upheld in the Supreme Court. ..(Interruptions)..

DR. V. MAITREYAN: Between 1st October to 25th September how many applications were received? You said that first application was

considered first. After that subsequent applications were also being considered ..(Interruptions)..

SHRI A. RAJA: Sir, our argument is ..(Interruptions).. My records are correct. ..(Interruptions).. Sir, on S-Tel judgement ..(Interruptions)..

SHRI ARUN SHOURIE: Sir, it may be a matter of privilege. So, I want to caution the Minister that I have with me the text. ..(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Why don't you raise it after he completes his reply?

SHRI ARUN SHOURIE: The respondent cannot be allowed to change the rules of the game after the game had begun. This is what the Court said in regard to the judgement ..(Interruptions)..

SHRI A. RAJA: In one judgement. I accept it. ..(Interruptions).. But it is being appealed to the Supreme Court. ..(Interruptions)..

SHRI ARUN SHOURIE: Mr. Raja, you had said it specifically. I am not against you. I don't want a situation in which we are forced to move the matter of privilege. You said specifically that the change had been approved by the High Court. ..(Interruptions)..

SHRI A. RAJA: Not approved by the Court. I never said that this was approved by the High Court. ..(Interruptions)..

SHRI ARUN SHOURIE: The High Court said, "No, you cannot change the rule after the game had begun." ..(Interruptions).. That was the point. ..(Interruptions)..

SHRI A. RAJA: I didn't change the rule. ..(Interruptions).. I gave the press note.

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Raja, ..(Interruptions)..

SHRI A. RAJA: I am not yielding. I will finish it. ..(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Raja, after you finish your speech I will allow hon. Members for clarification. ..(Interruptions)..

SHRI A. RAJA: Sir, I admit that there is a judgement. ..(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN: You continue with your speech. ..(Interruptions).. You say whatever you want to say. ..(Interruptions)..

SHRI A. RAJA: Sir, I admit that there is a judgement quashing the order of the Government. That is different. ..(Interruptions)..

SHRI ARUN JAITLEY: Let the hon. Minister finish. Then we have some clarifications. ..(Interruptions)..

SHRI A. RAJA: Sir, I have come across that S-Tel filed a case ..(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN: How much time do you want? ..(Interruptions)..

SHRI A. RAJA: I need ten minutes.

THE VICE-CHAIRMAN: After that I will allow clarifications. ..(Interruptions)..

(Followed by 2l/KSK)

KSK/1.50/2L

SHRI A. RAJA: Sir, S-tel filed a case. It came very recently, and I think, last month only. Sir, I think, the judgment came last month that he challenged that 25th September cut-off date was not correct. It was upheld by the Court that the decision taken by the Government was not correct. It mentioned that we should go for the other applications also. It has been appealed in the Supreme Court. I did not suppress any fact...(Interruptions). One other judgment...(Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, why do you reply to interruptions? You should say what you have to say. Any Member may put a question and you start replying. First, finish your speech.

SHRI A. RAJA: Sir, there are conflicting judgments. Proceedings are pending. That is why, I told that PIL is pending. I cannot go beyond the limit that how the judgment will come. If at all, the judgment comes tomorrow, I have to bow my head. That is different. As a lawyer, I know that...(Interruptions). Sir, my only submission is...(Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN: Please, look at the Chair. You are looking back at every Member. Please, address the Chair.

SHRI A. RAJA: Sir, what I wanted to say is that the procedure contemplated for first-come-first-serve has been followed right from 2004 invariably by all the Ministers. This justifies that no other alternative is available to the Government. 25th September also is not a surreptitious act. We have not done anything stealthily. The Press Note was given. It was opposed. After six months or one year, some one has filed a case. The judgment came against the Government wherein other references were made, and TDSAT and the other Court where all these cases, like dual technology spectrum, were upheld. That has also been challenged by the COAI. So, cases are pending in the High Court and the Supreme Court. Notwithstanding the proceedings in the Courts, what I wanted to say is that in issuance of licence, in issuance of spectrum, we followed the rule. There is no departure as per the earlier records available in the Ministry. We paid due attention to due diligence in terms of spectrum, in terms licence. I hope that the questions put by

hon. Members have broadly been answered by me. If at all, some questions have been left out, I will write directly to the Members. With these words, I conclude.

(Ends)

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, the hon. Minister has answered the debate at length. And, he has gone into various issues which were of some considerable importance. The core issue was neither the Postal Department nor the IT Department. We are grateful to him that he has gone into the issue at length - that the TRAI said, "Don't cap. Give it to as many as possible. There must be revenue sharing." The policy of first-come-first-serve is an old one. We have heard this indefinitely. But, as the hon. Member pointed out, there was one core question, and that one core question has not been answered. That one core question was whether when in 2007, without capping, you decided by 25th September or 1st October -- I am not into the arbitrariness of the date also at the moment -- to give additional licences and you shortlisted some 9-odd people who had to be given licences. I am not even on the figure. For that licence plus spectrum, 4.4 MHz or 6.2 MHz, how much should the Government have charged in 2007? That is the only question today. And, the whole nation wants to know whether that charge, which the Government has taken for that licence plus spectrum, of Rs.1650 crores, represents the fair value which the Government should have got as on that date. Sir, I am constrained to observe that if no answer, or no satisfactory answer, is being given, then we are entitled to presume that no answer could have been given. And, the reason being, first, the Minister rightly posed a question that

the cost of a shirt in 2001 was different and in 2007, it had to be different. Therefore, either the inflation index or the net present value from 2001 to be brought to 2007, should the Government not have considered, even if it did not want an auction, to improve upon the 2001 value in 2007 when this licence plus spectrum was being valued?

(continued by 2m - gsp)

GSP/1.55/2M

SHRI ARUN JAITLEY (CONTD.): Secondly, does the Minister now feel after the event, now that we have all the information available, that some of the recipients of these licences at Rs. 1,650 crore, immediately upon receiving the licence, availed the FDI policy in the telecom sector, and, off loaded 50 to 74 per cent of their shares to foreign collaborators, and, for that purpose, the valuation overnight changed from Rs. 1,650 crores to $ 2 billion, which is roughly Rs. 9,000 crores. Today, is he convinced that Rs. 1,650 crore price was under-valued?

Mr. Arun Shourie referred to the point, and, asked a question, if there is a correspondence from TRAI saying, "our recommendation has not been followed", and, even when the TRAI said, don't cap, and issue fresh licences, did the TRAI, at the same time, say -- and, I am reading the sentence -- "the entry fee as it exists today is, in fact, a result of a price discovered through a market-based mechanism applicable for the grant of licence to the fourth cellular operator. In today's dynamism and unprecedented growth of the telecom sector, the entry fee determined then, that is, 2001, is also not the realistic price for obtaining a licence; perhaps it needs to be reassessed through a market mechanism." (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Don't interrupt. You can reply later. (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Therefore, the TRAI says, don't cap; but not the 2001 price, determine it by a market mechanism. You determine the 2001 on NPV of 2007. The evidence came the very next day when within days of receiving the licences, 50 to 74 per cent shares were off loaded and the valuation discovered was not Rs. 1,650 but $ 2 billion. Today, is the Minister convinced that this Rs. 1,650 crore value was grossly undervalued. That is the core question, and, I am afraid that on this question, no satisfactory reply is coming.

DR. V. MAITREYAN: Sir, let us also seek the clarifications, then, the Minister can reply. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Okay. (Interruptions) Mr. Raja, you can reply at the end. Shri Sitaram Yechury. (Interruptions) Please don't resort to speeches. Just seek clarification.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, only due to this, I am not even proposing to repeat what the hon. Leader of Opposition has said. I am not going into that.

My only point is that it was sold at Rs. 1,650 crore, but after that the off loading was done by two companies to the tune of 50 to 74 per cent of their holdings, for an amount close to Rs. 10,000 crore. Now, this discrepancy is what has been suspected by all of us as a scam. What was that? The Minister will have to answer all of us about it. Either there was a genuine reason for them to price it so low, in which case it is a matter of omission, not commission, made by somebody, and, Sir, under the Indian Penal Code, both the acts of omission or

commission, are acts of corruption. So, if it was an act of omission and they had put it at Rs. 1,650 crore; that has to be explained. If it was not an omission, ex-post, looking back, when Rs. 10,000 crores could be made by off loading only 50 to 74 per cent, of what they were holding, then there was commission. Now, whether there was an act of omission, or, an act of commission, or, both, in each case, this is corruption. That aspect has to be addressed.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Mr. Maitreyan. Please seek only clarification.

DR. V. MAITREYAN: Sir, there are two questions involved. One is with regard to the licence fee of Rs. 1,650 crore or more, which the Leader of Opposition, Shri Arun Jaitley has asked. Second is with regard to 'first-come, first-serve' policy, which the Government pursued. Sir, I want to know from the Minister the criteria for selection of the companies. As far as quality is concerned, were those companies experienced in the telecom sector? They were all real-estate companies. They had no experience whatsoever in the field of telecom sector. So, it is just like that I start a letter-pad company, get the licence, and, transfer it to somebody. So, whether the factors like quality, past-experience and performance of the company in the field during the last decade, were taken into consideration. And, if these factors were not taken into consideration, then, who is accountable?

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (KARNATAKA): Sir, up to 2001, all 2-G licences were given through a process of tender. Mr. Minister mentioned my letter to him. When I first raised the issue of spectrum in

2007, the Minister responded saying, "this is consistent with the existing Government policy".

(Contd. by sk-2n)

SK-AKG/2N/2.00

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (CONTD.): I think, the most important question that Parliament needs to know is, at what stage this very simple process of tendering became this first-come-first-serve and why? Who made this recommendation and what was behind it? My second question is, will you now accept that there is a need to make a reference to the regulator for a new pricing mechanism for spectrum because the crux of the issue is spectrum is valuable? The price of Rs. 1650 crores is not an acceptable price for the spectrum? Will you, at least, now make a commitment to the Parliament that you will now make a reference to TRAI suo motu to fix a new price for spectrum? (Ends)

SHRIMATI BRINDA KARAT (WEST BENGAL): My only point is, considering the gravity of the issues which have come, concerning the loss to the exchequer, the estimates ranges from rupees sixty thousand crores to one lakh crores on this one issue, there has been a demand that there should be an impartial inquiry into this entire incident. We have been demanding a JPC also on it, Sir. What I would like to know from the Minister is, this demand, which is being made in both the Houses of Parliament, will it be considered? (Ends)

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो ग्राम डाक सेवक हैं, उनकी डिमांड बहुत समय से pending पड़ी है। यूपीए ने अपने मैनिफेस्टो में यह commitment किया था कि हम उनके लिए आने वाले बजट में प्रावधान करेंगे, लेकिन न तो बजट में उनके लिए प्रावधान हुआ है और न ही आदरणीय मंत्री

जी ने इसके बारे में कुछ कहा। मैं यह जानना चाहूँगा कि गोपीनाथ कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने पे स्केल के बारे में recommend किया है, उसको लागू करने के बारे में आप विचार करेंगे, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट में village level पर इस सर्विस को मजबूत करने के काम में डाक सेवकों का बहुत बड़ा योगदान है? इसके बारे में मंत्री जी कृपया बताएँ। (समाप्त)

DR. CHANDAN MITRA (NOMINATED): Sir, my question is very short and simple. It is a follow-up of what Dr. Maitreyan has asked. I would like to know from the Minister whether any process of due diligence was conducted before the allotment of first-come-first-serve spectrum to certain companies and whether the ownership pattern of these companies, that were allotted, is known. And, is it true that there are certain real estate companies from Tamil Nadu which took large shares in the companies that were allotted the spectrum and, therefore, were the beneficiaries when the spectrum was sold to a Singapore-based company at 5-6 times of the value? (Interruptions) Will the Minister please clarify the ownership pattern of the original allottee of the first-come-first-serve pattern?

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मैंने चर्चा के दौरान communication and information technology के बारे में जो कुछ भी तथ्य उजागर किए थे, उन्हें मंत्री जी ने स्वीकार किया है। ... (व्यवधान) ...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, you ask the question.

श्री प्रभात झा: सर, मेरी कुछ भ्रांतियाँ हैं, उन्हें तो दूर करना पड़ेगा न। ... (व्यवधान) ...

THE VICE-CHAIRMAN: No, no. If you have questions, you ask. Otherwise, no.

श्री प्रभात झा: सर, उन्हें मेरे confusion को दूर करना होगा न। मैं आपको confusion तो बताऊँ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): ठीक है, आप जल्दी बताइए।

श्री प्रभात झा: अगर आप जल्दी में हैं, तो मैं बैठ जाता हूँ।

उपसभाध्यक्ष : ठीक है। Yes, Mr. Minister.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I want to ask one question.

THE VICE-CHAIRMAN: No, no.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Why Sir?

THE VICE-CHAIRMAN: People have already asked from your party. (Interruptions) Please take your seat.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Please let me ask, Sir. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: No, no. Not at all. (Interruptions)

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, he is a trade union leader.

THE VICE-CHAIRMAN: No more speakers. (Interruptions) I have allowed two speakers from your party. (Interruptions) Let me be fair. (Interruptions)

SHRI SITARAM YECHURY: Thank you very much for that, Sir. (Interruptions) I am only saying that he is a trade union leader. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: I am not allowing all those who spoke. (Interruptions) I am not allowing all those who spoke. I have already allowed both of you. I have to be fair.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, this is not a party-based question. Clarifications cannot be party-based clarifications. He was in the trade union meeting. He has got questions to raise.

THE VICE-CHAIRMAN: How many should I allow? (Interruptions)

SHRIMATI BRINDA KARAT: Last point, Sir. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: How many should I allow? (Interruptions)

(Followed by 2O-ysr)

YSR-SCH/2.05/2O

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Brindaji, so many hon. Members are asking, that is my problem. Where do I stop? (Interruptions)

SHRIMATI BRINDA KARAT: But he is directly meeting trade unions. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Then every Member has a claim. (Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, he initiated the debate. At least, let him ask. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: I said, जल्दी बोलो. He said, 'no.' What can I do? (Interruptions)

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, allow both of them half a minute each. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Since the Leader of the Opposition has intervened, I concede it.

श्री प्रभात झा: डाक-तार विभाग को लेकर जितनी बातें कही गई थीं, इन्होंने उन्हें स्वीकार किया। किसी चीज़ को राजनैतिक रूप में न लेते हुए इन्होंने विभाग की दृष्टि से देखा है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इन्होंने एक बात बीएसएनएल और एमटीएनएल के बारे में कही, यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह आपके विभाग की रिपोर्ट है और यह टाइम्स ऑफ इंडिया में कही गई है और मैं इसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं, "बीएसएनएल और एमटीएनएल घाटे में हैं", लेकिन आपने यह कहा कि घाटे में नहीं हैं। आप यह कैसे कह रहे हैं? आप यह बताइए कि अगर घाटे में नहीं हैं तो कितने फायदे में हैं?

उपसभाध्यक्ष: ठीक है, हो गया।

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, I am on the non-core questions. On core questions, I join my colleagues. The other non-core questions have not been touched by the hon. Minister in his reply.

One, he told that the BSNL and the MTNL cater to 5,65,000 villages. I really appreciate that. But, at the same time, he has not clarified why then the other private operators are allowed to share the Universal Service Obligation Fund.

Two, and this question was raised during the discussion also, what is the basic reason behind the decrease in the net profit of the BSNL in the current year? In the current year, its net profit has gone down to Rs.104 crore from Rs.3,000 core last year and from Rs.8,000 crore year before last. And why is the BSNL continuing with a huge arrear of revenue collection? What is the reason? What is the basic thing behind that?

Three, a point was raised about Extra Departmental Employees and the Grameen Dak Sevak. (Interruptions) That has also not been replied by the hon. Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He has replied to that. (Interruptions) No more questions.

SHRI N.R. GOVINDARAJAR: Sir, I want to know from the hon. Minister..(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI A. RAJA: Sir, earlier I submitted this before the House and to the Leader of Opposition. What has been categorically recommended by TRAI, I shared it with him and Parliament.

Regarding the portion that was read by the Leader of Opposition, yes, I do admit that that observation is there. Equally true is that other observations are also there. Page 47 of the TRAI recommendation says, "Keeping in view the objective of growth, affordability, penetration of

wireless service in semi-urban and rural areas, the Authority is not in favour of changing the spectrum fee regime for a new entrant. Opportunity for equal competition has always been one of the prime principles of the Authority in suggesting a regulatory framework in telecom services.(Interruptions) One minute. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No interruptions are permitted. (Interruptions) No.

SHRI A. RAJA: "Any differential treatment to a new entrant will affect the principle of level-playing field." That is why I submitted this.

THE VICE-CHAIRMAN: Please make your reply brief.

SHRI A. RAJA: Twenty days prior to my career in the Ministry, the licence was issued at the same rate. We deliberated TRAI recommendations and then the recommendations one, two, three and four came into existence. Till 2001, and even 2007, so many recommendations came. The second recommendation of the 2002 says that you increase the subscriber base. Then they are telling that by increasing the subscriber base, it is incumbent upon TRAI to raise the base value, entry fee also. What I submitted before the House is that both the observations are there. (Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, he is not talking about the revenue point. (Interruptions)

SHRI A. RAJA: See both the recommendations. (Interruptions)

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, he is not answering the main question. (Interruptions)

SHRI A. RAJA: Sir, I cannot question TRAI. It is a statutory body.

DR. V. MAITREYAN: Did you protest that? (Followed by VKK/2P)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, please. (Interruptions) Brindaji, please. (Interruptions) You say what you have to say. (Interruptions) Don't listen to them. (Interruptions) You say what you have to say. (Interruptions) You address the Chair and say what you have to say. (Interruptions) Don't listen to them. (Interruptions)

SHRI A. RAJA: Sir, TRAI is a statutory body. It can give recommendations on its own accord. Suo motu recommendations can be given. (Interruptions) Sir, this is not the way. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: No interruption please. (Interruptions) Only what the Minister says will go on record. (Interruptions) You look at the Chair and say what you have to say. (Interruptions) Nothing else will go on record.

SHRI A. RAJA: Sir, right from the beginning, I am saying that so far as the recommendations or rules are concerned, the Department never flouted. That's why, I clarified the observation made by the court as well as the hon. Member whether it is ratio decidendi or obiter dictum. No doubt, entry fee must be nominal. That has been contemplated in the TRAI recommendation. It has to be revisited. By whom? TRAI has to revisit. I am not the competent authority. We felt that at the time of the discussion before the issuance of licence. But, it has not been revisited by TRAI. Ten days back, the same licence is issued by the existing operators, namely, Vodafone and others. So, the revenue share has been enhanced in terms of percentage. TRAI has not recommended it. That is why, I am, again and again, submitting before the House that due diligence was taken and revenue was being enhanced out of the licence fee on the spectrum. Not only spectrum, there is a licence fee on the basis of revenue sharing also. Ten per cent

is collected on the licence -- five per cent for USO and five per cent for the other side. So, ten per cent is being collected. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. Please. (Interruption) Tiwariji, please. (Interruptions)

SHRI A. RAJA: I have not been directed. (Interruptions) I have not been directed by TRAI to change it. (Interruptions)

SHRIMATI BRINDA KARAT: Has he been directed not to change it? (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Are you yielding to the Leader of Opposition? (Interruptions)

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): If the Minister is so convinced that he is not wrong, is he willing to have a JPC as suggested? (Interruptions) You are not answering the question. (Interruptions) Are you willing to have a JPC? (Interruptions)

SHRI SITARAM YECHURY: I have only one question. If the Minister says there is nothing wrong, why don't we have a JPC? (Interruptions)

SHRI A. RAJA: I can't say that. (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Is the Minister or the Government willing for a JPC on this subject? (Interruptions)

श्री शिवानन्द तिवारी: सर, ...(व्यवधान)... इसकी जे0पी0सी0 से जाँच करवाइए...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN: No. (Interruptions) Please, take your seat. (Interruptions)

DR. V. MAITREYAN: What is the process of selection of companies? (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Maitreyan, please sit down. (Interruptions) If all of you will stand up at once, neither can I hear nor can the Minister. (Interruptions)

SHRI A. RAJA: Sir, I would conclude in three minutes. Issuance of licence is in my domain. Issuance of spectrum is in my domain. What I want to submit is that there is no departure from the TRAI recommendation. If you say that TRAI has failed to recommend something or the Ministry has failed to refer it, that is a different matter. (Interruptions) They have to give. (Interruptions)

SHRIMATI BRINDA KARAT: Did you study that issue? (Interruptions)

SHRI A. RAJA: Sir, I am not yielding. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Don't look at them. You look at the Chair and say what you have to say. (Interruptions)

SHRI A. RAJA: Sir, revisiting the licence fee is in the domain of the TRAI. TRAI can recommend it tomorrow or a day after tomorrow. My apprehension, with all my sincerity to the Parliament, is that even if TRAI recommends for 3G auction, the person who is going to take spectrum on auction, that person or the company is going to be given licence. Even for that, TRAI has not recommended. At least, for 3G, the entry fee must be high. Please accept me. (Interruptions) TRAI recommendation for 3G spectrum was that 3G spectrum should be auctioned because it is a value added service. Rice can be given in PDS at subsidised rates, but ghee cannot be given at subsidised rates. TRAI recommended 3G can be auctioned. The operators can be permitted globally. Not only Indians, but, any global operator can come in for getting the 3G spectrum, but, a licence has to be issued. That is the rule we made. It is a guideline. Even then, the licence fee was not revisited by TRAI. My submission is, if it is revisited by TRAI, the Department will definitely accept it.

(Contd. by RSS/2q)

RSS/2Q/2.15/

SHRI A.RAJA (CONTD.): Coming to the Unitech Swan, Sir, issuance of licence is with me...(Interruptions)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Nothing except the Minister's statement will go on record.

SHRI A.RAJA: Licence is with me, Spectrum is with me, we followed the rules contemplated for licence and the Spectrum. Having given this, this is the first time, and that is why I submitted before the Parliament that I am the first Minister who travelled the new domain as per the TRAI recommendations... (Interruptions)... No Minister has been compelled to go to the other domain in the absence of the TRAI recommendations. The recommendation of the TRAI says: go for competition. We put it. Having given the spectrum, having given the licence...(Interruptions)...

DR. V. MAITREYAN:*

THE VICE-CHAIRMAN: Don't react to that. That is not going on record. Why do you react to that? You address the Chair and say what you want to say.

SHRI A. RAJA: Sir, when Essar got it, they are not in the telecom. The qualification has been prescribed, so far as I am concerned. When I assumed charge, guidelines are there as to what will be the network, what will be the nature of the company, what will be the Indian margin, what will be the percentage, FIB clearance, these are all the issues. It is mentioned in the guidelines. If any breach or any violation is there in the

* Not recorded.

licence conditions, then the Department can be held liable. Coming to the Unitech Swan, I already submitted before the House during the Question Hour that issuance of licence is with me, issuance of spectrum is with me... (Interruptions)... In the past also, whether it is Airtel, Aircel, they diluted their share for huge money. It is already submitted that it is not that the money is going to individual pocket. It is a corporate law. I am not concerned with it. Having issued licence, having issued spectrum, FDI policy immediately will attract. According to the FDI policy, they are doing. I discussed that with the Finance Ministry at my level. I think that I am the first Minister in the Ministry who wrote to the department to deliberate with the Telecom Commission that the equity of sale for three years should not be permitted. There was no condition prior to me. After discussing all these things because this is a new era for us, I have come across this type of FDI policy will enrich some companies. So, I made a law that equity of the sale should be prohibited. Remaining norms under FDI, permit them to go for that. That is all. (Ends)

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): We want a JPC. Mr. Minister, will you agree to the appointment of a JPC? ... (Interruptions)... Sir, we are completely dissatisfied with the reply of the Minister on this issue. It is a huge monumental scandal. Therefore, we are going to walk out.

(At this stage some Hon. Members left the Chamber.)

SHRI SITARAM YECHURY: We want a JPC. We are not satisfied with the reply of the Minister. We are walking out... (Interruptions)...

(At this stage some Hon. Members left the Chamber.)

श्री शिवानन्द तिवारी : महोदय, मंत्री जी के ...(व्यवधान)... भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है और उसकी जांच भी नहीं हो रही है। ...(व्यवधान)... यह सरकार पर आक्षेप है ...(व्यवधान)

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गए)

श्री कमाल अख्तर: सर, माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं ...(व्यवधान)...

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गए)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. Now, we will take up the Appropriation (No. 3) Bill, 2009. Shri Namo Narain Meena. Please keep quiet. Don't make noise.

THE APPROPRIATION (NO.3) BILL, 2009

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, on behalf of my senior colleague, Shri Pranab Mukherjee, I beg to move that the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2009-10, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, do you want to say something?\

SHRI NAMO NARAIN MEENA: No, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN: Now, Shri Vikram Verma.

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने इस विनियोग विधेयक के माध्यम से 304 खरब, 32 अरब, 55 करोड़, 88 लाख रुपए की स्वीकृति सदन से चाही है।

(2आर/डीएस पर क्रमश:)

श्री विक्रम वर्मा (क्रमागत): वैसे तो पास करने या न पास करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश में योजनाओं की जो स्थिति है, जिसके लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है, उन योजनाओं को यदि आप देखें तो उनका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है और इसीलिए उनकी उपयोगिता एक प्रकार से प्राय: कम हो जाती है। बजट को पेश हुए भी लगभग 20 दिन हो गये। इसे 6 जुलाई को पेश किया गया था। देश में एकाध दिन को छोड़कर, जो प्रैस विज्ञप्ति सरकार की तरफ से आई, उसके बाद प्राय: पूरे देश के अंदर एक निराशा का वातावरण है। देश में एक प्रकार का जो आर्थिक विश्वास पैदा होना चाहिए था, उस प्रकार का कोई आर्थिक विश्वास देश के अंदर पैदा नहीं हो पाया। इसलिए जो उम्मीदें थीं कि कुछ सकारात्मक काम होंगे, आम आदमी को राहत मिल पाएगी, इस प्रकार का कोई संकेत आज तक इस दिशा में नहीं आ पाया है।

अभी शुक्रवार को माननीय वेंकैया जी ने आंध्र प्रदेश सरकार का एक विज्ञापन जो अखबारों में छपा था, वह सदन के पटल पर रखा था, उसके बारे में बताया था। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। उसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वयं यह बताया था कि वहाँ किन-किन वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। वह अपने आप में इस बात का ज्ञापन है कि किस प्रकार से महँगाई एकदम बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ, हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से जो बराबर आता है, टीवी पर आ रहा है और बाकी जगहों पर आ रहा है कि महँगाई का रेट माइनस से भी नीचे चला गया है। यानी, दोनों में कहीं समानता नहीं दिखती, क्योंकि एक तरफ तो आंध्र प्रदेश की सरकार स्वयं महँगाई के आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। आप बाजार में चले जाएं, आपको महँगाई दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार की जो बातें हैं, वे कोई विश्वास पैदा करने वाली बातें नहीं हैं। बाजार में चीजों की कमी है। दालें आयात की गईं, लेकिन आज वे आयातित दालें कहाँ हैं? वे दालें कहाँ गईं? वह जनता के बीच में नहीं पहुँची। उपभोक्ता को नहीं मिल पा रही है और इसलिए उसका भाव 90 रुपये और 100 रुपये तक जा रहा है। आखिर ये सब चीजें आती हैं, बुलाई जाती हैं, लेकिन कहाँ जा रही हैं?

माननीय कृषि मंत्री जी ने शुक्रवार को यहाँ पर एक घोषणा की कि सरकार ने गेहूँ और बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, चावल के

निर्यात पर रोक पहले भी लगी थी, दालों के निर्यात के ऊपर भी रोक लगी थी, लेकिन दालों को निर्यात कर दिया गया। इसी सदन के अंदर मामले उठे। क्या आज तक उसकी जांच हो पाई? क्या यह पता लग पाया कि आखिर किन लोगों ने निर्यात किया, किस प्रकार से हुआ या किस चैनल से हुआ? इसी प्रकार, अभी आप बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मांग पर, जो पिछली बार चावल और बाकी चीजों के बारे में हुई, करीब 2,500 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला "आउटलुक" में, इसी सदन के अंदर और बाकी जगह भी उठाया गया। कहाँ गया वह? यह सीधा-सीधा 2,500 करोड़ रुपये का स्कैम है। आप यह घोषणा कर रहे हैं कि हमने निर्यात पर रोक लगाई। जो निर्यात उस दाम पर हुआ, वह आखिर कहाँ गया? आप देखें, घाना के राष्ट्रपति जी ने इसको और स्पष्ट किया है कि हमारे यहाँ का वह चावल घाना पहुँचा ही नहीं। आज यह स्थिति बनी हुई है। जहाँ तक माननीय वित्त मंत्री जी का दावा है कि हमने हर योजना की राशि पहले से अधिक बढ़ा दी है, इसे बढ़ा कर जितनी राशि की गई है, खास तौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में, उसमें 39,100 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष के बजट से 144 परसेंट अधिक दर्शाया गया है। हालांकि यह आठ महीने का बजट है, यह पूरे नौ महीने का भी नहीं है। आठ महीने में आपने राशि बढ़ाने की बात की है, लेकिन आप जरा देखें कि पिछला बजट जो 365 दिन का, पूरे वर्ष का था, उसमें पूरे देश के रोजगार का एवरेज 42 दिन आया था। जब आपने 365 दिनों में 100 दिनों के रोजगार देने की बात की तो अधिकतम कार्य का विवरण केवल 42 दिन, ज्यादा से ज्यादा 44 दिन, इसी सदन के क्वेशचंस के अंदर आया। आपका इस बार का बजट 365 दिनों का नहीं है बल्कि यह अब केवल 242 दिनों का है। आप यह कैसे कल्पना कर रहे हैं कि इन 242 दिनों में लोगों को आप 100 दिनों तक का रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे?

(2एस/एकेए पर क्रमश:)

aka-tmv/2s/2:25

श्री विक्रम वर्मा (क्रमागत): दूसरी बात, जिसको एक प्रकार से इसमें छिपाया गया है, वह यह है कि पहले जब बजट कम था, तब यह योजना पूरे देश में लागू नहीं थी। NDA सरकार के समय जब कुछ पिछड़े जिलों में फूड फॉर वर्क योजना लागू की गई थी, जब

रोजगार गारंटी योजना लागू की गई, तो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को हाथ में लिया गया। पहले जब यह योजना प्रारम्भ हुई तो यह केवल 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू हुई, उसके बाद 300 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू की गई और चुनाव से पहले आपने इसको पूरे देश में लागू करने की घोषणा की। लेकिन, आधा समय बीत चुका था जब आपने इसकी घोषणा की और इसलिए स्वाभाविक रूप से आपका यह दावा कि हमने रोजगार गारंटी योजना में 144 प्रतिशत अधिक धनराशि 39,100 करोड़ रुपया दिया है, सही नहीं है। मैं इसके इम्प्लिमेंटेशन की बात कर रहा हूं कि जब पहले ही इसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया, तो अब आपका इतनी धनराशि बढ़ाना केवल दिखावे के लिए है, क्योंकि वहां पर काम होना नहीं है। आपके पास न समय

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

है और जो यह आपका दावा है, वह दावा इस आधार पर गलत है कि पहले यह योजना कम डिस्ट्रिक्ट्स में थी, अब चूंकि पूरे देश को इसमें कवर किया जा रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बजट प्रोविजन्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे -- 200, 300 जिलों के नहीं बल्कि अब 550 से अधिक जिलों के हिसाब से आप करने जा रहे हैं।

इसमें जो एक दूसरा कम्पोनेंट जोड़ा जा रहा है, वह है कि स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण होना चाहिए। निश्चित रूप से यदि रोजगार के साथ-साथ हम वहां कोई स्थायी कार्य कर सकें तो ज्यादा अच्छा है, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात बता सकता हूं। हमसे कई बार प्रश्न पूछे गए कि हमारा जॉब कार्ड सरपंच ने, सचिव ने या किसी और ने ले लिया, आज तक हमारा क्या काम है, क्या नहीं है, हमारे पास आया ही नहीं। अब ये जो नीचे की कठिनाई है, इम्प्लिमेंटेशन में नीचे जो खामियां हैं, उसके बारे में भी इतने बर्षों बाद, योजना लागू होने के बाद भी हम उन खामियों को दूर नहीं कर पाए।

आपने किया कि बैंक पेमेंट चालू करेंगे। अब जो बैंक हैं, हर पंचायत में जहां-तहां आप काम खोल रहे हैं, लेकिन वहां बैंक नहीं हैं, बैंक कम से कम 15, 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप उसका वहां एकाउंट खोलने जा रहे हैं। बड़ा बैंक तो एकाउंट खोलने को तैयार नहीं, उनका कहना है कि 100 रुपए रोज का, उस समय तो 85 रुपए था, तो 80 और 85 रुपए रोज का है, इसका हम खाता कैसे खोलें। उनके लिए तो

यह एक प्रकार से, उनके नार्म्स के हिसाब से, खर्चीला बैठता है, इसलिए वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन, जैसे तैसे करके अगर एकाउंट खोल भी दिया तो किस्तें जमा नहीं हो पाती हैं। इसलिए जब मजदूर अपना दो, चार, आठ या दस दिन का पेमेंट लेने के लिए जाता है, तो दो-दो तीन-तीन बार उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं। अपने पास से किराया देकर उसको बैंक जाना पड़ता है, वह दिनभर वहां खड़ा रहता है, तब जाकर कहीं पेमेंट होता है। तो यह जो इसकी वास्तविक धरातल पर कमियां हैं, इन कमियों को यदि आप दूर नहीं कर पाएंगे तो इसकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए इन सब कमियों को दूर करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए।

आपका दूसरा क्षेत्र है प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना। आप देखें पेज 11 पर आपके बजट में आपने 59% अधिक राशि से 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह योजना इस वर्ष सिर्फ 6 महीने चलेगी। आप कह रहे हैं कि हमने 59% ज्यादा राशि रख दी है, लेकिन योजना चलने वाली कितनी है। अभी आपका 15 सितम्बर तक कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है और स्वाभाविक रूप से 15 सितम्बर के बाद ही काम चालू होता है, इसलिए इस योजना में आपके पास 6-7 महीने हैं। इन 6-7 महीने में आप यह देखें कि पुराने टारगेट तो आप पूरे कर नहीं पाएंगे और आप कह रहे हैं कि हमने इतने प्रतिशत धनराशि बढ़ा दी है! केवल वाहवाही लेने के लिए कि हम कितने गंभीर हैं इस मामले में, इसके लिए यह केवल आंकड़ेबाजी है, निश्चित रूप से यह नहीं हो पाना है। इसमें नीचे तक जो काम होना चाहिए, वह संभव नहीं है। मैं आपके सामने बताता हूं कि यह योजना सन् 2000 में प्रारम्भ हुई थी। यह योजना कितनी उपयोगी है, आप जरा इसको देखें। सर, गवर्नमेंट का document यह बताता है कि इस योजना से कितना लाभ होना है। 'ग्रामीण सम्पर्क' के पेज 5 पर प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में आप देखिए - अनुमान है कि PMGSY के प्रभावी कार्यान्वयन से एक दशक में ही प्रतिव्यक्ति सकल घरेलु उत्पाद, GDP, में तीन गुणा वृद्धि होगी। ..... ('2t/nb' पर जारी)

NB/VK/2T/2.30

श्री विक्रम वर्मा (क्रमागत) : इस प्रकार इस कार्यक्रम के पूरा होने पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 2.3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। अब आप यह स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसकी

स्थिति यह है कि 6,000 किलोमीटर सड़क बननी है, लेकिन अभी तक केवल 2 हजार किलोमीटर सड़क ही बन पाई है। एक तरफ आप यह दावा कर रहे हैं कि हमने इतना अधिक पैसा रख दिया है, लेकिन उतना पैसा रखने के बाद भी, उस प्रोजेक्ट की स्थिति कैसी है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की यह जो एनुअल रिपोर्ट आई है, आप इसी के आंकड़े देख लीजिए कि अभी तक कुल कितनी सड़क बनी है, कितना काम हो पाया है। इसलिए मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि अभी तक कुल मिलाकर लगभग 3,42,845 गांवों को जोड़ना बाकी है। वर्ष 2000 में जब यह योजना प्रारंभ की गई थी, तब उसका टारगेट यह था कि वर्ष 2007 तक हिंदुस्तान की 500 लोगों की आबादी को एक प्रकार से बारहमासी सड़क उपलब्ध कराकर जोड़ा जाएगा। वर्ष 2004 की प्रगति के तुलनात्मक आंकड़े आप देखें, उसके बाद आज 2009 आ गया है, लेकिन 2009 तक भी वह टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। अब आपका टारगेट है कि हम 2010 तक इसे पूरा करेंगे, बाद में फिर आपने इसमें संशोधन किया कि हम इसको 2012 तक पूरा करेंगे, इसका मतलब है कि सरकार की इसके प्रति उतनी गंभीरता नहीं है, क्योंकि इतनी धीमी गति से यह काम चल रहा है। केवल बजट प्रावधान बढ़ाकर दिखाने से सड़क का निर्माण संभव नहीं है।

महोदय, अभी स्थिति यह है कि 3,42,845 गांव इसमें जोड़ने हैं और कुल 3,65,094 किलोमीटर सड़क अभी बनानी है, तब जाकर हम ढाई सौ तक की आबादी को कवर करेंगे और इसके लिए 1,32,000 करोड़ रुपए की आज भी जरूरत पड़ेगी। यह मैं आपकी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं। पहले 6,000 किलोमीटर सड़क बनानी थी, उसमें से अभी तक कुल 2,000 किलोमीटर सड़क बन पाई है, 4,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम अभी बाकी है और उसके अलावा tribal areas, hill areas तक जाना है, मुझे नहीं लगता कि वह संभव हो पाएगा। इसी प्रकार आप ऊर्जा के बारे में देख लीजिए, आपकी आर्थिक समीक्षा के पेज 225 पर आप देख लीजिएगा कि इसमें बताया गया है कि 2008-09 के दौरान विद्युत इकाइयों द्वारा किए गए विद्युत उत्पादन में 2.7 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो कि 9.1 परसेंट के लक्ष्य से काफी कम है। आपका टारगेट था 9.1 परसेंट और आपकी वृद्धि हुई है 2.7 परसेंट। अब आप पैसा मांग रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हम budget

provisions बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप पैसे की डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन जो टारगेट है, उससे आप बहुत पीछे चल रहे हैं। बिजली की यह स्थिति आपकी बनी हुई है। बजट में केवल साढ़े तीन ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is only the Appropriation Bill. बजट पर डिस्कशन हो गया है .... (व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : नहीं, मैं बजट पर नहीं बोल रहा हूं ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am just pointing it out to you. आप फिर दोबारा .... (व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : मैं यह कह रहा हूं कि जब आप पार्लियामेंट से एप्रूवल ले रहे हैं, तो आपका कोई टारगेट तो हो, टारगेट से आप कितना पीछे चल रहे हैं, कम से कम सदन को यह तो पता होना चाहिए। मैं दो-दो लाइनों में केवल कुछ प्वाइंट्स बताना चाहता हूं, जो दो-तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं केवल उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं।

आप पालिसी को देख लें। आप इलेक्ट्रिसिटी पालिसी में स्वयं अमेंडमेंट लाए, उसमें तीन चीजों का कंपोनेंट था - एक था Rural Electrification Policy, इसके लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना आप देख लें, उसमें आपके sanctioned provisions थे for access to electricity to all households by the year 2009. वर्ष 2009 तक हिंदुस्तान के हरेक गांव तक आपको बिजली पहुंचानी थी, यह आपने अपने पालिसी ड्रॉफ्ट में लिखा है। आज स्थिति क्या है, 2009 में हम कहां तक पहुंच पाए हैं, क्या हम सारे गांवों तक पहुंच पाए हैं? दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी, वह यह थी - Quality and reliable power supply at reasonable rate. अब quality and reliable power supply की ओर मैं केवल इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि केवल सरकार को पैसा दे देना, बजट दे देना काफी नहीं है। प्रोविजन करके आपने ले लिया, लेकिन आपने रूल्स बनाए, आपने पालिसी बनाई, आपने टारगेट बनाया, क्या वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं? संसद को यह जानने का अधिकार है, इसलिए मैं इन मुद्दों को ला रहा हूं कि आप Appropriation Bill के माध्यम से इतनी बड़ी धनराशि तो ले रहे हैं, लेकिन हम कितना पीछे चल रहे हैं?

फाइनेंस मिनिस्ट्री और आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वे सदन को यह बताएं कि आपके जो अपने टारगेट हैं, इनको आप कब तक और कैसे पूरा करेंगे? 2U/VNK पर क्रमश:

-NB/VNK-RG/2u/02.35

श्री विक्रम वर्मा (क्रमागत) : आप जरा भुखमरी और कुपोषण पर देखें। माननीय कोयला मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, बिजली की बात चली है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोयले की सप्लाई दे नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारा कोयला है, और भी States का अपना कोयला है, आज भी एक-दो जगह की बात आई है, कोयला हमारा है, जमीन हमारी है, लेकिन उस पर अधिकार आपका है। वहां बिजली के लिए एग्रीमेंट होता है, आप खुद बताते हैं, लेकिन आप उतना दे नहीं रहे हैं, तो फिर यह जो आपका टारगेट है कि गांव के हर household तक बिजली पहुंचे, आखिर ऐसी स्थिति में यह कैसे पहुंच पाएगी? जब तक राज्यों के साथ आपका सकारात्मक सहयोग नहीं बनेगा, उन्हें आवश्यकता के हिसाब से नहीं देंगे, तब तक आपके ये टारगेट कैसे पूरे होंगे?

आप आर्थिक समीक्षा की पेज सं. 263 को पढ़ें। आज एक प्रकार की दर्दनाक स्थिति बनी हुई है। उसके सर्वे में निर्धनतम सात राज्यों के सोलह जिलों के 75 प्रतिशत परिवारों को दो वक्त का नियमित भोजन नहीं मिलता है, यह इस रिपोर्ट में है। आज हमारी यह स्थिति है कि 29 प्रतिशत लोगों को मुश्किल से खाना मिल पाता है। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे संगठन की रिपोर्ट पर विश्वास करें, तो देश की आबादी का ऊपरी तबका अपने भोजन से जो कैलोरी प्राप्त करता है, उससे 30 से 50 प्रतिशत से भी कम कैलोरी देश की बहुसंख्यक आबादी प्राप्त करती है।

श्री उपसभापति: इससे Appropriation Bill का क्या लगाव है ..(व्यवधान).. देखिए, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं बोलिए..(व्यवधान)..

श्री विक्रम वर्मा : माननीय उपसभापति जी, जब हम आम आदमी की सरकार और आम आदमी का बजट की बात कर रहे हैं ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आपको बोलना है, तो बोलें ..(व्यवधान).. Budget Session में आपको यह बात बोलने का मौका था ..(व्यवधान).. जो आपने किया।

श्री विक्रम वर्मा : देश के अंदर भुखमरी और कुपोषण है और बाकी की स्थिति ऐसी बनी हुई है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर हम इसका उपयोग कैसे कर पा रहे हैं और इसके लिए नीचे योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है?

आज एग्रीकल्चर में देख लीजिए। जिस प्रकार से आपने टारगेट तय किया है, आज एग्रीकल्चर 52 से 54 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराता है। एक बार केवल ऋण मुक्ति कर देने से हमारा काम नहीं चल जाएगा। हमें ऋण मुक्ति के अलावा कुछ वर्ष तक यानी तीन, चार, पांच साल तक सतत् किसानों को मजबूत करने के लिए और निरंतर योजनाओं वाली बात करनी होगी, अन्यथा इस साल सूखा पड़ गया या कहीं बाढ़ आ गई, फिर वही की वही स्थिति बन जाएगी और फिर किसान कर्ज के चक्रव्यूह में पड़ जाएगा। इसलिए स्वाभाविक है कि यदि समय रहते हम बजट में कुछ इस प्रकार के प्रोवीजन नहीं करेंगे, तो कल यह स्थिति बनेगी। जैसे कि आज कुछ मुख्यमंत्रियों ने सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए मांग की है, उनके लिए कोई प्रोवीजन की बात नहीं की गई है कि उनके लिए किस प्रकार से किया जाएगा। आपने केवल यह कह दिया है कि एक मद होता है, जिसके तहत उनको दिया जाता है। अभी जो तात्कालिक परिस्थितियां सामने आ रही हैं, जिसके कारण किसान फिर नए कर्ज के चक्र में पड़ने वाला है, उसके बारे में किसी प्रकार के उपाय या किसी प्रकार के सुझाव या किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई है, अन्यथा फिर थोड़े दिन में वही की वही परिस्थिति बनने की बात होगी।

आपने बजट में यह घोषणा जरूर कर दी कि जो समय पर ऋण का किस्त चुकाएगा, हम उसको एक परसेंट कम यानी सात की जगह छः परसेंट की ब्याज पर और ऋण देंगे। पर आज स्थिति यह है कि सूखे और बाढ़ के कारण खेती की यह हालत होने वाली है तो समय पर कौन किस्त चुका पाएगा? कुछ राज्यों ने ब्याज दर कम किए, उन राज्यों को सहायता देने के बारे में इसमें कोई प्रावधान नहीं है। आपने सीधा-सीधा बजट भाषण में घोषणा कर दिया था कि हम उनके लिए छः परसेंट करेंगे, जो समय पर किस्त चुकाएगा। लेकिन जिन राज्यों ने अपने पास से इसको पांच परसेंट पर लाया, मध्य प्रदेश तीन परसेंट

पर लाया, तीन परसेंट पर और किसानों को देने वाला है, ऐसे राज्यों को सहायता देने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री उपसभापति : आपके दो सदस्य और बोलने वाले हैं और आपके बीस मिनट हो गए हैं ..(व्यवधान)..।

श्री विक्रम वर्मा : महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैंने केवल दो-तीन बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित कराया है कि जो राज्य आज वास्तव में अपने पास से और अपने संसाधन से इस प्रकार की सहायता और सुविधा दे रहे हैं, उन राज्यों को कुछ भी सहायता देने के लिए इस विनियोग में कहीं भी किसी प्रकार के कोई प्रावधान नहीं रखे गए हैं और इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि वे इस बारे में जरूर चिंता करे।

(2w/SC पर जारी)

2w/2.40/ks

श्री विक्रम वर्मा (क्रमागत) : इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अन्य चीजें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन है, उनके संबंध में मेरा बार-बार सरकार से आग्रह है कि हम बजट इसीलिए पास करते हैं या नीचे तक धनराशि इसीलिए जाती है कि हम उस सबका उपयोग करके, जो आपने टारगेट्स तय किए हैं, जो आपके अपने बजट भाषण में है, पिछले बजट भाषण में है या उसके पहले के बजट भाषण में हैं या जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, according to the policies, हम कहां तक पहुंचे हैं। इस विनियोग विधेयक के माध्यम से हमारा निवेदन है कि जो प्रमुख सेक्टर्स हैं, उन्हें देखने की आवश्यकता है। जो आपकी रिपोर्ट आयी है, उस रिपोर्ट के अनुसार आज हमारे यहां पचास परसेंट से ऊपर तीन से पांच साल के जो बच्चे हैं, वे कुपोषण की बीमारी से त्रस्त हैं। आपकी जो रिपोर्ट आयी है, यह उस रिपार्ट में है। यदि उन बच्चों की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, चिंता नहीं करेंगे तो आप कल्पना करें कि आगे क्या स्थिति होगी। महोदय, मैं आखिर में इस विनियोग विधेयक के संबंध में माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि पिछले वर्षों के कार्यान्वयन को देखते हुए, इस वर्ष जो भी धनराशि आप प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया उसके साथ यह भी देखें कि इसका कार्यान्वयन और उपयोग ठीक से हो तथा वास्तव में हम जो टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं और जो लाभ उन्हें देना चाहते हैं, उस बारे में आप जरूर ध्यान दें। धन्यवाद। (समाप्त)

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (MAHARASHTRA): Mr. Deputy Chairman, Sir, I support the Appropriation (No.3) Bill, 2009 by which, for about 105

services and purposes, certain sums from the Consolidated Fund of India have been sought under article 114(1).

In my college days, Sir, whenever Budget was presented, to know whether it was good or not, I used to read Palkhiwala's comments; if Palkhiwala opposed the Budget, I always thought the Budget must be good. That is because certain elite or people from a certain class spoke only for that class of people. He used to hold a huge meeting at the Brabourne Stadium. At that time, a commoner like me always used to conclude from his opposition to the Budget that the Budget must really have been good. Nowadays, Rahul Bajajji criticises the Budget and I immediately come to the conclusion that it must be a good Budget.

Anyway, Sir, this Budget had a human approach. Therefore, the Appropriation Bill also has that approach. The Budget was community-oriented, rather than corporate-oriented. Therefore, it has a human approach. Why I am saying this is, one, because of emphasis on infrastructure and, two, because of emphasis on social sector. But, if the emphasis on infrastructure has to succeed, then, the most important part is the implementation part. The delay that is caused in implementation of infrastructural projects is tremendous; it is criminal and it is a wastage of money in the sense that, many a time, we have to spend double the estimated amount on infrastructure because of delays. These delays occur basically on account of the corrupt attitude of those involved. Therefore, without any hesitation, the Government has to invoke all the laws of the land including the Prevention of Corruption Act for the purpose of straightening those who are involved in delaying the projects. Secondly, if officers, whoever they may be and of whatever

rank they may be, indulge in any delay or criminal negligence, then strict action must be taken under the Service Rules and those cases must be expedited and disposed of within six months. If this approach is taken and if they are aware of this approach of the Government, I am sure the infrastructure delay will be reduced to a considerable extent.

(Contd. by 2x/tdb)

TDB-MCM/2X/2.45

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (CONTD.): We know what happens in Delhi and other places. That is why, these are the instances, which I have given here. When crores of rupees infrastructure is going to come in the next few years, we have to straighten these lines for the purpose of achieving good results. Sir, because this involves funding, I would like to come to the demand of the State of Goa for a Special Category State. Recently, Sir, two days back, the hon. Finance Minister had come there, and we also acquainted him of the matter. There is a Gadgil Formula under which the distribution of funds is done. There were amendments in it from time to time, and as of today, there are eleven States to which the funds are allotted as per Special Category norms. Goa had missed two Five Year Plans. We were under the Portuguese rule for 450 years. We have to cater to international tourists to a large extent. Therefore, Goa has to be considered as the 12th State in the category of Special Category States for the allotment of funds. I am saying this because for the Special Category States, 90 per cent is grant and 10 per cent is loan. So, for a small State like Goa, this facility has to be given.

Then, Sir, as far as tax concessions are concerned, it was given to Goa for a limited period. After some time, they were taken away and the entire industries shifted to Himachal Pradesh and Uttaranchal. These industries shifted from Goa because the tax concessions in Goa were withdrawn. आप बुरा मत मानिए, लेकिन हालत ठीक है। After 2007, it was decided by the then Finance Minister and the Government of India that a level-playing field will be available; there will be no concessions. Fine, we accepted that. But, somehow, there was a pressure from your State and ultimately the extension was there and today we are in trouble.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Naik, you should have mentioned all these things in the General Budget. ...(Interruptions)... How Goa is...(Interruptions)...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, if I go technically, then I can quote every figure and then speak on that figure. There are 105 services mentioned here and my points are under that. ...(Interruptions)... Yes, Sir; I can justify that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can justify anything, but the Appropriation Bill is...(Interruptions)...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: You see the debate on the Budget. ...(Interruptions)... That is the convention that you speak on the issues in general terms also. If we start speaking on figures, the House will be empty. ...(Interruptions)... So, Sir, the question is this. Goa is a small State. We have got limited land; we have got limited population. ...(Interruptions)... We would like to protect our land. ...(Interruptions)... We would like to protect our land. Therefore, we would like to have an amendment to article 371, just as Nagaland and Mizoram have done. I

am asking for this because unless there is a constitutional backing, we cannot have a legislation to regulate land transactions. This is very vital for our growth. You may not see what is the provision for it in the Budget. Unless we do that, our land will not be protected. The same question arises in regard to migrants. I am not opposed to this thing. But, we have got a population of 14 lakh and 3,700 square metres of area. If two lakh migrant people come to Goa every year, then, how will we cope with it? Where is the infrastructure for it? We don't have power; we don't have water. So, these are the questions which should be seen from that angle.

Sir, ultimately, the officers of the All India Services who are there in Goa have to help the Government in implementing various schemes of the Budget. They have to help the Government in advising in each Department how to go about. These people of All India Services go to Goa for two years. We call them 'briefcase officers', because they just enjoy their posting there for two years, their family remains here. They would like to come here for weekend; go there on Monday, and they do things like that. They are not interested in any project of the State. They don't advise the Government properly about the various projects of the Government of India. They do it because they know that they are there for two-three years. They are not committed to the good projects of the State. They are not committed to any project being implemented by the State of Goa. They don't give any advice. Not only that, Sir. The most important task which they have to do is to bring in the schemes of the Government of India to the State. In order to bring in the schemes of the Government of India to the State, they have to study those

schemes. They have to find out what those schemes are. They don't take any initiative, Sir. Therefore, we are asking now for a special cadre of All India Services for Goa. Unless we get a special cadre, the Budget provisions for various programmes and all other programmes cannot be effectively administered.

(Contd. by 2y-kgg)

kgg/2y/2.50

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (CONTD.): Secondly, Sir, we have demanded before the Finance Minister when he came to Goa and held discussions with our Chief Minister. Our Finance Minister with our Chief Minister has announced a sea-link project from Dauna-pala to Panjim. It is a big adventure, for which we will require help from the Finance Minister. The Finance Minister was kind enough when he came to Goa to announce that he would render the necessary help to the Government of Goa in having the sea-link bridge, just like we have one in Mumbai. Though there may be less traffic on this route, but it would be a big tourist attraction for those who visit Goa.

Then, I would like to submit one or two points. As far as education is concerned, today is the world of internet, electronic medium. Those who give education on computer literacy are charged service tax. I do not think on schools who run secondary or higher secondary classes the service tax is levied. But, if a computer literacy institution educates in computers, it is charged service tax heavily. I think, the Government should reconsider and encourage such institutions. At the most, you can rate the institutions because so many

institutions are mushrooming. You can grade them and good ones can be given this facility.

Sir, as far as the income-tax is concerned, I would like to make a small suggestion. Currently, there are no time-limits prescribed for the disposal of rectification of applications for orders giving effect to appellate orders. The Act needs to prescribe time-limit for the disposal of rectification of applications for orders giving effect to appellate orders. Secondly, currently, all refunds from the Income-Tax Department are issued manually and this can be time consuming and requires constant follow up with the tax authorities.

Sir, as far as depreciation is concerned, traditional definition according to old economy for depreciation is wearing out of capital and it is not relevant to IT products as these never wear out, they just become obsolete. It is, therefore, strongly recommended that the rate of depreciation on IT products be increased to 100 per cent from the existing 60 per cent reflecting the true active life. This will indirectly subsidise the cost of ITs to the corporates by at least 14 per cent and lead to consumption of additional one million computers created in replacement and ensuring investment in cutting-age technology. This is required because they do not wear out, they just become obsolete. Therefore, depreciation concept, as far as computers are concerned, should be given rethinking. Thank you very much, Sir, for the time given.

(Ends)

SHRI MATILAL SARKAR (TRIPURA): Sir, thank you. I have some observations in regard to the Appropriation Bill (No.3), 2009. I would like to invite the attention of the hon. Finance Minister, on the observation,

to clause 3 of the Bill. It is stated that the sums shall be appropriated for the services and purposes expressed in the schedule. I will speak on clause 3 in regard to the items of the sums sought for here.

Sir, coming to the agricultural sector, we have seen in the annual report, it is stated, "The production of wheat, coarse cereals, sugarcane, pulses is decreasing year-to-year." It is decreasing. On the other hand, cash crops production is increasing. So, for the export benefit, cash crops are being produced in some areas. As a result, what happens? There is a shifting of cultivation from foodgrains to cash crops. That is why, we are becoming dependent on the other countries in regard to wheat, coarse cereals, pulses, etc.

(Contd. by kls/2z)

KLS/2Z-2.55

SHRI MATILAL SARKAR (CONTD): So, what is the aim of the Government to revive this sector so that we may not depend on import for our day-to-day food and other essential commodities? Sir, what is seen is that the import cost was about Rs.30,000 crores in the year 2008-09. If we can divert this amount to support the farmers in respect of irrigation, in respect of giving them credit flow at the rate of 4 per cent interest, as Prof. Swaminathan recommended and if we can do it, then our farmers would be able to produce more, they would be benefited and at the same time, production would go up. Why do you not reverse this? At the same time, for not doing this, what is the plight of the farmers? Sir, every year about 15,000 to 17,000 farmers are committing suicide. There are two main reasons for these suicides by the farmers. One reason is credit flow. They are not getting institutional

credit flow from the banks and other financial institutions. They are not getting it. They are rushing to the moneylenders. What about the moneylenders? The moneylenders can get loans from the banks and they are giving loans to the small farmers. So, the rate of interest is three or four times high. This way the farmers are destined to commit suicide in some areas of the country. So, care has not been taken to see how we can combat the farmers' suicides. Coming to Item No.16, PDS, Sir, our demand is that TDS should be universalised. There should be no difference in providing food and other essential commodities. Sir, what happened in the Budget? For the BPL, it has is reduced from 35 kgs. to 25 kgs. I am asking the hon. Minister whether he is advising the poor to remain half fed because you are reducing it from 35 kgs. to 25 kgs. You are giving at Rs.3 per kg., that is right but you are reducing the quantity. If somebody requires 35 kgs., for 10 kgs. how much he is spending you can easily see. Ultimately, they are not getting food at the lower cost. They are not getting it. You maintain 35 kgs. They are to pay more, more than what was necessary in the previous time. So, this is not helping the poor. Sir, price hike is one of the most important things. I am sorry to say, Sir, we have seen NDA and we have seen UPA, nobody is worried about this price hike. It is skyrocketing. What is to be done, I do not know. Sir, I am giving one suggestion. If the Government is ready to supply 14 to 15 essential commodities at the affordable rates through Fair Price Shops I can challenge that the prices will come down. I do not know whether the Government is ready to take this suggestion. They should distribute 15 or 16 items through Fair Price Shops at affordable rate. Sir, now I come

to the Item No.80 about NREGA. While discussing NREGA and the sanctioned amount that the Government has sought in the Bill, I am to mention my State, the State of Tripura. As regards the completion of the projects, we stand first. In the whole country, we stand first. As regards the quality and other things, we stand second.

(Contd by 3A)

SSS/3A/3.00

SHRI MATILAL SARKAR (CONTD.): So, I have the legitimate right to comment on NREGA affairs. Sir, here for 100 days you are not keeping provision. The provision you are keeping here comes out to be 39 to 40 days per labour. So what about the Act? The Act was for 100 days. You are not keeping provision for 100 days. Last year, we had gone up to 62 days. That is why the money was not received on time. My State is efficient enough to spend 100 days' component also. But, that was not available in time. That is the thing. Sir, my demand is that there should be 200 days. You amend the rule and make it 200 days. You are providing 100 days. What about the other days? Where will they get work? (Time-bell)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have only two more minutes.

SHRI MATILAL SARKAR: I will take five more minutes. Let me try.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I have been requesting the Members not to make it a General Budget discussion.

SHRI MATILAL SARKAR: I would like to bring to the notice of the hon. Minister one very important issue. In my State, the State Government of Tripura has taken a decision about a programme called the Urban Employment Programme for the poor of the urban areas and this is the

first of its kind in the country. It is already in force. It is called the Tripura Urban Employment Programme. The slum dwellers and other poor people living in the cities deserve benefits like NREGA scheme. They also deserve this. But, in no city in the country it is invoked. In our State we have started it and, I think, in all other cities if the Central Government takes the decision it can be spread to all other cities. Sir, only two points I have to mention about the Right to Forest Dwellers. This is a very commendable Act which we have passed. Already we have started. We have already given pattas to about 60 per cent of the forest dwellers. There was election and the rest 40 per cent we will complete. The problem is about three generations that you have mentioned in the Act. They had to give documents that they are living there for three generations. Sir, the tribal people, the primitive people did not bother for documents. They are living there. They are enjoying and making use of forest for themselves. That was the custom. If we ask for the document, from where will they give it? From the kings' period they have been living there. So, this is the thing to be followed liberally. I think, the condition should be relaxed on the point about the three generations. That should be substituted by some other suitable works. Sir, in Tripura, there are not only tribals, there are non-tribals also. Indira-Mujib Pact says that, "All those refugees who entered India prior to March 25, 1971 will be allowed to stay in India. It is clearly written in Indira-Mujib Pact. So, if you impose "three generations" that will be an injustice to those who came before March 25, 1971.

(Contd. by NBR/3B)

SHRI MATILAL SARKAR (CONTD.): So, that has to be looked into. They are refugees. They entered into forest. They managed to live there for bread and butter. They had to rush there for fear of life. They had entered into forest for fear of life at the time of partition of India. For these two reasons, the documentation criteria have to be relaxed.

The last point is about the Sixth Central Pay Commission. Sir, the Government has accepted the recommendations and implemented the same to the Central Government employees. But, at the same time, the State Government employees are not getting this benefit. Sir, the State Government employees and the Central Government employees are purchasing commodities from the same market, residing side-by-side. But, on the one hand the Central Government employees are getting the benefit of the Sixth Pay Commission and on the other the State Government employees are not getting it. So, is it not the duty of the Central Government to look after them also? The State Government may not be having money. What share are you giving to the States? Sir, in the NDC meeting, the Chief Ministers of States unanimously demanded that the share of the Central revenue should be raised to 50 per cent to the States. Now, you are giving 25 per cent or 29 per cent, not more than that and keeping the rest with you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sarkar, you have to conclude. You have taken a lot of time. Please, conclude.

SHRI MATILAL SARKAR: I am concluding, Sir.

Sir, the Report of the Sixth Pay Commission should also be implemented for the employees of the States and the money should be given to the States according to the demands.

With these words, I conclude my speech. Thank you.

(Ends)

श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद उपसभापति महोदय। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूँगा कि जो विनियोग विधेयक 2009 है, उस पर सरकार कार्य करे। विगत 60 सालों के अन्दर हर सरकार अपना विनियोग विधेयक लाती रही है और उन्हें पारित कराती रही है। Budget allocations होते हैं, उसके बाद पास कर दिए जाते हैं, लेकिन implementation बहुत ही खराब है। अगर पिछले 60 सालों में implementation सही रहा होता, तो शायद आज आम आदमी को सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान आदि समस्याओं से नहीं जूझना पड़ता। सर, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह अनुरोध करूँगा कि वे कृपया accountability की ओर ध्यान दें और यह देखें कि जो निर्णय लिए जाते हैं, जो budget allocations दिए जाते हैं, appropriation करके जो रुपए दिए जाते हैं, उनका सही उपयोग क्यों नहीं होता है और आम आदमी तक वे सुविधाएँ क्यों नहीं पहुँचती हैं।

हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की 60 प्रतिशत से अधिक जनता कृषि में लगी हुई है और हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 27 प्रतिशत है। यह असमानता ही हमारी कृषि को आकर्षणहीन बना रही है, जिसके कारण आज लोग कृषि में न लग कर इधर-उधर जा रहे हैं। भारत में विश्व की सब्जियों का उत्पादन लगभग 15 प्रतिशत है, विश्व में भारत में फलों का उत्पादन लगभग 8 प्रतिशत होता है, लेकिन 40 प्रतिशत फल और सब्जियाँ बाजार में पहुँचने से पहले ही बर्बाद हो जाती हैं। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि कृषि के जो उत्पाद हैं, उन्हें कैसे सही ढंग से बाजार में पहुँचाया जाए, जिससे हमारे किसान आत्मनिर्भर हों, किसान की आमदनी बढ़े और कैसे सरकार बिचौलियों को समाप्त करे, क्योंकि जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा, हमारे किसान के पास

पैसा नहीं होगा, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। किसानों और मजदूरों की ओर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

यह भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया है कि देश के 73 प्रतिशत किसानों की बैंकों तक पहुँच नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में उन बैंकों का लाभ किसानों को मिल रहा है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

डीजल बराबर महंगा होता चला जा रहा है। आज हालत यह है कि मानसून बिगड़ चुका है। इसके लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे इस बजट में कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

भारत निर्माण योजना, जिसे सरकार ने चार साल पहले बड़े जोर-शोर से लागू किया था, असल में उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा योजना के तहत जो लक्ष्य दिल्ली में निर्धारित किए गए थे, राज्यों तक पहुँच कर वे सब सिकुड़ जाते हैं। उनका implementation सही नहीं होता है। 2005-06 से 2008-09 तक एक करोड़ हेक्टेयर खेतों को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया था। परियोजना का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी लक्ष्य की परिधि में रखे गए किसानों को अधिकतर खेत-पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। भारत निर्माण योजना के अन्तिम वर्ष 2008-09 के जो आँकड़े हैं, अगर उसे देखा जाए, तो 9878.26 हजार हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त करना था, जिसके स्थान पर केवल 1196.777 हेक्टेयर का लक्ष्य ही प्राप्त हो सका है।

(3सी/एससीएच पर जारी)

SCH/3.10/3C

श्री महेन्द्र मोहन (क्रमागत): हम किस प्रकार अपने लक्ष्यों को पाएंगे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इम्प्लिमेंटेशन की ओर बहुत ध्यान दिया जाए। जम्मू-कश्मीर के लिए 101.55 हजार एकड़ का लक्ष्य था, लेकिन प्रगति शून्य रही। बिहार में 1699 हजार एकड़ के लक्ष्य के विपरीत मात्र 16 हजार एकड़, उत्तर प्रदेश में 977 हजार एकड़ के विपरीत केवल 377 हजार एकड़ लक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी केन्द्र का राज्यों के साथ कोई सामंजस्य नहीं रहा है। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

देश में खेती और किसानी की यह दुर्गति है, अगर स्थिति यही बनी रही तो हम आर्थिक प्रगति के 9% के आंकड़ों तक कैसे पहुंच पाएंगे? इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जल्द ही इस ओर ध्यान दिया जाए। सरकार ने यह भी कहा है कि हम खाद्य सुरक्षा के लिए एक विधेयक लाएंगे, लेकिन इसे किस प्रकार से किया जाएगा? मेरी राय यह है कि इस ओर थोड़ा तेजी से कार्य किया जाए।

विश्व की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें यह कहा गया है कि विश्व के एक-चौथाई, अर्थात् 25% लोग भारत में रहते हैं। यह संख्या 2 करोड़ 30 लाख है तथा साढ़े चार करोड़ के लगभग लोग ऐसे हैं, जिन्हें शाम का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है।

विकास में भी असमानताएं हैं। जो प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात विकास की दृष्टि से अति विकसित प्रदेश हैं, वहां पर भी भुखमरी की स्थिति ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली, जहां पर प्रतिव्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, वहां पर 26% बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं।

गरीब जनता तक सही दामों पर भोजन को पहुंचाने के लिए जो बहुत ही आवश्यक आधार है, वह है पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम के अन्दर भी बहुत कमियां हैं और हर जगह पर इसमें रुपयों का गोलमाल किया जा रहा है। पीडीएस सिस्टम के लिए जो अनाज दिया जाता है, वह खुले बाजार में बिक जाता है। दलहन अनाज की स्थिति भी यही हो रही है। यहां पर हमें देखना होगा कि किस प्रकार हम पीडीएस सिस्टम को और स्ट्रॉंग करके सही व्यक्ति तक अपने सामान को पहुंचाने की व्यवस्था कर सकें।

आज हमारा पूरा पीडीएस सिस्टम फेल हो रहा है। क्यों? सदन में कृषि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि पीडीएस सिस्टम में खामियां हैं। इसमें बोगस राशन कार्ड की समस्या है। लेकिन केवल सदन में इसकी स्वीकारोक्ति कर देने से ही बात समाप्त नहीं हो जाती है, उसका कोई हल निकाला जाए। इसी प्रकार से बीपीएल को लेकर भी एक बड़ी भारी समस्या है कि वास्तव में बीपीएल कौन है? कौन-से व्यक्ति बीपीएल में आते हैं? कृषि मूल्य नीति में कहा गया था कि खाद्य सुरक्षा नीति के तहत हर गरीब को सही समय पर अन्न की आपूर्ति की जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार गरीबी का ही निर्धारण नहीं कर पा रही है कि कौन गरीब है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए गरीबी की परिभाषा अलग है, खाद्य मंत्रालय के लिए गरीबी की परिभाषा अलग है, राज्यों में अलग है और योजना आयोग गरीबी

को अलग तरीके से परिभाषित करता है। कम से कम केन्द्र सरकार यह तो देखे कि हर जगह पर गरीबी की परिभाषाएं एक सी हो जाएं। 1990 तक पीडीएस सार्वभौमिक था और 1987-88 में सूखे के समय इसकी अहम भूमिका रही। 1997 में आप टार्गेटिड पीडीएस सिस्टम लेकर आए और इस सिस्टम में आपने बीपीएल और एपीएल दो भागों में पूरी जनसंख्या को विभाजित कर दिया, लेकिन फिर भी उसके अनुसार कार्य नहीं हो पाया।

उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने ऐलोकेशन किया है और क्या उसके हिसाब से हम आगे भी चल रहे हैं? प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में हमने 12,000 करोड़ रुपया बढ़ाया, पावर सैक्टर में हमने यह कहा कि हम कम से कम अपना 5000 मैगावाट जोड़ेंगे। ऐसा क्यों? अगर चीन एक लाख मैगावाट जोड़ता है तो हम 5000 मैगावाट की बात क्यों करते हैं? अभी कुछ समय पहले प्रश्न काल में हमारे एक प्रश्न के उत्तर में विद्युत मंत्री जी कह रहे थे कि 1 लाख 50 हजार मैगावाट का प्रोडक्शन है, केवल 15 हजार मैगावाट की कमी है। अगर केवल 15 हजार मैगावाट की कमी है, तो फिर इतनी अधिक बिजली की कटौतियां क्यों हो रही हैं? लोगों को बिजली क्यों नहीं उपलब्ध हो रही है? कहा जा रहा है कि हम राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत हर गांव तक बिजली पहुंचा रहे हैं। क्या वहां पर केवल बिजली का कनैक्शन देने से ही उन्हें बिजली प्राप्त हो जाएगी। जब तक वहां बिजली का उत्पादन नहीं होगा, जब तक बिजली नहीं पहुंचेगी, जब तक उनके घरों में बल्ब नहीं जलेंगे, तब तक ऐसे बिजली को पहुंचाने से क्या फायदा? इसी प्रकार रोड ट्रांस्पोर्ट और हाइवेज़ के अंतर्गत बहुत खराब ऐलोकेशन किया गया है। हालांकि इसके लिए बजटरी सपोर्ट दिया जा रहा है, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन उसके इम्प्लिमेंटेशन का क्या हो रहा है? जब तक उसका इम्प्लिमेंटेशन ही सही तरीके से नहीं होगा, तो क्या होगा? हम हमेशा बात करते हैं कि हम अपने यहां मालन्यूट्रिशियन को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में यह समाप्त हो रहा है? मेरा अनुरोध है कि इस ओर देखा जाए और इसे समाप्त किया जाए। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग हो। जब तक एकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि कौन अधिकारी किस काम के लिए जिम्मेदार है, जब तक उनके अन्दर यह भय पैदा नहीं किया जाएगा कि जो कार्य उसे दिया गया है, उसे उसने

समय पर पूरा करना है, तब तक कोई कार्य समय पर नहीं हो सकेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री हो, उसके ऊपर ऐक्शन हो, कार्यवाही हो और उसकी जानकारी सदन को दी जाए। जब तक इस प्रकार के कार्य नहीं किए जाएंगे, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि सरकार आम आदमी के लिए जो कुछ कार्य करना चाहती है और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, उसमें उसे सफलता प्राप्त हो पाएगी।

3d/psv पर जारी

-SCH/PSV-PB/3D/3.15

श्री महेन्द्र मोहन(क्रमागत): इसके लिए यह बहुत आवश्यक है। ...(समय की घंटी)... नरेगा की स्कीम्स के बारे में भी बहुत-सी चर्चाएँ हो चुकी हैं। सौ दिनों के कार्य की बात हो रही थी। अभी हमारे एक पूर्व वक्ता ने कहा कि जो बजट एलोकेशन है, वह केवल 30 दिनों के लिए है, तो इस प्रकार से कैसे काम होगा? हमें राज्य सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम सही करना चाहिए कि कम-से-कम जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें सौ दिन कार्य करने का मौका प्राप्त हो। अगर वह नहीं होगा, तो किस प्रकार हम देश में गरीबी को समाप्त करेंगे?

उपसभापति जी, इन सब बातों को देखते हुए और समय की बाध्यता को देखते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल यह अनुरोध करना चाहूँगा कि वह कृपया गरीबी की परिभाषा और मापदंड को तय करें जो हर विभाग के लिए एक हो। गरीबी से सम्बन्धित विश्वसनीय और पर्याप्त आंकड़े हों, जिसे राज्य सरकारों से भी वैध कराया जाए। भ्रष्टाचार दूर हो, उचित मूल्य की दुकानों की सही व्यवस्था हो, सामान को सही समय और पर्याप्त ढंग से सही रूप में गन्तव्य तक पहुँचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए, जिससे कि हमारे उत्पादकों की जो बरबादी हो रही है, वह न हो। बेघर आदिवासी और दूरदराज के इलाकों को इस व्यवस्था में विशेष रूप से शामिल किया जाए।

माननीय उपसभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी का जो उद्देश्य है, जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा या माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि वे इस देश की गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर एक अच्छा माहौल पैदा करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो

उन सबके लिए यह बहुत आवश्यक है कि इस ओर सतत कार्य किए जाएँ और ऐसा न हो कि जो सौ रुपए खर्च किए जाते हैं-- जैसा कि कहा जाता है कि सरकार के सौ रुपए में से 10 रुपए ही आम आदमी तक पहुँचते हैं और बाकी 90 रुपए भ्रष्ट अधिकारियों और इधर-उधर के बीच-बिचौलियों के बीच में बँट जाते हैं, यह चीज़ समाप्त हो और सही रूप से कार्य किए जाएँ। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि इस प्रकार के कार्यों को सही रूप से किया जाए। धन्यवाद। (समाप्त)

श्री उपसभापतिः श्री आर0सी0 सिंह। आपके पाँच मिनट हैं।

श्री आर0सी0 सिंह (पश्चिमी बंगाल): सर, मैं अपनी बात पाँच मिनट के पहले खत्म करने की कोशिश करूँगा।

श्री उपसभापतिः ठीक है। आप उतने में ही खत्म कर दीजिए, आपका धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री आर0सी0 सिंहः अगर थोड़ा आगे-पीछे हो जाए, तो आपकी थोड़ी मदद चाहिए। ...(व्यवधान)...

सर, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो बजट है, यह तो आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब महँगाई आसमान छू रही है, उस समय सरकार को जो आम लोगों को बजट में रिलीफ देनी चाहिए, उसकी जगह पर कुछ व्यक्तिगत मालिकों को बजट में छूट देने की कोशिश हो रही है। मुझे याद आता है कि बजट स्पीच के पैराग्राफ 93 में कहा गया है कि `` ... the business of laying and operating cross country natural gas or crude or petroleum oil pipeline network for description ...`` सर, इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स का जो 1961 का कानून था, उसमें एक धारा जोड़ी और उसे जोड़ कर 100 परसेंट टैक्स रिबेट दे दिया। इसमें एक विशेष कम्पनी को, रिलायंस गैस ट्रांस्पोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को, 20 हजार करोड़ रुपए की छूट दी गई, जो आम लोगों तक जा सकती थी, जिसको कि इसमें नहीं रखा गया। जहाँ हम देश के आम लोगों की बात कहते हैं, तो देश के आम लोगों की हालत यह है कि जो सबसे गरीब किसान है, जिसके पास जमीन का एक छोटा-सा टुकड़ा है, इस महँगाई के आलम में वह अपनी जमीन को बेच कर के दीन-मजदूरों की लाइन में खड़ा हो रहा है। वह

किसान से मजदूर बन रहा है। ऐसे किसान, जो हमारे देश के जी0डी0पी0 में 22 परसेंट का योगदान करते हैं, 70 प्रतिशत से ज्यादा जिनकी जीविका खेती पर निर्भर करती है, उनके लिए जो रिलीफ देनी चाहिए थी, इसमें बजट में वह रिलीफ नहीं मिल सकी है, इसमें इसे जोड़ने की जरूरत थी। इस तरह जितनी राशि उनके will share के लिए, उनकी जरूरतों के लिए देनी चाहिए थी, women के लिए, children's development के लिए, youths' affairs के लिए, उसके लिए इस बजट में sufficient प्रावधान नहीं रखा गया है, जिसको कि रखा जाना चाहिए था।

सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि लोन देने की बात जो कही गई है, इंटरेस्ट रेट 6 परसेंट उनके लिए है जो इसे टाइमली पे करेंगे, उनको रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन इस सूखे के मौसम में उनके घर में जो थोड़ा-बहुत धान बीज के लिए पड़ा हुआ था...।

(3ई/एच0एम0एस0 पर क्रमशः)

3e/3.20/hms-skc

श्री आर0सी0 सिंह (क्रमागत) : जो सूखे में चला गया, अब वे अपना टैक्स नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जो time bound relief देने की बात कही गयी है, उस की जगह उन लोगों को permanent relief देने की व्यवस्था की जाना चाहिए क्योंकि अभी प्रोडक्सन में 4.7 परसेंट की कमी आयी है और यह सूखे के चलते और बढ़ेगी। इसलिए उनको वह रिलीफ जारी रखी जानी चाहिए।

महोदय, मेरा तीसरा सवाल यह है कि वैश्विक मंदी में कंपनियों के बंद होने के चलते, Hire and Fire की नीति के चलते बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं और मंत्री महोदय ने कहा है कि वे 1.2 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। मुझे लगता है कि वह "नरेगा" की ही बात कर रहे हैं। इसलिए "नरेगा" में 100 दिन का रोजगार एक परिवार को देने के बजाय इसे बढ़ाकर 250 दिन किए जाएं ताकि वे लोग जिंदा रह सकें। महोदय, इस तरह की व्यवस्था इस बजट में की जानी चाहिए थी।

चौथी बात, इस देश का जो आम आदमी है, अभी उसे 4-5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पाती है और अधिकतर गांवों में तो बिजली है ही नहीं। महोदय, किसानों को खेती के लिए बिजली उपलब्ध नहीं है। बिजली उत्पादन को इस बजट में और बढ़ावा देने के लिए जिन materials से बिजली पैदा होती है, जैसे कोयला इत्यादि, उन्हें और मजबूती देने के लिए बजट में ज्यादा allocation किए जाने की जरूरत थी जिस से कि देश में ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती। महोदय, हम जानते हैं कि देश में वर्ष 2008-09 में बिजली उत्पादन के टार्गेट में 9.1 परसेंट की कमी थी, इसलिए इस के allocation में और ज्यादा पैसा देने की जरूरत थी।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि mines and minerals के डवलपमेंट पर भी सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे देश के लिए बहुत उपयोगी हैं। महोदय, मैं आखिरी एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। महोदय, आज जहां देश में बिजली की ज्यादा जरूरत है और उस के लिए कोयले के production की भी जरूरत है। हम विदेश से कोयला लाते हैं तो उन कंपनियों को 6 हजार टन के हिसाब से पैसा देते हैं, वहीं अपने देश में 3 हजार रुपए टन के हिसाब से payment करते हैं। मैं चाहूंगा कि बिजली कंपनियों को सरकार उसी रेट से payment करने की व्यवस्था करे।

महोदय, अभी Public Distribution System सिर्फ बी0पी0एल0 से नीचे रहने वालों के लिए है। मैं चाहूंगा कि यह सिस्टम देश में सारे लोगों के लिए लागू हो, जिससे कि आम आदमी को relief मिल सके।

महोदय, पश्चिमी बंगाल में "आइला" के चलते, समुद्री जल के प्रकोप से पूरे पश्चिमी बंगाल का उत्तर चौबीस परगना, दक्षिण चौबीस परगना क्षेत्र के लोग व हावड़ा, हुबली नदियों के किनारे के लोग बुरी तरह से affected हुए हैं। इस के प्रकोप से वहां की फसल बर्बाद हो गयी है। जो लोग वहां फूल की खेती व मछली पैदा करने का काम करते थे, उनका काम पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इसलिए उस इलाके में खारे पानी में जो फसल उगायी जा सके, इस तरह के बीज supply किए जाने चाहिए। महोदय, उन लोगों को relief देने के लिए सरकार ने 1 हजार करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है जोकि पर्याप्त नहीं है।

उनके लिए यह राशि बढ़ाकर जल्द-से-जल्द प्रदान करने की मैं आप के माध्यम से मांग करता हूं।

(समाप्त)

SHRI N. K. SINGH (BIHAR): Thank you, Sir. I am conscious that The Appropriation Bill has already been passed in the Lok Sabha and it has come to us for some broad discussions on the framework of the appropriations, which the Finance Minister has sought from us.

At this stage, Sir, I would just like to propose four or five suggestions for the consideration of the Finance Minister, which are more in the nature of institutional reform, in the manner in which expenditures are composed, expenditures are evaluated and the entire budgetary process is conducted.

Sir, my first suggestion is that the Finance Minister himself is quite conscious of the fact that large public outlays require scrutiny of the quality of these public outlays, in a manner which is concurrent and a manner which is independent. In the document which the Finance Ministry has circulated along with the Budget document, they have circulated the document on medium-term fiscal initiatives. In the fourth section of that medium-term initiative, they have proposed the constitution of an office of independent evaluator at an arm's length relationship with Government.

(Contd. at 3f by hk)

HK/3f/3.25

SHRI N.K. SINGH (CONTD.): I urge the Finance Ministry to act quickly on its own suggestion and to quickly create an office for independent evaluation so that this House can have the benefit of an evaluation from

an independent source of the quality of large public outlays for which they seek our authorisation.

My second suggestion, Sir, is that I had in this House brought to the notice of the hon. Finance Minister that the present classification of Government accounts remain in a state of colossal mess. The artificial distinction between plan expenditure and non-plan expenditure, between revenue and capital expenditure is something, which needs to be holistically visited. For instance, Sir, we are often told that it is Government's objective to bring down the revenue expenditure significantly in the next two years, but perhaps Government themselves are conscious that large devolution to States on health and education is something which comes in the revenue account and the multiplier benefits of what happens in education and health have long-term benefits for the economy and, therefore, does not automatically follow that old revenue expenditure is ab initio something which we need to curtail. So, this, Sir, requires a re-visiting of the classification of Government account. The issue of plan and non-plan is something on which this House has deliberated earlier and maybe the Finance Minister can give some thought to the constitution of a Government Reclassification Committee with the former CAG which can have expenditure and others to look into classification of Government accounts.

My third point, Sir, is that it is about time that the Ministry of Finance begins to reform itself and that the Ministry of Finance begins to reform the Reserve Bank of India. In fact, without wanting to embarrass the Prime Minister, I would certainly like to bring to the suggestion that

in many discussions and in many speeches which the Prime Minister has made on earlier occasions before he was Prime Minister, he talked and mentioned that the most unreformed institution of the Government was the Reserve Bank of India and one of the most unreformed institutions was the Ministry of Finance. Whereas the Finance Minister and the Finance Ministry have talked the paradigm of reforms to others, this is one of those things in which one can say, 'Doctor heal thyself first.' And what kind of a change on the Reserve Bank, am I suggesting? On the Reserve Bank I am suggesting two important areas of reforms. The first, Sir, is that there is an inherent conflict of interests when the Reserve Bank, apart from fixing its monetary and credit policy, is also the principal portfolio manager of the Government. It is the investment banker of the Government. There is an inherent conflict of interest between the Reserve Bank functioning as an investment manager and the Reserve Bank functioning also as a credit monitoring institution and determining the foreign exchange policy. So, that is the first area where I think there is a conflict of interest. That may entail, of course, the creation of an independent debt management office on which there is now sufficient literature and experience available.

The other area of reforms of the Reserve Bank is, all over the world people have regarded that the functions of the Central banker must not be mixed up with the functions of the Central banker doing the supervision of individual banks. All over the world, Sir, people have created an independent Banking Regulatory Authority. They have treated it an arm of the Central Banker which acts as a kind of an independent surveillance instrument to again avoid an inherent conflict of interest

between the functions which the Central Bank is asked to perform and these two functions which I have mentioned, namely, the portfolio manager function and the function of micro supervision of banking responsibility. The Ministry of Finance itself, Sir, in terms of classification of these three Departments -- Revenue, Expenditure and Economic Affairs -- needs a re-think if we are to really meet the more complex challenges which lie ahead of us in the management of our economy.

My next point, Sir, is that since the Finance Ministry is keen on moving towards greater transparency in budget-making, I would urge them to consider the adoption of the OECD Budget transparency mechanism.

(Contd. by 3g/KSK)

KSK/AKA/3.30/3G

SHRI N.K. SINGH (CONTD): What does this mechanism entail? It entails that Budget is not a surprise. It is not one fine day, when something is unravelled. It is the people, public policy makers, think tanks, and, perhaps, the Parliament is engaged more decisively in the formation of the budgetary processes. This entails my final point, that point is, Sir, to improve the quality and depth of Parliamentary oversight into the Budget-making process. All over the world, Parliaments are engaged at different stages before ideas take a final crystal shape. Would, for instance, the Finance Minister consider taking this House and having a sneak review of what the economy look like, let us say, in the Winter Session of Parliament by bringing a mid-term review paper which would you enable us to have a better grasp instead of being confronted with a surprise? Improved Parliamentary oversight, Sir, is another area where I

think the institutions need to be reformed. I brought to your notice, Sir, the need for making institutional changes, the need for some far-reaching reforms in the working of the Ministry of Finance and in the working of the Reserve Bank of India. The Finance Minister has put, by having this huge outlay, his trust in money. I hope that we can trust the money in the nature with which these large public outlays have been entailed. And, these cannot be achieved unless some of the underlying institutions are reformed more fundamentally. Thank you, Sir.

(Ends)

श्री मंगल किसन (उड़ीसा) : उपसभापति जी, आज जो एप्रोप्रिएशन का बिल आया है, इसमें भारत सरकार को total 304,32,55,88,00,000 रुपए (तीन सौ चार खरब, बत्तीस अरब, पचपन करोड़, अठासी लाख रुपए) खर्च करने के लिए व्यवस्था की गई है। आजादी के बाद से हर साल का बजट प्रोविजन तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आम आदमी को जो सुविधा या facility मिलनी चाहिए, वह कम होती जा रही है और केवल चंद लोगों को, जो ऊपर के दर्जे में हैं, उनको facilities मिलती जा रही हैं। उदाहरण के लिए 6th Pay Commission में वेतनमान का जो निर्धारण किया गया, उसमें Highest salary और lowest salary का जो गैप है, उसको कम किया जाना चाहिए था। हर गरीब, आम जनता, जो poor family से आता है, जो छोटी-मोटी नौकरी करता है, उसके लिए भी यह एक बाजार है और जो highest salary और हाई पोस्ट पर आते हैं, उनके लिए भी यह एक मार्किट या बाजार है। इसलिए यह जो इतना गैप है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए था। This gap between the highest-paid person and the lowest-paid person gap should be minimised. इसके बाद देश के आजाद होने के बाद से जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हैं, चाहे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हों, पब्लिक सैक्टर प्रोजेक्ट्स हों या माइनिंग सैक्टर प्रोजेक्ट्स हों, इन प्रोजेक्ट्स के लिए जिस परिवार ने अपना सब कुछ गंवा दिया है, जिनका displacement हुआ है, उनका अभी तक resettlement नहीं हुआ है। लगभग 5,00,000 से अधिक परिवार अभी displaced हुए हैं, लेकिन उनका अभी तक

हिन्दुस्तान में resettlement नहीं हुआ है। इसके चलते उन लोगों को शहर के किनारे या जंगल में रहना पड़ता है - उनके पास न घर है, न ठिकाना है, न ही उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए या कुछ हेल्थ सर्विस available कराने के लिए कुछ रिसोर्सिज़ हैं। इसलिए आजादी के 62 साल बाद इस Appropriation Bill में या बजट में उनके लिए कुछ resettlement करने की सुविधा देने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी।

('3h/nb' पर जारी)

GSP-NB/3H/3.35

श्री मंगल किसन (क्रमागत) : यह दु:ख की बात है कि आज तक उनके लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। हिंदुस्तान में developed States हैं और poor States हैं। जैसे उड़ीसा एक गरीब राज्य है, झारखंड एक गरीब राज्य है, बिहार एक गरीब राज्य है। इन राज्यों में रहने वाले बाशिंदों को बराबर स्तर पर लाने के लिए कम से कम बजट में स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए, लेकिन दु:ख की बात है कि जो पैदल जाता है, उसको बजट बोलता है कि जो aeroplane में जाते हैं, उनको दौड़ाओ। This is the bad economic system of the Government of India. We should rethink about it, and, if it is possible, it should be reviewed.

उपसभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि कुछ States, mineral resources में richest हैं, लेकिन economically poor हैं। उनकी जमीन बरबाद होती है, उनके परिवार displaced होते हैं, लेकिन जब mineral resources की इनकम होती है, उसको respective States को देने के लिए जो फार्मूला भारत सरकार ने बनाया है, वह गलत है। इसलिए जिस स्टेट में mineral resources हैं, उनके operation में, उनके exploitation में उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है और वे displaced होते हैं। वहां का रास्ता खराब होता है, वहां का drinking water source खराब होता है, environment hazards होते हैं, लेकिन जो respective companies और भारत सरकार है, इन सब सोशल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए उनके पास कोई solution नहीं है। इसलिए इस बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए।

इसके बाद मेरा आखिरी प्वाइंट यह है कि जो जंगल में रहते हैं - आदिवासी हैं, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ हैं, दूसरे गरीब वर्ग भी जो उस शैड्यूल्ड एरिया में रहते हैं, यह शैड्यूल्ड एरिया इतना पिछड़ा हुआ है कि जब तक आप इसे देखेंगे नहीं, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। आज भी जो primitive groups हैं, उनके बदन पर कपड़ा नहीं है, उनके खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, उनके रहने के लिए घर नहीं हैं। वे लोग हर रोज nomadic life बिताते हैं और उनकी दुर्दशा होती है। बारिश के समय उनकी हालत देखकर आप भी रो पड़ेंगे। इस तरह के जो शैड्यूल्ड एरियाज़ हैं और वहां रहने वाले जो primitive groups हैं, उनके लिए बजट में आज तक जो भी किया गया है, वह बहुत कम है। उस एरिया के डेवपलमेंट के बारे में जब भारत सरकार अच्छी तरह से सोचेगी, तभी उनको कुछ फायदा हो सकता है। आज तक जो लोग बात करना नहीं जानते थे, जो लोग एक आम आदमी को देखकर डर जाते थे, आज उनकी हालत यह हो गई है कि उन्होंने हाथ में बंदूक उठा ली है। इसीलिए भारत सरकार को उनके बारे में सोचना पड़ेगा और उनकी डिमांड भी सुननी पड़ेगी। धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Rupani. You have eight minutes.

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात) : उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जब चुनाव चल रहे थे, तब प्रधान मंत्री जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्विस बैंक में यहां के भारतीयों का जो काला धन पड़ा हुआ है, सरकार बनने के बाद, उसको हम वापस लाने के लिए तुरंत ही ठोस कदम उठाएंगे और 100 दिनों में हम कुछ न कुछ ठोस कदम अवश्य उठाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं हुआ है, प्रणब मुखर्जी की बजट स्पीच में भी इसके बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं आया है।

3J/VNK पर क्रमशः

श्री विजय कुमार रूपाणी (क्रमागत): आज हमारे यहां पूंजी की कमी है, इसके कारण हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी पूंजी वहां से आए और वह देश के डेवलपमेंट में लगे, इसके लिए पूरे देशवासी आतुर हैं और हम भी मानते हैं कि वह पैसा Swiss Bank से यहां आना चाहिए, लेकिन इस बजट में उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। सौ दिनों में से साठ दिन तो चले गए हैं, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ, अब तीस-चालीस दिन बाकी है। उसके बारे में भी आप कोई ठोस कदम उठाएं, ऐसी हमारी पहली मांग है।

आप लोगों ने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत जो वेतन में वृद्धि की है, इस वृद्धि के कारण सब राज्य सरकारों पर काफी बोझा बढ़ गया है, क्योंकि यहां सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, तो natural course में सभी राज्यों के कर्मचारी वही डिमाण्ड कर रहे हैं और ज्यादातर राज्य सरकारों ने उसके बारे घोषणा भी कर दी हैं कि छठा वेतन आयोग लागू होगा, लेकिन राज्यों की जो रेवेन्यू इनकम है, वह बहुत कम है, इसलिए सभी राज्यों को छठा वेतन आयोग लागू करने के लिए पैसे की मदद मिलनी चाहिए, ऐसी भी हमारी मांग है।

अब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच टका महंगाई भत्ता बढ़ने का समय आ गया है। 01.07.2009 से 22 टका डी.ए. मिलता है, वह 27 टका मिलना चाहिए। यह केन्द्रीय कर्मचारियों का डिमाण्ड है, इसलिए उनका डी.ए. पांच टका बढ़ना चाहिए, इसलिए हमारी जो मांग है उसको स्वीकार करके केन्द्रीय कर्मचारियों को पांच टका डी.ए. मिलना चाहिए।

आज सुबह प्रश्न काल में भी विद्युत की चर्चा हुई थी। जो देश में infrastructure बढ़ाने की बात है, उसमें उर्जा सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एनडीए की सरकार में तय हुआ था कि 2009 तक हर घर में बिजली होगी, हर गांव में तो होगी, लेकिन हर घर में भी बिजली होगी। लेकिन पिछले पांच वर्षों में यूपीए सरकार को बिजली का जो उत्पादन बढ़ाना चाहिए था और जिस काम को 2009 में पूरा करना था, अब वह आप 2012 की बात कर रहे हैं। गुजरात में हमने 17 हजार गांवों में without interruption तीन फेज बिजली दे दी है। साठ साल की आज़ादी के बाद पूरे देश की यह पहली आवश्यकता है कि हर गांव

और हर घर में बिजली हो। इसके बारे में अच्छी तरह से प्रावधान नहीं किए गए हैं। हम अभी भी जो बात कर रहे हैं कि 2012 में होगी, लकिन जो बीपीएल कार्ड रखते हैं, उनके घर में मुफ्त बिजली मिलेगी और बीपीएल में भी जो criteria था, वह भी कम कर दिया है और बीपीएल की जो वास्तविक संख्या है, उससे कम दिखाई जा रही है। जब तक real में बिजली नहीं पहुंचेगी, तब तक हमारा विकास अधूरा रहेगा और हम बिजली के आधार पर जो बाकी सब समृद्धि लाना चाहते हैं, वह नहीं ला पाएंगे और "गरीबी हटाओ" जो कार्यक्रम है, उसको भी हम अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए और बजट में इसके लिए रकम की व्यवस्था रखनी चाहिए। जो बिजली का generation यानी power manufacturing है, वह भी हम अच्छी तरह से करें और तुरंत यानी 2010 तक हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली होनी चाहिए, उसके लिए भी बजट में प्रावधान ठीक से रखना चाहिए।

हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं कि प्रत्येक गांव में डॉक्टर जाए, यह हमारी कल्पना है और जब तक डॉक्टर गांव में नहीं होगा, वहां उनकी सुविधा नहीं मिलेगी ..

(3k/MP पर जारी)

MP/3K/3.45

श्री विजय कुमार रूपाणी (क्रमागत) : दवाइयां भी नहीं रहेंगी। जब डॉक्टर होंगे, तो वे वहीं रहेंगे। इसलिए डॉक्टर्स के लिए जो फैसिलिटी देनी चाहिए, वह तो स्टेट गवर्नमेंट का विषय है, लेकिन उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि डॉक्टर्स को भी गांव में अच्छा घर मिल सके, उनको रहने की अच्छी सुविधा हो, डॉक्टर्स को वहां रहने की इच्छा हो, ऐसा प्रोविज़न जब होगा, तभी प्रत्येक गांव में डॉक्टर्स रहेंगे और तभी प्रत्येक गांववासी को उनकी सुविधा मिलेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि इसके लिए कुछ न कुछ प्रोविजन हमें रखना चाहिए। साथ ही आज जो आवश्यकता है कि प्रेग्नेंट माताएं और नवजात शिशुओं की जो मृत्यु दर है, उसको कम करने के लिए वहां ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। "चिरंजीवी योजना" जैसी योजनाएं वहां लागू करनी चाहिए और प्रत्येक गांव में उनकी व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, हमारे गुजरात की बात करें, तो शिप ब्रेकिंग का हमारे यहां बहुत बड़ा बिजनेस चलता है और भावनगर में अलंग उसके लिए मशहूर है। वहां बाहर से जो शिप

आते हैं ब्रेकिंग करने के लिए, उस पर पांच टका इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसे ज़ीरो परसेंट करना चाहिए। बहुत सालों से हम लोग यह डिमांड कर रहे हैं और पूरे विश्व का शिप ब्रेकिंग बिजनेस हमारे देश में तभी बढ़ सकता है, जब उसकी ड्यूटी हम ज़ीरो परसेंट करेंगे।

दूसरे, गुजरात और महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव बैंक चलते हैं, वहां पिछले पांच साल से, माननीय चिदम्बरम जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब से उन कोऑपरेटिव बैंकों पर इनकम टैक्स लगाया हुआ है, उसको वापस लेना चाहिए। महोदय, गांवों में और शहरों में कोऑपरेटिव्ज़ को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी जी की जो कल्पना थी, उसके कारण वह कोऑपरेटिव्ज़ का बिजनेस चलता है, इसलिए उसे प्रॉफिट मेकिंग संस्था के तौर पर नहीं देखना चाहिए,। वह कोऑपरेटिव मूवमेंट आगे बढ़े, इसलिए इनके बैंकों पर भी जो इनकम टैक्स लगाया गया है, वह वापस होना चाहिए। इसके साथ ही हमारी डिमांड है कि पूरे देश में Evening Courts होने चाहिए। आज सभी courts में बहुत सारे केसेज़ पेंडिंग हैं, इसलिए पूरे देश में Evening Courts चलाए जाने चाहिए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ डिपार्टमेंट initiative ले, उनके लिए बजट प्रोविज़न करे, ऐसी हमारी डिमांड है।

(समाप्त)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): माननीय उपसभापति जी, आज एप्रोप्रिएशन बिल को इस सदन में विचारार्थ और रिटर्न करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। वैसे तो जनरल बजट की बहस में माननीय वित्त मंत्री जी ने जवाब दे दिया है, लेकिन फाइनेंस बिल इस हाउस में पुन: डिसकशन के लिए आएगा। तब उसमें चर्चा होगी और फाइनेंस मिनिस्टर उसका जवाब देंगे।

महोदय, विभिन्न मंत्रालयों की डिमांड्ज़ के सिलसिले में भी अलग-अलग मंत्रालयों के लिए माननीय सदस्यों ने जो भी queries उठाई थीं, उनके जवाब प्रस्तुत कर दिए गए हैं। आज इस चर्चा में आठ महानुभावों ने अपने विचार रखे हैं। मैंने सबको ध्यानपूर्वक सुना है, सबको नोट किया है और भारत सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें माननीय सदस्यों ने यह अपेक्षा की है कि उनका इंप्लिमेंटेशन सही हो। बजट पिछले सालों से ज्यादा रखा गया है, अच्छी बात है, लेकिन उसका इंप्लिमेंटेशन सही हो, डिलीवरी सिस्टम सही हो और अंतिम व्यक्ति जिसके लिए वह है, उसको उसका लाभ पहुंचे - उनकी

इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन साथ ही मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि विभिन्न मंत्रालय इन योजनाओं को अपनी गाइडलाइन्स के द्वारा चला रहे हैं और राज्य सरकारें उनको इंप्लिमेंट कर रही हैं।

(3L/SC पर क्रमशः)

-mp/sc-vkk/3.50/3l

श्री नमो नारायण मीणा (क्रमागत) : लेकिन फिर भी बीच-बीच में हम लोग और सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं। मैं स्वयं भी जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाता हूं तो लोगों से तरह-तरह की शिकायतें मिलती हैं कि implementation में कहीं न कहीं कोई कमी है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए - सब मंत्रालयों को भी करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी करना चाहिए। इस बार हमारी सरकार ने, delivery mechanism सही हो और implementation सही हो, उसके प्रयास किए हैं। रोज़गार गारंटी के लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ombudsman नियुक्त करने की बात कही गयी है ताकि भ्रष्टाचार की जो शिकायतें होती हैं, उनका तुरंत हल किया जाए और ये योजनाएं सही तरीके से चल सकें। श्री एन.के.सिंह साहब ने कई रिफॉर्म्स के बारे में सुझाव दिए हैं। जैसे scrutiny of the outlays - यह बात बिल्कुल सही है कि जो भी outlays हैं उनकी scrutiny हो। क्या दिया गया, क्या खर्च किया गया, क्यों नहीं खर्च हुआ, यह देखा जाए। इसके साथ ही classification of Government accounts, reforms in banking in general and Reserve Bank in particular और adoption of transparency in Budget-making. ये सब अच्छे सुझाव हैं। इन पर हमारा मंत्रालय विचार करेगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य सदस्यों ने कई सुझाव दिए। मैंने सब नोट किया है। आपने रोज़गार गारंटी के बारे में सुझाव दिए हैं, प्रधान मंत्री सड़क योजना के बारे में सुझाव दिए हैं, विद्युत उत्पादन के बारे में, पीडीएस के बारे में, अकाउंट्स और रिटर्न्स के बारे में सुझाव दिए हैं। इसी प्रकार NREGA के बारे में, Sixth Pay Commission के बारे और सिंचाई के लक्ष्य पूरे करने के बारे में भी सुझाव दिए गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सब पर कार्यवाही होगी और फाइनेंस बिल आपके बीच में आ रहा है, उसमें आप

लोगों के और महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए जाएंगे। उपसभापति महोदय, इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको consider करके return करने का काम करें।

(समाप्त)

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, रूपाणी जी ने गवर्नमेंट इम्प्लाइज़ को पांच परसेंट डीए

..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2009-10, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I beg to move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

(Ends)

SHORT DURATION DISCUSSION ON INCREASING OBSCENITY AND VULGARITY IN TELEVISION PROGRAMMES BEING SHOWN ON DIFFERENT CHANNELS AGAINST CULTURAL ETHOS OF THE COUNTRY

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up Short Duration Discussion on the increasing obscenity and vulgarity in television programmes being shown on different channels against cultural ethos of the country. Shri Ravi Shankar Prasad.

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, आपने इस अति लोक महत्व के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। अपनी टिप्पणी आरम्भ करने के पहले मेरे जेहन में एक सवाल उठता है कि मैं किस हैसियत से बात करूं।

एक माननीय सदस्य : फॉर्मर मिनिस्टर की हैसियत से।

श्री रवि शंकर प्रसाद : इस हाउस में अम्बिका सोनी जी हैं जो अभी I&B मिनिस्टर हैं, Leader of Opposition अरुण जेटली जी हैं, वे भी I&B मिनिस्टर रह चुके हैं और मैं भी I&B मिनिस्टर रहा हूं। हम तीनों में एक और समानता है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। अम्बिका सोनी जी भी पहले मीडिया को सुनाती रही हैं, सुनती रही हैं और झेलती भी रही हैं। अरुण जी का भी बहुत व्यापक अनुभव है, लेकिन इस सबके साथ-साथ हम सभी सांसद हैं।

(3एम-एमसीएम पर क्रमागत)

MCM-RSS/3M/3-55

श्री रवि शंकर प्रसाद (क्रमागत) : और हम सभी की एक व्यापक जवाबदेही भी बनती है देश के प्रति, समाज के प्रति। संविधान के छात्र के रूप में मैं प्रेस के अधिकारो को समझता हूं और जब मैं प्रेस की बात करता हूं, मीडिया की बात करता हूं, टी0वी0 की बात करता हूं, तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि भारत में इसका बहुत जबर्दस्त विकास हुआ है। We are indeed proud of the great growth of media and television in India. माननीया अम्बिका जी, अगर नए आंकड़े होंगे तो मुझे बताइएगा, यह 2005-2006 की रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर की रिपोर्ट हैं, जहां तक लगभग मुझे याद है, उसके बाद कोई सर्वे हुआ हो तो बताइएगा। इस देश में लगभग साढ़े बासठ हजार रजिस्टर्ड न्यूज पेपर्स हैं -पीरिओडिकल, वीकली और डेली, जिनकी टोटल रीडरशिप 18 करोड़ है। अगर 5 लोग पढ़ते हैं तो लगभग देश के 60-70 करोड़ लोग प्रिंटेड मेटीरियल्स पढ़ते हैं। लगभग 2130 न्यूज पेपर्स हैं Again correct me if I am wrong. You are the best person to do so. और लगभग आठ करोड़ अठासी लाख लोग डेली न्यूज पेपर विभिन्न भाषाओं के पढ़ते हैं।

(उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0जे0 कुरियन) पीठासीन हुए)

हिन्दी के न्यूज पेपर के जानने की मैं जो कोशिश करता हूं, लगभग 712 हिन्दी के न्यूज पेपर हैं, जिनकी रीडरशिप साढ़े सात करोड़ है। अगर हम टेलीविजन की बात लें, तो देश के आसमान में लगभग 325 चैनल घूम रहे हैं। Their signals are there. Correct me if I am wrong. This is what I have heard. All the more good, 480. लगभग 175 हम डाउनलोड करते हैं By the satellite principles and guidelines which we follow. मंत्री महोदया, मुझे फिर करक्ट करिएगा, जहां तक मेरी जानकारी है कि इस देश में 24 घंटे विभिन्न भाषाओं में 45 न्यूज चैनल्स हैं। अब आपने और दिया होगा तो बताइएगा। उपसभाध्यक्ष जी, इस देश में 11 करोड़ टेलीविजन होम हैं -सेटलाइट, केबिल, दूरदर्शन चैनल और अगर एक टी0वी0 5-6 लोग देखते हैं तो इस देश के लगभग 65-70 करोड़ लोग टेलीविजन देखते हैं। अब जो नया डायरेक्ट-टू-होम आया है, उसकी रेंज क्या है शायद उसकी गणना अभी नहीं हुई है। We are very newsy people Television entertainment is rising very fast. और एक नया सिस्टम निकला है No news is local news. जो पहले आधे घंटे एक जिले का न्यूज है, वह दूसरे आधे घंटे में स्टेट का न्यूज बनता है और वह तीसरे आधे घंटे में कंट्री का न्यूज बनता है, और अगर उसमें कंटेंट है तो इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है। जब मैं आज संसद में बोल रहा हूं तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि हम प्रेस की आजादी के पूरे समर्थक हैं। मेरी पार्टी कमिटेड है दी फ्रीडम ऑफ प्रेस, मैं व्यक्तिगत रूप से भी हूं। प्रेस को इस बात का अधिकार है कि वह हमारी आलोचना भी करे और हमें उस आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र है तो हमें आलोचना करने के अधिकार को देना पड़ेगा। कभी-कभी उनके अन-कंवेंशनल तरीकों पर हमारी आपत्ति होती है, वह चर्चा का विषय आता है। उन्होंने कई एम0पीज0 के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया, जिन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे थे। लेकिन मैं इसके पॉजिटिव आस्पेक्ट को देखता हूं, उपसभाध्यक्ष जी, कि यही संसद है जिसने उस अवसर का उपयोग करके अपने उन 11 एम0पीज0 को एक्सपेल किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टीट्यूशनली वेलिड माना है। तो अगर मीडिया हमारी कमजोरियां दिखाता है तो हमको उसका सम्मान भी करना चाहिए। इसलिए मूलतः प्रमाणिक रूप से भारत में जो टेलीविजन

का विरोध हुआ है We need to be very proud of that. उपसभाध्यक्ष जी, एक शब्द है - Freedom of media, दूसरा शब्द है right of creativity, तीसरा शब्द है obligation towards society. इनके बीच में क्या रिश्ते हों?

(3n/GS पर क्रमशः)

MKS/GS/3N/4.00

श्री रवि शंकर प्रसाद (क्रमागत) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपने मन में एक सवाल पूछता हूं कि समाज, सरकार, संसद, सर्जना और सेंसर, इसके बीच में क्या रिश्ता हो ? यह सवाल एक लोकतंत्र में हमेशा उठता है। उपसभाध्यक्ष जी, मेरी समझ यह है कि सेंसर की सुई इस प्रकार से नहीं चलनी चाहिए कि सर्जना की सरिता सूख जाए। इसके साथ ही, इतना आवश्यक यह भी है कि सर्जना का अधिकार इतना उच्छृखंल नहीं होना चाहिए कि संस्कारों के सरोवर गंदे हो जाएं। यह basic bench-mark है। Censor should not kill creativity, and the Right of Creativity should not be so irresponsible that it pollutes the time-tested propriety. यह मौलिक बिंदु हमको समझना पड़ेगा, जो बहुत आवश्यक है। लेकिन कई बार लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण हो जाता है। उपसभाध्यक्ष जी, अब उसका निदान कौन करेगा, बात यहां पर आती है। मैं बहुत प्रमाणिकता से महसूस करता हूं कि सरकार की भूमिका इसमें बहुत कम होनी चाहिए। We need to respect the freedom of the media and the Right of Creativity, and the Government should have a minimum role. लेकिन समस्या तो है और जब हम संसद में हैं, अगर देश यह चिंता करता है, तो हमें इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा, इसका क्या उत्तर होगा ? इसके पीछे समस्या क्या है ? मैं कुछ बातें आज खुलकर कहना चाहता हूं - मीडिया से भी, क्योंकि मीडिया के लोग हमारे मित्र हैं। आप गलतियों को जरूर निकालिए, लेकिन एक sting operation हुआ एक टीचर अरोड़ा के साथ। उस sting operation के बाद हमने उसको पिटते हुए देखा है। बाद में मालूम हुआ कि वह पूरा sting operation गलत था। क्या हम उसके सम्मान को रेस्टोर कर सके ? यह सवाल कहीं न कहीं उठाना पड़ेगा ? हम उसकी कितनी बड़ी क्षति कर गए, उसकी पूरी प्रतिष्ठा को, सम्मान को, His entire reputation stands completely destroyed before his pupils, before

his students, and also before the society. उपसभाध्यक्ष जी, एक कार्यक्रम गुड़िया का था। यह एक चैनल पर आया था। वह मुस्लिम समाज से आती थी। उसका पति शायद गायब हो गया था। उसकी दूसरी शादी हो गयी थी। बाद में उसका पति वापिस आ गया। उसकी शादी का असर क्या है, यह चर्चा में आ गया। अब एक चैनल उसका इंटरव्यू ले रहा है और अब वह बड़ा विषय बन गया। मुझे मेरे पत्रकार मित्रों ने बताया कि बाकी चैनल वाले उस चैनल के यहां पहुंच गए, कुछ लोग एफ.आई.आर. कर रहे हैं कि हमको भी गुड़िया मिलनी चाहिए, क्योंकि इस गुड़िया को हम भी दिखाएंगे। आप उस औरत की मानसिक परेशानी को समझिए। How she feels? मुझे याद है कि पटना में हमारे कुछ मित्रों ने धरना-प्रदर्शन में बंद कर रखा था और दानापुर के पास, तारिक अनवर जी, आपने वह कहानी देखी होगी, एक महिला डिलिवरी के लिए जा रही थी और बंद के कारण उसकी डिलिवरी सड़क पर ही हो गई। अब सुबह से शाम तक उस बेचारी महिला की तस्वीर, आपको कैसा लग रहा है, It was down right atrocious; I have not the slightest doubt in saying that. यह क्यों होना चाहिए, यह कब तक होना चाहिए ? ये बड़े सवाल हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, जहां एक ओर मैं इस देश के टेलिविज़न के इंटरटेनमैंट और मीडिया की तारीफ करूंगा कि इसने देश में बहुत अच्छे काम किए हैं। आज लोग इंटरटेनमेंट को एप्रिसिएट करना सीख गए। मुझे याद है, मैं टेलिविज़न की डिबेट में जाता हूं, जयन्ती और अभिषेक हैं, हां, अभिषेक आज हैं, आज आपको मैं बहुत दिन के बाद देख रहा हूं। उपसभाध्यक्ष जी, पहले जब हम टी.वी .डिबेट के लिए जाया करते थे, आपको याद होगा, तो हम लोगों की कोशिश होती थी कि हम लोग दूसरे को बोलने नहीं दें, सिब्बल साहब भी हैं, He has also been an equally important face on television debates. लेकिन देश ने हमसे अपेक्षा की कि आप civilised debate करिए, अपनी पारी का इंतजार करिए और आहिस्ता-आहिस्ता आज देश में हर टेलिविज़न की डिबेट का स्तर बढ़ा है।

(3ओ पर जारी)

श्री रवि शंकर प्रसाद (क्रमागत) : उसी प्रकार से जो प्रोग्राम्स के कंटेंट हैं, उनका भी असर बढ़ा है। अगर कोई प्रोग्राम पूअर होता है, लोग उसको लाइक नहीं करते हैं, लेकिन महोदय, दिक्कत कहां आ रही है, यह बहुत समझने की जरूरत है। दिक्कत यहां आती है कि क्या बिकता है, क्या चलता है, क्या लोग देखना चाहते हैं? अब सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों होता है? मुझे याद है, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, जो टेलीविजन के कॉरिस्पोंडेंट थे। वे पॉलिटिकल इस्यूज को कवर करते थे। उन्होंने मुझ से कहा कि रवि जी, मैं दो सपेरों को लेकर आगरा गया था, क्योंकि मुझे दो सांप खोजने थे, जो साथ-साथ नांचते थे। मैंने कहा कि आपको क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि क्या बोलूं, आजकल यही बिकता है, इसलिए खोज कर रहा था। उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चिंता यही है और इससे बड़ा सवाल यह उठता है, लोग कहते हैं कि ये लोग देखना चाहते हैं। इसके साथ यह सवाल उठता है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं? आपको किसने यह अधिकार दे दिया कि देश क्या देखना चाहता है और इसकी सही समझ आपको ही है। They are important issues. We need to understand them. महोदय, जो मैंने समझा है, वह यह है कि इस पूरे घालमेल के पीछे जो एक सबसे बड़ी परेशानी है, वह है TRP की राजनीति, the politics of Television Rating Points. जो आज सबसे अधिक अन-साइंटिफिक तरीके से हो रहा है। कोई कहता है कि हमारा चैनल सबसे बड़ा तेज़ चैनल है, तो कैसे है? आज की TRP में हमारा प्वाइंट ऊपर है, तो दूसरा कहता है कि उनकी TRP का प्वाइंट एक बजे तक ऊपर था, तीन बजे के बाद हम ऊपर चले गए हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस हाउस को बड़ी नम्रता से यह बताना चाहता हूं कि The greatest fraud is being played on the country in the management of the TRP; and I say so with full sense of responsibility. यह देश कोई 110 या 112 करोड़ का है। यहां एक या दो प्राइवेट एजेंसीज हैं। उन्होंने कहां से यह अधिकार प्राप्त कर लिया और देश में कुछ हजार मीटर्स रख लिए तथा कुछ शहरों में रख दिए। बस, उनको यह मोनोपली मिल गई कि हम यह तय करेंगे कि इनकी रेटिंग A है और इनकी रेटिंग B है। जब आपकी रेटिंग अच्छी होगी, तो आपको विज्ञापन मिलेगा। रेटिंग अच्छी करने के लिए आई बॉल चाहिए। आई बॉल करने के

लिए बस, यही बिकता है। This is the whole unfortunate nexus.मुझे मालूम है कि हमारे टेलीविजन में काम करने वाले एक से एक अच्छे लोग हैं। हमारे न्यूज़ चैनल्स में एक से एक अच्छे लोग हैं, जो देश को यह बताना चाहते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है तथा देश कहां उलझ रहा है? उनके पास इसकी एक से एक स्टोरी है, लेकिन उनसे कहा जाता है कि आपकी स्टोरी बिकती नहीं है, क्योंकि इसमें TRP नहीं है। That is the real problem. उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे आज तक याद है कि एक चैनल का एक कार्यक्रम था कि इस देश के दलितों की स्थिति कैसी है? I remember that programme, a five-day programme, on the rights of our oppressed people, one symbol. उत्तर प्रदेश के किसी गांव की कहानी थी कि वह दलित साइकिल से आ रहा था और एक घर के सामने वह साइकिल से उतर गया। He would ride on that cycle even after 60 years of independence. जब वह उस घर को पार कर जाएगा फिर वह साइकिल चलाएगा। यह एक इतना रचनात्मक शोर्ट था, हमने कहा कि यह उन्होंने देश की एक बहुत बड़ी समस्या को किस तरीके से उठाया है। मुझे मालूम है कि हर चैनल में बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, लेकिन बिकता नहीं है। सर, आज सबसे बड़ी बात इस देश को सोचनी है, संसद को सोचनी है और मंत्री जी मैं इस पर आपका उत्तर चाहूंगा कि What steps are you taking to undo this wholly non-transparent TRP business going on in this country? What is their accountability? Who has created it? What is their legal sanctity? All these things are required to be taken note of. मैं बिहार से आता हूं और कई लोग बंगाल से आते हैं तथा यहां पर असम से भी लोग हैं। वहां पर एक भी डिब्बा नहीं है। यदि पटना में दो-तीन मिल जाएं तो बड़ी गनीमत होगी। ...(व्यवधान). उत्तर प्रदेश का वही हाल है, कांशी में नहीं है, असम में नहीं है और लखनऊ में नहीं है, लेकिन मुम्बई में होगा, दिल्ली में होगा क्योंकि विज्ञापन का सारा केन्द्र मुम्बई है, दिल्ली है। यहां पर विज्ञापन बनते हैं। यदि विज्ञापन चलाना है तो आई बॉल चाहिए। यदि आई बॉल चाहिए तो दिखाना है।

(क्रमश: 3P/LP पर)

श्री रवि शंकर प्रसाद (क्रमागत) : यह वेस्टेड नेक्सेस बन गया है। मंत्री जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मैंने साफ कहा है कि मैं किसी सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं हूं, But it is high time you should have a law, have an autonomous regulator to determine the TRP of all the channels in the country by a proper support of law and we are willing to support you. यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज देश में हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान में इतने चैनल्स हैं। उनका रेट ऑफ ग्रॉथ फिफ्टीन परसेंट है We are proud of that growth. आज हिंदुस्तान के टेलीविजन के अच्छे प्रोग्राम वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्राम्स में आते हैं। इसके बारे में ईमानदारी से सोचना पड़ेगा और देश को फैसला करना पड़ेगा कि एक ऑटोनॉमस रेग्युलेटर हो, उसमें मीडिया के भी लोग रहें, वे लोग न्याय हित में हों, वे टी.आर.पी. तय करें। मैं सोचता हूं कि यह पूरी TRP मंथ टू मंथ तय होनी चाहिए, प्रोग्राम वाइज, डे वाइज और ऑवर वाइज नहीं तय होनी चाहिए। This creates the biggest vested interest. हम चाहेंगे कि आप इस दिशा में कुछ प्रामाणिकता से फैसला करें। एक और समस्या है.. (व्यवधान)..आप मुझे पांच मिनट का समय दीजिए, बड़ी कृपा होगी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। एक विज्ञापन की समस्या है। माननीय अंबिका सोनी जी, आपका जो रूल है, आपको याद होगा कि केबल कंडक्ट्स रूल के अंतर्गत आप एक घंटे में सिर्फ बारह मिनट का विज्ञापन दिखा सकते हैं। आपको पता है कि विज्ञापन कितनी देर दिखाया जाता है। अकसर विज्ञापन का जो मामला है - मुझे याद है, मैं उन दिनों पद पर था, दो-तीन विज्ञापनों को लेकर बहुत चिंता हुई। वह मैने नोटिस किया, उन्होंने कहा कि एडवरटाइजमेंट कौंसिल, उनकी एक अंदर की बॉडी है, वह इसे देखती है। जब यह विषय अखबार में आया तो एडवरटाइजमेंट कौंसिल के एक अवकाश प्राप्त सचिव ने मुझे पत्र लिखा कि मंत्री जी, एडवरटाइजमेंट कौंसिल कुछ नहीं करती। जब तक वह नोटिस करती है, जवाब आता है, तब तक विज्ञापन का एक साल का कोर्स खत्म हो जाता है। Some of the advertisements are very good. जो मुझे सबसे ज्यादा भाता है, वह एक फोन कंपनी का विज्ञापन है, जिसमें एक छोटा कुत्ता, एक छोटी लड़की के साथ होता है, यह हाइट ऑफ क्रिएटिविटी है। उसके साथ ही साथ कितने

भद्दे विज्ञापन आते हैं, जो भारतीय महिलाओं के प्रति कितना बड़ा अन्याय है, मैं उनके लिए शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। इन विज्ञापनों में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। मंत्री जी आप जानती होंगी कि It is plain and simple commerce to promote good. इसलिए उसके बारे में जरूर विचार करना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष जी, मुझे आपसे दो-तीन बातें और कहनी हैं। यह जो ऑब्सेनिटी की बात करते है, समय बदला है तो हमें समय के अनुसार बदलना पड़ेगा, जैसे इस देश में लगभग सिक्स्टी परसेंट से प्लस यूथ हैं। यूथ हैं तो उनके पांव थिरकेंगे और संसद में बैठकर हम कभी यह न सोचें कि हम नौजवानों को उनके पांव थिरकने से रोकेंगे, लेकिन इससे बड़ा एक और विषय है कि यह देश क्या सोचता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1995-96 के दशक में हिंदी फिल्मों में डबल मीनिंग वाले गानों को लिखने का एक चलन हो गया था। वे गाने इतने फूहड़ हैं कि मैं उनको सदन के पटल पर रखने की हिम्मत नहीं कर सकता हूं। अच्छे-अच्छे गीतकार इंदीवर सरीखे गीतकार भी खटिया सरका रहे थे, ऐसे गाने लिख रहे थे। उसी समय जावेद अख्तर साहब ने 1942, ए लव स्टोरी में एक गाना लिखा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, It was the height of romantic creativity. वह गाना देश में लोकप्रिय हो गया। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि पूरे देश में लोग इसे गुनगुना रहे थे। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि यही हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान के सही मर्म को समझना जरूरी है। मैं आजकल देखता हूं कि नए प्रोग्राम आते हैं, नए टी.वी. आते हैं, नया चैनल आता है तो कहते हैं कि आप हमारे यहां रामायण देखिए, दूसरा चैनल कहता है आप हमारे यहां कृष्ण देखिए, उनकी टी.आर.पी. बढ़ती है, विज्ञापन भी मिलता है। एक चैनल अपने यहां मीराबाई को दिखाने की कोशिश कर रहा है, लोग देख रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में spiritual चैनल्स आए हैं, उनकी रेटिंग कितनी बड़ी है। आज रामदेव बाबा योग दिखाते हैं, उनकी रेटिंग कितनी बढ़ी है, लेकिन होता क्या है कि टेलीविजन की पूरी डिबेट has gone haywire. आप कभी सार्थक चर्चा भी कीजिए तो आप मीडिया के राइट को कंट्रोल कर रहे हैं, आप फ्रीडम ऑफ प्रैस को कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे ख़याल से यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से अपने मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि हम उनके पूरे अधिकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब हम संसद में बैठते हैं तो हमारी जवाबदेही देश

के प्रति बनती है। हो सकता है कि आज मेरी कई टिप्पणियां तीखी लगी होंगी, हो सकता है कि शाम को कई चैनल्स पर मेरा चेहरा दिखाया जाएगा, लेकिन शायद मेरी जवाबदेही देश के प्रति भी बनती है और अगर हमारी मीडिया के मित्र, एंटरटेनमेंट के मित्र उस जवाबदेही को समझेंगे तो मैंने चिंतन के लिए जो बात कही है, वे उसका स्वागत करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

(rg/3q पर आगे)

RG/4.15/3Q

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (TAMIL NADU): Sir, on this particular topic of media and its self-control, I would like to say that as a democratic country, we are giving a lot of freedom to the people as well as the media. The survival of democracy is in the hands of the media. The media has to impart proper knowledge to the people. If they understand the people's mood, and if they work on what is needed for the country, then, the country will develop. But, taking advantage of the freedom, which is given in the Constitution, and interpreting article 19 (2), that freedom of expression allows everybody to say whatever they like. It would then mean there should be a law to curtail it. But the laws, which are available with us now, are very vague in every respect. If we look at Sections 292 and 293 of the Indian Penal Code, it gives a lot of exemptions, justifiably for public good; for example, those in the interest of science, literature, art of learning, or, for bona fide religious purposes, or, any ancient monument, within the meaning of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, or, any temple, or, any car used for the conveyance of idols. This is a basic structure on which our democracy has been built even before the colonial countries had

occupied our nation. It is no doubt that every temple, Hindu temple, is depicting various postures. The Konarak Temple, which is one of the major attractions for all the tourists, is the best example. But it is a part of science. People have to explain to the ordinary persons who may not have the advantage of knowing what sex is. But it should be confined to only those persons who need it. But when they make things available in every aspect, and advertise certain things in order to sell their product, which is in no way connected with sex at all -- they include sexual words and pictures in it -- we have to find out under what definition they are doing it. If you take the Information and Technology Act, Section 67 allows publishing or transmission. It is not clearly defined. At the same time, it has given the punishment period of 5 years to 10 years and a fine of Rs.2 lakhs for violation of the law under Section 67. If you take the Indian Penal Code, the punishment is only for two years and a fine of Rs.2,000 or Rs.5,000. These are all contradictions under which we are having laws. Now, when there is a contradiction, what is the definition that we take? There is no definition at all in our law. But, when we look at the definition of the U.S., the Pennsylvania Consolidated Statute defines it in Section 5909. It says, "The average person applying contemporary community standards would find that the subject matter taken, as a whole, appeals to the prudent interest." This is a definition given by the Americans. If we take the definition of an Eastern country, say, Japan, article 175 of the Constitution says, "It aroused and stimulated sexual desire, offended a common sense of modesty or shame and violated proper concepts of sexual morality." The U.K. defines it in the Obscene Publication Act,

1959, using the words 'deprived and corrupt". These are the words which we have also borrowed when we amended the Act in 1969.

(Continued by 3R)

3r/4.20/ks

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Contd.): Sir, the Supreme Court of Canada, talking about undue exploitation holds that the dominant test should be the community standard. However, it is the standard of tolerance, not taste, that is relevant. South Africa's definition talks about (a) child pornography (b) explicit violent sexual conduct (c) bestiality. In that way, every country has its own definitions. The European Convention of Human Rights says, the definition must be clear, contextually sensitive and responsive to the progress in the knowledge and understanding of the phenomenon towards which the legislation is directed. Vagueness is dangerous.

Sir, it is high time that we brought in a proper law. We need not ban everything because we do not have the right to choose channels. It is in the hands of the common man to make a choice with channels. But we can have one test. If the grandfather, grandmother, daughter, son and grandchildren can all sit together in their living room and watch television and if all that they are watching is acceptable, then there is no question of obscenity. Thank you, Sir.

(Ends)

SHRIMATI BRINDA KARAT (WEST BENGAL): Sir, this is a very important topic and I express my appreciation to the Chair for giving us time to discuss it.

When it was known, Sir, that we are going to have such a discussion, I heard several commentators on television asking the question: Is it the right of Members of Parliament to decide what viewers are going to watch on television? It is not the job of parliamentarians to decide what channel, viewers are going to watch. But Sir, I think, when there is such an outrageous violation of certain minimum norms which have been set up, both in the Constitution and in various laws prevailing in India, it is certainly the duty of parliamentarians to discuss it and suggest remedial measures, and particularly so, when, as my colleague, Shri Ravi Shankar Prasad, has said, certain channels descend to the lower depths while chasing TRPs. Of course, there are exceptions.

Sir, as a participant in women's movements, which for several decades now have been fighting against assault on the dignity of women, the aspects which I would like to focus upon are their portrayal in sections of the media, demeaning women, treating women as sex objects, commodifying women's bodies. These are aspects, Sir, about which we have laws in this country but which are being flagrantly violated. It is this which I object to. There are, at present two types of portrayals of women which, I think, are objectionable. The first is, as I said, which treats women as sex objects. The second is that which assaults a woman's dignity by portraying her in an extremely submissive, subordinate and passive role; a woman who in the name of self-sacrifice and sacrifice for the family, or in the name of some cultural constructs, commits the worst kind of atrocities against herself and her own body. That also, Sir, is extremely demeaning to women. We have seen serials which show a woman who is a victim of rape falling at the feet of the

rapist and saying that she would be helped if he marries her. This is also very demeaning. The reason why these kinds of images of women are being portrayed -- it is not of academic interest -- but it is directly related to public behaviour and public approach towards women. We cannot deny the huge reach and power to influence minds that the television has. Sir, studies have shown, both internationally and in our own country, the influence that such portrayals of women have in shaping public approaches to women.

(Contd. at 3s/tdb)

TDB/3S/4.25

SHRIMATI BRINDA KARAT (CONTD.): And that is why, it is of direct interest that a control should be put on this. My party, Sir, and the Women's Organisation -- I have been associated with the All-India Democratic Women's Association -- have made it very clear. We are entirely against any type of Government censorship. In the name of censorship to censor channels, and, particularly, news channels, is abhorrent to the minimum norms of democracy. We are opposed to it. We are also opposed to the Government taking on itself the role of the upholder of the so-called morality. I am opposed to any kind of moral policing. But, I want to differentiate between moral policing in the name of culture and the dignity of women, the integrity of women's bodies and the commodification of women. Therefore, what I believe and what is required today is, what the Supreme Court had suggested many, many years ago, and with so many recommendations have come to the Government, i.e., to set up a public authority, set up an independent regulatory authority with representatives of the public who can decide a

code of conduct. I can tell you very clearly that the media has utterly failed in any type of self-regulation. And it is this utter failure of the media in self-regulation, it is the utter failure of these bodies set up and the associations set up by the media -- whether it is the Advertising Council of India, whether it is the Indian Broadcasters' Federation, whether it is the News Broadcasters' Federation -- to implement their mandate, to have some kind of self-regulation that today Parliament is forced to have a discussion like this, and to say, "No more. We are not going to tolerate this assault on women's dignity; we are not going to tolerate this promotion of obscurantism, this promotion of superstition, this promotion of many caste-based identities which are harmful to oppressed castes, which treat with contempt poor people". This kind of thing, Sir, is abhorrent to public broadcasting and, therefore, we believe it is time the Government should come up with an independent regulatory authority, and I stand here today to forcefully make that demand.

The second point I want to make in this is, my friend has given many examples of what is happening today, which are very, very accurate and correct. But, you look at advertising today in this country, Sir. It seems that these advertisers have absolutely no code whatsoever. You look at the recent advertisements which have come for male deodorants. I mean, they are just absolutely shocking and obscene, and they make an absolute mockery of woman's sexuality. I am not against the depiction of woman's sexuality. You see it in Khajuraho; you see it in Konark. That does not undignify women. But, here you have an expression of woman's sexuality which is nothing but sensationalism;

nothing but the use of women's bodies and nothing but titillation. It is absolutely outright objectionable. And all these advertisements which utilise women's bodies from selling soap, to cars, to computers, there has to be some limit, Sir. And the Advertising Council of India has this Consumer Council. I know it because we have made so many complaints to it. How many complaints have I not made on behalf of my organisation? Only recently, we have made two complaints. We have made a complaint about 'Fair and Lovely'. Why? It is because it is a racist ad. In a country like India, you are trying to demean people who have a dark skin; you are promoting fairness; and you are promoting fairness by the use of chemicals which are hazardous, apart from everything else. This was several years ago, Sir. I had made a complaint. They set up some mechanism, but, till date, those ads are continuing. So, in this type of advertising code, I am afraid to say, the Council has utterly failed and the Government has also utterly failed because the Government had set up a Committee. That Committee, Sir, had various representatives of various sections. My organisation, AIDWA was also represented on it.

(Contd. by 3t-kgg)

kgg/3t/4.30

SHRIMATI BRINDA KARAT (contd.): It has given its report; I mean, it was a very partial report, I do not agree fully with it. But, there are some very important recommendations that committee has made. The Government is sitting on it for the last two years. What is the use of setting up a committee to look at code of conduct if you are not

bothered to implement at least some of the recommendations which may be very positive?

Then, one more thing I want to talk about, on news channels. Our news channels have a certain element of support because there should be no censorship on news. Just now, I was sitting in the Central Hall of Parliament. I do not want to mention the news channel because I am not specifically targeting or pointing to this or that news channel. There, it says, so and so, नीचे लिखा है News. What is being shown on that channel, right now? 'Belly dancing' with women who have very little clothes on. Now, since when this belly dancing, depicting women with very little clothes on constitutes news? The point is, even as far as news is concerned, this is the manipulation of news to utilise women's bodies, to push up the TRP ratings. This exactly is what I say, Sir, highly objectionable. Within this also, something is probably more shocking and, that is, the use of children and use of children's bodies. I have seen, Sir, video films made, picturisation of songs. It is very good to see picturisation of songs, they are good, they make you happy and they are very entertaining. But, there must be some standards on picturisation of songs. You have young women attired in school uniform, thereby showing them as school girls, depicting themselves to attract the male gaze in a way which is really harmful and damaging to the young mind. Is this something we can accept or tolerate in the name of freedom of the channels to project what they want to project?

I had earlier made this point and I want to reiterate by quoting a survey which we have done. We had gone to Delhi University and Amity University. We had a 500 questionnaire. We questioned young boys and

girls of equal number. You will be surprised to find. We had the list of some of the TV programmes which we felt were highly objectionable. Some advertisements were really demeaning to women. 80 per cent of the girls we spoke to felt that they were really demeaning and should be scrapped. But, unfortunately, the large majority of young men who were interviewed felt the exact opposite. Some of the comments that they made were so revealing because their feeling was that girls want to be portrayed in that way and, therefore, it was permissible. So, in other words, you are projecting a picture as though young women in this country or women in this country equate modernity with the number of men that you can sexually attract! This is how minds and frameworks and mentalities are formed. Is this what modernity is going to be about? Is this the projection of modernity which is going to help young people to understand? So, this is what is extremely objectionable, Sir.

Therefore, I would like to reiterate that firstly we are not for moral policing. We know, in the name of culture, the most retrograde codes are imposed on women whether it is the dress code or behavioural codes; I am not, in the least, in support of any type of moral policing from any quarter. But, at the same time, this kind of freedom which is there today, used and misused by TV channels and by many newspapers should be put to an end by setting up this regulatory authority.

Sir, my last example, and I am very sorry that I have to do this; I feel a bit embarrassed also to bring this up in the House, in front of so many of my male colleagues. But, the reason I want to do this is because it is not just fly-by-night television operators who are here today

and gone tomorrow. Sir, this is one of the most respected and read national newspapers.

(Contd. by kls/3u)

KLS-DS/4.35/3u

SHRIMATI BRINDA KARAT (CONTD): This newspaper on June 29, --and I am going to lay this on the Table of the House, -- has got a page which is "Evergreen Legends of Delli". And what are these evergreen legends of Delhi, Sir? You excuse me, Sir, and my colleagues may excuse me if I just talk about this. ...(Interruptions)... All my colleagues, yes. ...(Interruptions)... What it says is that 'continuing the traditional art of bottom pinching in buses, despite all odds. For being undeterred by age, caste, creed. ..... For the supreme ability to keep a poker face along with his twitching fingers for leaving his make behind on society'. And for those who are nominated they are going to give award to two people. This is nothing but encouraging sexual harassment of women in buses. How can we permit such a thing? I demand, Sir, the Government launches criminal prosecution against those responsible for this. It is absolutely outrageous. It is not an advertisement; it is a programme, which is being run by this national newspaper in which they are giving awards for encouraging sexual harassment. It is absolutely disgusting and outrageous and I certainly demand that the Government and our very sensitive Minister - I do not know whether it will come under the Law Ministry or the Home Ministry or some other Ministry- to please look at this, take action against it and make an example of people who want to try and add humour to an act which is most

degrading and objectionable to women. I strongly object to it, Sir, and I hope that the Government will do something about it. Thank you.

(Ends)

श्री कमाल अख्तर (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज पूरे देश के अंदर सांस्कृतिक मूल्यों के विरोध में, टीवी चैनल्स में बढ़ती हुई अश्लीलता और मर्यादाओं के उल्लंघन, जैसे महत्वपूर्ण विषय पर संसद के अंदर चर्चा हो रही है। सर, रवि शंकर जी ने और वृंदा जी ने, सब लोगों ने इस पर अपनी बातें कहीं, मैं उनकी बातों से इत्तिफ़ाक करता हूँ कि हम लोग टीवी चैनल्स या मीडिया की आजादी के खिलाफ नहीं हैं। हम लोग यह मानते हैं कि आज देश के विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक जमाना था कि जब दिल्ली या मुम्बई में कोई घटना होती थी तो गांव के अंदर उसकी सूचना पहुँचने में और उसे लोगों के सुनने में दो-दो, तीन-तीन दिन लगते थे। आज यह मीडिया और टीवी चैनल्स की बदौलत है कि लोगों के बैठने में, उठने में, पहनने में और सारी चीजों में परिवर्तन हुए हैं। आज देश के अंदर राजनीतिक या किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी घटना भी होती हैं तो उसकी सूचना चंद सेकंड्स के अंदर गांवों तक लोगों के बीच में पहुंच जाती है। हम लोगों को यह भी मानना चाहिए कि इस भारत के अंदर, इस हिन्दुस्तान के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान कृष्ण, अशफाकउल्ला खाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसे लोगों के आचरण, उनके सिद्धांतों और उनकी नीतियों पर चलने वाले लोग भी हैं। हमने उनसे सीखा है, उनको पढ़ा है, उनके उसूलों को पढ़ा है। आजादी के नाम पर यह नहीं हो सकता। हम लोगों ने यहाँ पर 22 तारीख को एक मुद्दा रखा था। हम लोग Reality Shows या TV Serials के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज Reality Shows और TV Serials के नाम पर हमारी मर्यादाओं, नीतियों, सिद्धांतों, हमारे बुजुर्गों ने हमें जो आचरण दिए और हमारे लोगों ने इस देश के अंदर रहने का जो एक कायदा-कानून बनाया, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि आज इस तरह के serials बनाये जा रहे हैं, आप लोगों ने इसी संसद के अंदर कानून बनाया और हम सभी लोग बाल विवाह के विरोधी हैं। हम यह कहते हैं कि

बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन आज इस चीज को serials के माध्यम से, "बालिका-वधू" के नाम से पूरी तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम बाल विवाह के विरोध में है।

(3डब्ल्यू/एकेए पर क्रमश:)

SSS-AKA/3W/4.40

श्री कमाल अख्तर (क्रमागत) : सर, आज जहां लोग अपने TV Channels से देशभक्ति की फिल्में देखकर देशभक्ति की प्रेरणा लेते हैं, reality shows से अच्छे-अच्छे गायक और talented लोग निकलकर आते हैं, वहीं बालिका वधू, इस जंगल से मुझे बचाओ, सच का सामना और ऐसे-ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जिनको मैं इस सदन में बोल नहीं सकता, वह असंसदीय कहलाएगा। लेकिन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन reality shows को तो छोड़ दीजिए, मैं अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि जो हमारे समाचार चैनल्स हैं, उनमें भी एक-आध देखा जाता है कि न्यूज़ खत्म होने के बाद जिस तरह के advertisement आज दिए जाते हैं, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोई भी सज्जन आदमी, हिन्दुस्तान का कोई भी बुजुर्गों में आस्था रखने वाला आदमी, उस चीज को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है ताकि देश को पता चलना चाहिए कि वे कितना गलत कहते हैं। एक TV Channel में समाचार के बाद एक महिला फोन उठाती है और दूसरी महिला से पूछती है कि कैसे हुआ, कब हुआ, कितने घंटे हो गए। वह बोली कि अभी दस घंटे हो गए। तो दूसरी बोलती है कि 72 घंटे के अंदर इस गोली को ले लो, गर्भ का कोई खतरा नहीं है। इस तरह के अगर advertisement दिए जाएंगे तो बताइए कि किस तरह का प्रभाव लोगों पर और हमारी आने वाली जनरेशन पर जाएगा?

सर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गांव के अंदर हम लोग देखते हैं कि मेला, उर्स लगते हैं। मेले के अंदर अगर कोई भी नोटंकी या डांस पार्टी लगाना चाहता है तो उससे कहा जाता है कि आप पहले DM या SDM से अनुमति लेकर आइए। उन्हें इसलिए अनुमति नहीं दी जाती कि वहां पर सैंसर से पास हुए गानों पर नाच-गाना होता है, शांति

भंग होने का खतरा होता है और उससे लोगों में गलत संदेश जाता है। लेकिन, सर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी एक TV Channel पर मैं गया, वहां पर बहस चल रही थी, बहस में उन्होंने कहा कि अगर आपको यह channel पसंद नहीं है तो आपको इसे बंद कर देना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक channel नहीं है, इस तरह के ऐसे-ऐसे और इतने channels हैं कि अगर उन channels को आप बंद करेंगे तो लोग TV देखना बंद कर देंगे।

एक यह बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक VH Music Channel है, जिसमें Night Live NEWS होता है और उसमें पिछले Saturday की रात को, उस प्रोग्राम में भारत के झंडे का कलर पीछे करके उस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा जाता है - The Biggest Condom. सर, यह कितनी घटिया बात है!

सर, हम लोग मंत्री जी से यह कहना चाहते हैं कि न तो हम लोग reality shows के खिलाफ हैं, न हम serials के खिलाफ हैं, लेकिन जब ये पास किए जाते हैं, जब इस तरह के प्रोग्राम्स जनता के बीच में प्रसारित होने के लिए जाते हैं, तो कम से कम कोई ऐसी समिति बनाएं या उनको इस प्रकार से सैंसर जरूर करें, ताकि जो ये अश्लील बातें हैं, अश्लील विचार हैं, ये हमारे नौजवानों या समाज के बीच में न जाएं, जिससे उन पर गलत असर पड़े। हमारा सिर्फ इतना ही अनुरोध है और जो इस तरह के कार्यक्रम आपकी निगाह में हैं, अभी आपने नोटिस लिया है, आप ऐसे channels के खिलाफ, ऐसे कार्यक्रमों के खिलाफ कड़ाई से कदम उठाएं, ताकि वे इस समाज के अंदर अश्लीलता न फैला पाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

DR. K. MALAISAMY (TAMIL NADU): Thank you very much, Mr. Vice-Chairman, Sir. I appreciate the sponsors instrumental for bringing this topic for discussion because it is very much the felt need of the society and it is more timely also. In other words, a right topic has been

chosen at a right time. My job is pretty easy, particularly, after listening to Mr. Ravi Shankar Prasad and Shrimati Brinda Karat. They have done enough justice to their job. (Contd. by NBR/3X)

-SSS/NBR-NB/3X/4.45

DR. K. MALAISAMY (CONTD.): Coming to the subject, any place on earth has got its own origin, history, culture, character, etc. In the same way, India has got its unique features in terms of its own culture and character. Sir, particularly, I have got the greatest appreciation for our Hindu family system, hospitality, character and culture in which a family has been built. I have also got the greatest appreciation of how our children are brought up, how elders are respected by children, etc. It is unique to India alone. We have borrowed so many things from other countries. If we borrow right things, it is well and good. But, at the same time, the Western countries' cultural invasion over India has done the greatest damage. I mean, this is very much instrumental because of our media. Sir, yourself and the entire House knew that the Indian democracy stands on three pillars -- Executive, Legislature and Judiciary -- operating through bureaucracy and assisted by the Fourth Estate. Sir, the Fourth Estate, namely media, is a very important tool in our democracy. Media has been playing its role in several ways. We appreciate the other ways. But, it has done the greatest damage to the society as rightly pointed out by our colleagues spoken earlier. A man is said to be fully grown only when his body is grown, his mind is grown and his soul is grown. Unless body, mind and soul are grown together, man is not complete. We look at it in this way. On the one hand, due to media's influence, man's body is out, health is out, mind is out and soul is out. I do not like to go into the details at all. And, on the other, serials, advertisements and other features, which have been explained by our friends, have been doing the

greatest damage to our society. This is how I look at it. As rightly said by Shri Sudarsana Natchiappan, the law is inadequate. The hon. Minister and the officials concerned may try to say that we have got this law, we have got this system and all that. But, according to me, whatever may be the system in existence, whatever measure that we are taking, they are all inadequate and ineffective. This is the first point.

Secondly, Sir, for any objective to be achieved, one should have organisation, manpower and operation. According to me, your organisation or your operation is inadequate to meet the situation. You have got legislation only for the name sake. What is the use of any law which confines itself only to paper? It should be effectively implemented. There has to be an effective law and it should be implemented effectively. Sir, unless law is rigorously implemented, unless persons are given deterrent punishment and the violators are dealt with severely, things cannot improve. In short, what I am trying to say is, law should be effective and the system to implement that law should be much more effective. On the whole, the society needs that Television channels should be disciplined to the extent, so that our character and culture is safeguarded. Thank you.

Sir, you should thank me, because, today, I have completed my speech much earlier than the time allotted to me. Thank you.

(Ends)

---

* Pp 473 onwards will be issued as a Supplement.

-SSS/NBR-NB/3X/4.45

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have not done that. What you have done is: you have taken up the speeches of both, Brindaji and Shri Ravi Shankar Prasad. Your points are also there. You have also taken their points. I heard them. Anyway, thank you for sticking to the time. I will be very happy if you behave like this every time.

(FOLLOWED BY USY "3Y")

SHORT DURATION DISCUSSION ON INCREASING OBSCENITY AND VULGARITY IN TELEVISION PROGRAMMES BEING SHOWN ON DIFFERENT CHANNELS AGAINST CULTURAL ETHOS OF THE COUNTRY (CONTD.)

-NBR-USY/4.50/3C

SHRI SHYAM BENEGAL (NOMINATED): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have heard with great interest the earlier speakers. There is very little to disagree with them, except, I think, the conclusions drawn are not something that I would entirely endorse because I believe that the Government has really very little role in all this. Essentially, culture is dynamic. The whole process is evolving. What was culturally unacceptable, yesterday, is culturally acceptable today. And, what was culturally acceptable, yesterday, is maybe culturally unacceptable today. So, it is a constantly changing pattern. When it comes to television...(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Benegalji, isn' there is something basic?

SHRI SHYAM BENEGAL: Yes, there is. For instance, you have classic culture; you have folk culture; you have popular cultures; you have mass

cultures. Now, the fact is that until the middle of 20th century, you really did not think in terms of mass culture. Today, you have to think in terms of mass culture. And, this mass culture is made possible, essentially, because of the kind of technology that we today have. For instance, television is a part of this mass culture. The manner, in which television functions, is incredible. We know that it has enormous power because it reaches everybody. But, to me, the important thing here is really the fact that it is a social medium. Because it is a social medium, there has to be a sense of social responsibility. Now, this is where really the problem exists. In our country, I can tell you, like, for instance, we have had the Censor Board for cinema. And, I do not believe that the Censor Board is actually an effective way of functioning because the Censor Board has not functioned efficiently in all these many years. It has not functioned well at all. We have a certain kind of sense of cord. Obviously, that sense of cord is, essentially, based on ideas that can be interpreted very subjectively. In any case, for instance, in matters of culture, in matters of taste, it is a question of my world against yours. I do not believe that there can actually be an objective way of judging these things. It is a question of I like it or I don't like it; or, somebody likes it or they don't like it. But, this whole debate has started because of a few programmes that are being shown on television. Now, this particular set of programmes, as you well know, have been directly from television, outside our country, that is, from the American television. For instance Sach ka Saamna is nothing but a copy of something, called, "Moment of Truth'. The 'Moment of Truth' has been showing even in India over a long period of time. Nobody objected to it. It is strange

that nobody objected to it because it is as though we are not offended if some foreigner demeans himself or herself. But we suddenly gets affected when our own people demean themselves. Because, ultimately, what is this particular programme? This programme is simply, like, say, "I will give you so much money, if you strip naked in public". This is what the programme is all about. It is a very simple thing. This programme is demeaning to human being as such; it is a terrible thing; it is a terrible kind of programme and concept. If anybody says, "Yes, it has got very high TRP", obviously, it has very high TRP. It is a simple thing. If there is an accident on the road, who does not want to watch that? Everybody does that. If there is an act of extreme violence, who does not watch that? Everybody watches that. Day-before-yesterday or yesterday, we saw on television a lady being stripped and people were just watching, doing nothing but watching, just spectating. Now, this kind of spectating is involuntary. It is not voluntary. People do not do it by choice. Similarly, pornography is also the same thing. It is demeaning. After you have seen something like that your own sense of self-esteem disappears. People do these things in private. For instance, if you go to a cyber cafe, you have young people, teenagers, on one side, and you have a dirty old man on the other side watching porn sites. I don't particularly worry about that because they are individuals and they are doing it in private on which you cannot legislate anything at all.

(Contd. by 3z -- PB)

SHRI SHYAM BENEGAL (CONTD.): It is a very simple thing. But television is a social medium and if it is a social medium, it means that it is going to be watched by public at large, often families; it is family viewing and 90 per cent of the time, it is family viewing. But, even then, I do not believe that the Government has any serious role to play in this. I think, what needs to be done is, we need to create regulatory, self-regulatory bodies; but that self-regulatory body of the Broadcasting Council or whatever, needs to have an equal number of people from civil society. I do not at all believe that you need to have Government people on it. I don't think the Government people should really be involved in all this. I believe that you need to have a regulatory body which consists of people from the industry itself, television industry itself, and, on the other hand, you should have a group of people who happen to be members of the civil society. I also believe that the casting vote should be in the hands of a person belonging to civil society. I think, that is the most important thing. Otherwise, I don't think we can get rid of it, and, I certainly don't believe that the Government has any serious role to play in this. I can immediately tell you that from 1928 we have the Film Censor Board. Can we say that it has succeeded? It hasn't succeeded because if you look at the history of the last 10 or 15 years, you will find that the Censor Board, which has quasi-judicial powers, will actually give a Censor Certificate to a film. But then one or another political interest will suddenly decide that they will go and attack the cinema house. And, what happens? Is that Censor Certificate worth anything at all? It is because often the Police will stop the film saying

that it is a threat to law and order. This has happened time and time again.

So, I personally do not think that the Government has any role. But I do believe that civil society has a role in this and the Broadcasting Council itself has a role in it. I think, we can determine how to set that kind of a body. Thank you very much.

(Ends)

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं, जो आए दिन लोगों को, mass को प्रभावित करता है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि वह जो दिखा रहा है, वही सच है और जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वह मजबूरी में देखें, चाहे जैसे भी देखना हो देखें, लेकिन इतनी बात सच है कि टेलीविजन में जो कार्यक्रम आ रहे हैं, उन कार्यक्रमों में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। श्याम बेनेगल साहब ने जो कहा कि सरकार उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, मैं उस विचार से सहमत नहीं हूं क्योंकि अगर सिनेमा दिखाने के लिए सेंसर बोर्ड है, तो टेलीविजन के लिए भी एक सेंसर बोर्ड होना जरूरी है। हमारे एक मित्र ने कहा कि अगर मेले में कोई फंक्शन करने जाता है, कोई नाच-गाने का कार्यक्रम करना चाहता है, तो वहां पर कलेक्टर की परमिशन होती है कि आप जो कार्यक्रम करना चाहते हैं, वह कार्यक्रम सही है या हंगामे वाला है। तो अगर एक साधारण नाच-गाने का प्रोग्राम कोई मेले में करने जाता है और उसके लिए उसको परमिशन की जरूरत है, तो टेलीविज़न तो लाखों-करोड़ों लोग देखते हैं, उसमें अगर कुछ obscene दिखाया जाता है, कोई गलत बात दिखाई जाती है, किसी को अपमानित करने के लिए दिखाया जाता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, तो उसके लिए अगर कोई रेग्युलेटरी अथॉरिटी नहीं होगी, तो फिर यह मामला कैसे चलेगा? उदाहरण के लिए मैं एक सवाल यहां रखना चाहता हूं। बच्चों का एक कार्यक्रम होता है - कार्टून फिल्म ! छोटे-छोटे बच्चे जो कार्टून फिल्म देखते हैं - उसको बच्चे नहीं समझते, हम समझते हैं कि उसमें कार्टून के माध्यम से इतना violence दिखाया जाता है कि बच्चे को अगर आप पढ़ने के लिए कहिए, तो वह गुस्सा हो जाता है और कार्टून में एकदम involve हो जाता है। वह

foreign की कार्टून फिल्म होती है, उसको यहां लाकर borrow किया जाता है और हमारे घरों में बच्चे इतना कार्टून देखते हैं कि उनका पढ़ने का मन नहीं करता है।

(4A/SC पर क्रमश:)

-mp/sc/5.00/4a

श्री राजनीति प्रसाद (क्रमागत) : वे पढ़ाई करने के लिए जाने को तैयार नहीं होते हैं। इन cartoon films में यह सब दिखाया जाता है कि इधर से कोई मार रहा है, उधर से कोई और मार रहा है। इसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। सर, अब मैं "बालिका वधू" के बारे में कहना चाहता हूं। "बालिका वधू" में बच्चों की शादी हो जाती है। अगर आप उस पूरे सीरियल को देखेंगे, तभी कोई conclusion निकाल पाएंगे, लेकिन अगर कोई आधा ही सीरियल देखेगा तो उसे यही पता चलेगा कि बच्ची नयी-नयी शादी करके आयी है, उसकी दादी कैसे उसको रूम में बंद करती है और खुद रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। फिर कैसे 5 घंटे, 6 घंटे, रात भर उसको रूम में बंद कर देती है कि तुम इसमें रहो, तुम्हें बाहर नहीं निकलना। इस प्रकार ये जो violence वाले सीन हैं, जो मानवीय दृष्टि से खराब हैं, उनके बारे में हम लोगों को जरूर विचार करना चाहिए। अगर आप इन पर विचार नहीं करेंगे तो उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारे एक मित्र ने अभी बहुत अच्छी बात कही, शायद रवि शंकर प्रसाद जी ने कहा था, कि एक महिला, जो स्कूल की टीचर थी, उसके बारे में टेलीविजन में क्या-क्या नहीं दिखाया गया लेकिन बाद में वह सब गलत पाया गया। इस प्रकार वह महिला तो अपमानित हो गयी, अब उसका क्या होगा? जब कोई ट्रायल चलता है, judiciary का ट्रायल चलता है, लेकिन ट्रायल मीडिया में हो जाता है कि उसने ऐसे किया, वैसे किया। यह क्यों होता है? क्या हमारी मंत्री महोदया या हमारी सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती है? क्या आप मीडिया का ट्रायल करेंगे? यह एक गंभीर समस्या आपके सामने है और इस समस्या के संबंध में हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि आज बच्चों के साथ बैठकर कोई बहुत अच्छे सीरियल या टेलीविजन के प्रोग्राम देखने के लायक नहीं रह गए हैं। कभी कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम लोग रिमोट अपने पास रखते हैं ताकि उसे बंद किया जा सके,

जैसे अगर हम लोगों के साथ कहीं कोई बच्चा बैठा हो और कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे किसी को मार दिया, उसे हम लोग देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं दिखाना चाहते हैं। इस प्रकार आज हम पारिवारिक परिवेश में टेलीविजन नहीं देख सकते। ऐसे घर, जहां एक ही टेलीविजन है, उसी में सबको सब कुछ देखना है। अगर पारिवारिक परिवेश नहीं बनेगा तो दूरदर्शन या टेलीविजन देखना मुश्किल हो जाएगा। सर, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, कुछ अच्छी बातें आती हैं जैसे Discovery Channel है, जिसे देखना हम लोग पसंद करते हैं। लेकिन जो रिएलिटी शोज़ हैं, जैसे "सच का सामना" नामक सीरियल आता है जो रात को साढ़े दस बजे स्टार टीवी पर आता है। उसमें पचास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक करोड़ रुपये मिलते हैं। आपको सच बोलना है कि किस लड़की से आपको प्यार था, नहीं था, क्या था, परिवार के बारे में सब सच बोलिए और एक करोड़ रुपये पाइए। अगर असत्य पकड़ा गया तो फिर आपका गेम खत्म हो गया। वह सीरियल "कौन बनेगा करोड़पति" की तरह है जो रात को साढ़े दस बजे "स्टार टीवी" पर दिखाते हैं। सर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन पर जरूर रोक लगनी चाहिए। अगर आप रोक नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में हम लोगों को बहुत मुश्किल होगी। हमें कभी-कभी लगता है कि लोगों में टेलीविजन देखने की जो एक बाढ़ सी आ गयी है, आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लोग इसको देखना बंद कर देंगे और फिर रेडियो के चैनल्स शुरू होंगे, रेडियो पर गाने शुरू होंगे। इसलिए अभी से ऐसा कुछ काम करिए जिससे obscene यहां नहीं दिखाए जाएं, लोगों को प्रोग्राम देखने में अच्छा लगे। इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए। आपने हमें मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। (समाप्त)

(4बी-एमसीएम पर क्रमशः)

MCM-HK/4B/5-05

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, इस विषय पर मेरी पार्टी की ओर से श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात रखी है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी काफी कुछ प्रकाश डाला हूं। इस संबंध में मुझे अपनी ओर से भी दो-चार बातें कहनी हैं। सच बोलना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन यह सत्य है कि सच बोलने के लिए साहस की जरूरत होती है और इन तर्कों के सहारे हम अश्लीलता और अशिष्टता

के प्रदर्शन को जायज नहीं ठहरा सकते। इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं, उनको मैं एक तरह से समाज विरोधी ही कहूंगी। बंद कमरे में होने वाली बातों से अलग सार्वजनिक अभिव्यक्ति और अपनी मर्यादा की अलग सीमाएं होती हैं, क्योंकि तब ये बातें व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक हो जाती हैं और इसका असर किसी व्यक्ति पर न पड़कर पूरे समाज पर पड़ता है। अब आप उदाहरण के तौर पर यही देख लीजिए कि जो बलात्कार की शिकार महिला होती है उसका नाम सार्वजनिक नहीं करने की मर्यादा का पालन, मीडिया स्वयं करता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। उस सामाजिक जिम्मेदारी को वह अच्छे से निभाता है। मैं कहना चाहती हूं कि ऐसी ही जिम्मेदारी की भूमिका की अपेक्षा हमें इलेक्ट्रोनिक मीडिया से अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण में भी है। टी0आर0पी0 की होड़ में सामाजिक सरोकार की अपेक्षा मीडिया भले ही पूरी न कर सके जिसकी अपेक्षा है, लेकिन इतना संयम तो उसे बरतना ही चाहिए कि किसी की निजी जिंदगी, नितांत निजी सच की प्रस्तुति का तर्क देकर उसे जायज हम नहीं ठहरा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे समाज में जो विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, और अंधविश्वास हैं, आजकल देखिए कि कितने सारे चैनलों पर जो सीरियल आ रहे हैं, अब उसमें हद हो गई है, जहां एक तरफ हम female foeticide की बात करते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक महिला ने जहां बच्ची को जन्म दिया है इस कारण उसके परिवार वाले दूसरी शादी कर रहे हैं। यह हम क्या दिखा रहे हैं? अन्य सीरियल में एक जगह बंदूक की नोक पर शादी की जाती है और उस लड़की के साथ जिस तरह परिवार में अत्याचार होते हैं और वह सह रही है तो मुझे समझ नहीं आता है कि यह क्या दिखला रहे हैं। ऐसे एक नहीं हजारों सीरियल्स हैं। इसी तरह से विज्ञापन भी ऐसे हैं जिन विज्ञापनों के बारे में पूर्व में भी कह दिया है, समय अभाव के कारण मैं उनको नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन इनके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि कार्यक्रमों को दर्शक पसंद करना चाहते हैं। आपको देखना होगा कि इनकी संख्या कुल आबादी में कितनी है? जो लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं और इनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनको आप इस तरह की बातें दिखला कर समाज में यह संदेश देना चाहते हैं कि ये बातें बुरी नहीं हैं तथा इनसे हमें निज़ात नहीं पाना है। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया है, टी0वी0 है उन्हें स्वयं को यह देखना होगा कि उनकी प्रस्तुति का समाज पर क्या असर पड़

रहा है। इसी तरीके से मैं यह कहना चाहती हूं कि सत्य वही है जो समाज को नई दिशा दे और उनके अंदर एक सृजनात्मक और रचनात्मक अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करे। तो टी0वी0 चैनल्स खास तौर से भी स्वयं इस बात का ध्यान रखें।

महोदय, आपके माध्यम से मुझे और कहना है कि यह जो मीडिया और चैनल हैं, उन पर सेंशरशिप हो। जो मेरी पार्टी का पक्ष है, वह रवि शंकर प्रसाद जी ने रखा है। मैं भी स्वयं उसकी वकालत नहीं करती हूं, वह नहीं होना चाहिए, लेकिन आज सदन में मैं जरूर मांग करुंगी कि इन सब पर एक सामाजिक सेंसर जैसी व्यवस्था जरूर लागू होनी चाहिए। अगर इसके लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ती है तो सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आजादी के साथ ही जो हमारे व्यापक सार्वजनिक हित का मामला भी है और अभिव्यक्ति की ऐसी आजादी को हमारा संविधान भी हमें नहीं देता है, जिसके अंतर्गत हमारे जो सामाजिक हित हैं उनके ऊपर कुठाराघात हो। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि एक तरफ जहां हमें इनको संयम बरतने के लिए इलेक्ट्रोनिक मीडिया को कहते हैं, साथ ही संसद में भी सभी सांसदों से आग्रह करना चाहूंगी कि जब संसद में हम आज इस बात को उठा रहे हैं, तो जब वे संसद के बाहर अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पर भी जाकर जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो अश्लीलता है और अशिष्टता की अभिव्यक्ति होती है, उसके खिलाफ हम जनदबाव बना सकें।

(समाप्त)

(4C/GS पर आगे)

KSK/GS/5.10/4C

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Shri Shantaram Laxman Naik; not more than seven minutes.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (GOA): Sir, please give me ten minutes. I gave the notice.

The source of entire freedom which is being used by the electronic media is said to be article 19. This article 19 is no licence by any stretch of imagination for the very fact that it mentions that nothing

prevents a State from enacting law to impose reasonable restrictions on grounds of public order, morality and decency. This article is very clear, and, in no circumstances, it can be used as a licence. Besides this, we have got section 292 of IPC, and the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986. In the later part of my speech, I will read both Codes - Programme Code and Advertisement Code - which is very much there under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995. This entire set of laws can never permit what we are talking today. Only thing is that there must be a will to implement these existing regulations. Secondly, Sir, media, unfortunately, takes advantage of the fact that we are scared of the media, or, our respect for the media. Even when Shri Ravi Shankar Prasad was speaking, he was apologising after every sentence because he was * that he might be misunderstood.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Don't say that he was * That is expunged.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Naturally, Sir, we are politicians; we have to go to the field. We are * Let me say, I am scared because we are public figures, we have to go to the people.

THE VICE-CHAIRMAN: You can say you are scared; not in his case.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Today, why are we having a debate on this issue? It is not because of all those serials being telecast on television. Umpteen times, we have discussed this matter. The immediate reason for me, and others also, to give notice was the serial, Sach Ka Samna. That provoked us to give notice and we have hardly spoken on this serial. What are the questions asked? Question asked to a lady was whether

---

---

* Expunged as ordered by the Chair

she, at any time, thought of killing her husband. This was the question asked. Then, in front of her husband, in front of her relatives, other such questions were asked like, "Did you sleep with some one else after your marriage?". By what stretch of imagination, can this serial be permitted? I was shocked to know that a person like Vir Sanghvi, the Editor of a leading newspaper, justified the serial. Because these people go to programmes and they earn lakhs of rupees. Therefore, they justify anything which comes on television. This is shocking to me. Therefore, Sir, we have to do something about this aspect. The argument that these people come voluntarily on the programme and they are told about the questions is no justification. It is not their question only. What about those people who listen, children who listen such things? Vir Sanghi says, "Switch off your television." Switching off the television is not a solution. Therefore, this is a TV serial which has to be considered seriously. We have discussed other serials earlier also. Now, programmes are also being shown on astrology. People sit with laptop. बताइए, आपकी डेट क्या है, कितने बजे जन्म हुआ था, कहां पर जन्म हुआ था ? फिर, टुक, टुक करके भविष्य बताते हैं । क्या बताएं, आपकी शादी कब होगी, फलां, फलां समय और दिन आपका शुभ नहीं है, उस वक्त आप कुछ काम मत करिए उसके बाद एक अंगूठी पहन लीजिए या फिर कुछ religious rites करिए, आपकी शादी हो जाएगी । ये लेपटॉप वाले आ गए है । At least, there are two-three programmes where these people sit with laptop take two-three details of the person and then immediately, they tell the future. Such misguiding serials are being shown. Is this permissible under any law? Then, there are programmes where, time and again, we are told, "दुनिया खत्म हो रही है", "the world is going to finish". कितनी बार ऐसा प्रोग्राम हो गया है।

(continued by 4d - gsp/asc)

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (CONTD.): Everybody was scared. Maybe that we were not scared to that extent. But sometimes, we also feel that it may be so. Who knows? गांव के लोगों को तो बहुत सारे डर होते हैं।

Second aspect is superstitious programmes based on superstitious beliefs. First of all, we have to blame ourselves because sometimes, we, as politicians, also perform some other rites which are akin to superstitious beliefs. Our Constitution speaks about maintaining 'scientific temper'. Everywhere, we say that 'scientific temper' should be increased amongst children. Around 25-28 years ago, Late Indira ji, in her Twenty Point Programme, had also mentioned about it. But we are not increasing scientific temper in our political, private or social life, and, are performing so many rites which are nothing but superstitious beliefs.

Down South, in the last elections, a political party's president asked every candidate seeking ticket to the election, to come with an application along with his or her horoscope. This is what the leaders perform. Shyam Benegal ji, I agree with you on most of the issues except when you said that if somebody goes to a cyber cafe and watches some porno, there is no objection or something. It is not so. Now, under the I.T. Amendment Act, that is a serious offence. The other day, I said, people should be educated; students should be educated because they do not know about this law. Students from various schools and colleges can be picked up by the police because this has become an offence. Earlier, it was considered under 'privacy'.

Moreover, Sir, these TV channels do not look after what we do here. Nobody reports the functioning of the Parliament or shows the debates in which we participate. They do not cover a single sentence which is spoken by the Members; the Question Hour is also not covered. But, if any of our Member, more so, fortunately, if some actor or actress is standing outside and waiting for his or her car, that photo will appear on the front page. But nobody bothers about what we say inside this House. Let the television channels ponder over it, and, do something about it. I have seen it several times. These are the incidents.

Sir, I congratulate doordarshan. Madam, I am also telling you that unless you watch doordarshan, you cannot get the exact picture of what is happening in the country. If you really want to know about the activities of the Government or of other organisations, you have to watch doordarshan because there is no other channel except doordarshan, which covers this aspect.

I remember an incident when our former Member, Shatrughan Sinha, and, our Member, Jaya ji, both criticized the doordarshan. I told them, it is the doordarshan, which made you popular in villages, when these channels were not there. People used to see you on television in the movies which were telecasted on Sundays, and, thereby, Mr. Shatrughan Sinha became popular; Jaya ji became popular during Guddi days. (Time-bell) Sir, I will take only two minutes more. (Interruptions)

Sir, nobody referred to the law of the land on this? Because of lack of time, I will not go into the details. Sir, The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 prescribes two codes, one is the

programme code and the other is the advertisement code. It is elaborately mentioned as to which programmes cannot be aired by the television operators. It has been done specifically and these are exhaustive guidelines. But the only thing is that these restrictions are there only for the poor cable television operator, and, for those who produce programmes, there is no restriction. You have put restrictions only on the Cable Network people. Therefore, there is a need for a regulatory body to cover all these aspects. Let media not take it as an offence; we have to do that one day or the other. Thank you.

(Ends)

(Followed by sk-4e)

SK/4E/5.20

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (TAMIL NADU): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I would also like to thank the people who are responsible for mooting this Short Duration Discussion on Increasing Obscenity and Vulgarity in Television Programmes. Sir, at this juncture I would like to say *

This is what Bharathiar says. This is how a lady should be, always straightforward. But, what is being shown in the television is really very, very disgusting. There are only two types of women being shown in the television programmes, one lady is always crying; whatever is going on, she is being beaten up, she is being ill-treated and the other woman, who is being depicted over there, is shown almost like a villain. She is depicted as all bad. Either this sort of thing or that sort

* The Hon. Member spoke in Tamil

of thing is shown. But, this is not the reality. In case of cinema, we have to spend some time as well as some money. But in this case, this comes to our house where we can see it. Umpteen number of channels are there. I mean, a lot of private channels are there. When DD-I and DD-II were there, 'Junoon' and 'Dard' were shown on television. We cannot forget the characters. In a TV serial extra marital affair of Keshav Kalsi is shown. Whatever is shown there, that is all justified. Each and every character is being depicted, is being shown as if everybody is having some extra marital affair. I just wonder what will happen to the minds of the people, the housewives, and the children who are watching these programmes from minimum 6.00 p.m. to 9.00 p.m. And there are some really poor husbands. They are not even given their meal at proper time when the serials are going on.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Poor husband! Teach him to cook.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY: This we can discuss later. This is some other subject. I don't want you to intervene in this please, Madam.

So, they are regularly seeing such serials which are corrupting their minds like anything. Suppose any foreigner -- all foreign channels are coming to us and we are seeing them -- comes here and see, is this what is India, is this our culture which is shown in our television serials.

Apart from this, our media people are always after something sensational. When the Mumbai bomb blasts happened, the same day many more important things were going on, but nothing was shown. Each and every minute of the Mumbai blasts was shown. Everybody

was watching that. In fact, we had to watch only that. This is another thing about media. They are teaching what is not allowed. As my colleague, Mr. Shyam Benegal, was telling, what is not even allowed even by the Censor Board in the Cinemas, in the big screen, it is being shown on the television. I will tell you what is being shown in a particular serial, Sir. We are going to enact a law against the acid being thrown on ladies. We are about to enact some law against that. But what a television serial shows is, a person is taking one egg. He is removing what is inside it and with a syringe he is taking everything outside and then acid is being put inside. They are actually teaching in this particular serial how this acid thing is prepared and then thrown on the face of a lady. Of course, some good programmes are there. I was Member of the Censor Board. We had certain norms like what things are to be shown and what things are not to be shown and there are some bad words which should not be shown on the big screen like this. Is it possible to bring such a thing, such a regulatory system, for the small screen also? That is a question. You belong to my neighbouring State, Sir. In each and every State, we have our own culture. We have seen unity in diversity. So, the best thing would be, not as my colleague was telling, if the regulatory system is made only of the TV people, the same thing will happen. They will be encouraging, they will be advocating their own rights only. So, this regulatory system should be given certain guidelines like these are the things which can be shown, what is already prevailing in the Censor Board. Like eunuch people being always shown for comedy purpose.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the chair)

These sorts of things have to be avoided as per the Censor Board rules. Similarly, we can form a set of rules for this regulatory system uniformly for each and every television programme, which have to be followed.

(Contd. by 4F-ysr)

-SK/YSR/5.25/4F

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (CONTD.): Whatever regulatory system we are going to propose, it should be there in every State. A minimum of ten people representing a cross-section of society should be present on the board, so that some effective steps can be taken to prevent vulgarity and obscenity from TV programmes. Thank you, Sir.

(Ends)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (KARNATAKA): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am thankful to you for having given me this opportunity. I am sorry I was not here to listen to the debate. I am told that some hon. Members spoke wonderfully well. More time was given to women Members. They made good contribution to the entire debate. You know that we were held up in the General Purposes Committee meeting and that is why we could not be present in the House.

Sir, I just want to make two points. I was not expected to speak. I am Chairman of the Committee on Petitions. This matter came up before the Committee on Petitions. I would request the hon. Minister to pay some attention.

Hundreds and thousands of people met us at various places and some of them came and deposed before the Committee. They all asked us to stop this violence, vulgarity, and obscenity. People are really

horrified to see what is being shown on TV. As far as content of the programme is concerned, comparatively, Doordarshan is better. There is no doubt about it, as far as the present context is concerned. If you see what is happening across the board, it is a very horrible situation. We feel pained. Are we so helpless? Can't we do something about this?

Fortunately, we have a lady Minister who represents our culture and tradition. I hope that she will take note of the sentiments of the House and the sentiments of the people and do something in this regard. This is my first suggestion.

Two, Sir, I do not know about the content which is shown on TV channels in this part of the country. In southern parts of the country, on certain channels, while some programme is going on, you get a scroll. Even in the morning, I saw it. It says, "Geeta, I love you. Where are you? Geeta, I want to kiss you." In the morning I saw it on the television. It is not that a person is speaking to another person. It is through SMS.

This is the reason why I stood up in the House to bring it to the notice of the hon. Minister. These kinds of SMSs are coming on TV channels. They take the name of any person, anybody's daughter or anybody's sister without their consent. If 'X' is loving 'Y,' I have no problem. I don't want to come in between them. They can talk to each other on the telephone. Or they can meet, greet, talk, walk and then do what is allowed. I said, 'what is allowed.' What is not allowed is not expected to be done. But the point is that it is shown on a screen meant for public.

Mr. Kapil Sibal is also here. He must also guide us how to take care of this. It is a very serious issue. It pains us. Every day on a television channel this scroll is coming mentioning a name and then it gives the name of place also like Rajahmundry, Visakhapatnam or Chennai.

Sending that sort of SMSs has become a big business. All sorts of vulgar messages are being aired by television channels. What will be the impact of that SMS on our young generation? That is a big issue which is agitating our minds. I just told my Leader also that I would take a minute to intervene in between and draw the attention of the hon. Minister to take care of the three aspects -- violence, vulgarity and obscenity.

Secondly, about this new technology or new business or commercial proposition of going into the personal lives of individuals and airing it on a television channel and then unnecessarily creating bad ideas in the minds of younger children of the country. It is a very bad thing. I know that you cannot control everything. I am also aware of it. But there are provisions whereby you can regulate this.

I hope the Minister also got the recommendations of the Committee on Petitions before her. It was placed before Parliament. We made a categorical recommendation saying that there has to be a similar organisation like the Press Council of India with more teeth. The Press Council of India is toothless. It is everybody's knowledge. There has to be a regulatory body for the electronic media also.

Sir, I may bring it to your notice that the people from the electronic media came and met the Committee. They said that they

were planning to have self-regulation. I told them that self-regulation was the best regulation.

(Contd. By VKK/4G)

-YSR/VKK-SCH/4g/5.30

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (CONTD.): But, it's not happening and everybody is not going by that. So, that being the case, there has to be a regulatory authority. We have the mushroom growth of the television channels. It is good in one way. Earlier, there was only Doordarshan. दूरदर्शन, यानी दूर से दर्शन करना। देश में अब बहुत दर्शन हो गया, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं और टीआरपी के लिए, कॉम्पिटीशन के लिए चैनल्स में जिस तरह की अनहेल्दी प्रैक्टिस हो रही है, इसके बारे में हमें थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। I only urge upon the Minister to take note of the feelings of the people, keep in mind the recommendations of the Committee and do the needful. Thank you.

(Ends)

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, धन्यवाद। यहां से लेकर वहां तक मैं सबके भाषण सुन रहा हूं ...(व्यवधान)

श्रीमती वृंदा कारत: जो आप बोल रहे हैं, कहीं यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है।

श्री राजीव शुक्ल: नहीं यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। इस मामले में आप एकदम निश्चिंत रहिए।

1997 से इस तरह की स्पीचिज़ चल रही हैं। बारी-बारी से सब लोग सरकार में रह चुके हैं। एक भी दल ऐसा नहीं है, जिसका सरकार से डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली नाता न रहा हो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। 'जब जागो तब सवेरा', इसलिए मैं समझता हूं कि आज अगर यह बहस हो रही है, तो यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है और फिर हमें अम्बिका जी जैसी मंत्री मिली हैं, जिनमें कुछ कर दिखाने का दम-खम है। हमारी अपेक्षा है कि आज जब यह बहस एक सार्थक मोड़ पर आ पहुंची है, तो इस मामले में कुछ न कुछ

निर्णय अवश्य होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि निर्णय क्या हो? निर्णय बहुत साफ है। मेरा अपना व्यू है और वृंदा जी ने भी कहा कि सरकार की मॉरल पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए। 480 चैनल्स हैं, रोज़ टेक्नोलॉजी बदलती है, इसलिए सरकार को इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। यह एक दिन की बात नहीं है। सरकार के वश में यह नहीं है कि वह इस तरह से कुछ रोक लगाए, डंडा चलाए, दारोगा बैठाए और नोटिस भेजे। ये सब काम सरकार के लिए बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तमाम तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। इसका सही उपाय सदन के सभी माननीय सदस्यों के भाषणों से निकल कर आ रहा है, जिसे श्री वीरप्पा मोइली जी के नेतृत्व में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन ने भी दिया था और लगातार इसके लिए सब तरफ से तमाम सिफारिशें आई हैं और वह यह है कि इसके लिए एक रैगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए। उस रैगुलेटरी अथॉरिटी में ब्रॉडकास्टर्स के रिप्रेज़ेंटेटिव्स हों, कुछ गवर्नमेंट के रिप्रेज़ेंटेटिव्स हों, क्योंकि अगर ब्रॉडकास्टर्स मानते नहीं हैं, तो उनको इस बात के लिए मनाना चाहिए। इसलिए उसमें गवर्नमेंट के रिप्रेज़ेंटेटिव्स भी अवश्य हों और साथ ही समाज के अन्य वर्गों का भी प्रतिनिधित्व हो। वह अथॉरिटी कंटेंट के मामले में और अन्य मामलों में ं निर्णय ले। मैंने देखा कि सदन के सारे वक्ता इस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए सरकार को रैगुलेटरी अथॉरिटी तो हर हालत में बनानी चाहिए, यह मेरी भी मांग है और उसमें सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अकेले सरकार के अफसरों से डंडा चलवाने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। उस झंझट में सरकार को पड़ना भी नहीं चाहिए।

दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप उसमें पड़ते भी हैं तो कौन यह तय करेगा कि क्या ऑब्सीन है और क्या नहीं है, क्या अश्लीलता है और क्या नहीं है? कल जैसे वृंदा जी ने जिक्र किया कि एक प्रोग्राम आ रहा था, जिसमें लोग बोल रहे थे कि संसद सदस्यों को इस पर बोलने का क्या अधिकार है। ये कौन होते हैं, जो सूखे की बात करें या गरीबी की बात करें? वे यह बात क्यों नहीं करते कि इस देश में भुखमरी है? बाद में यही लोग कहेंगे कि ये कहां से आ गए यह बताने के लिए कि कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, इस देश में इस तरह की बहस शुरु हो जाएगी। कोई कहेगा कि यह अच्छा है और कोई कहेगा कि यह खराब है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।

पाकिस्तान के बॉलर एक होते थे, सरफराज़ नवाज़। गेंद की शाइनिंग के लिए उसे थाई पर रगड़ना पड़ता है और वह टीवी पर भी दिखाया जाता है, तो सारे मौलानाओं ने इसका विरोध कर दिया कि यह अश्लीलता है और यह बंद होना चाहिए। बॉलिंग करते वक्त, जब यह अपने रनअप पर चलता है, तब इसे टीवी पर बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए इस तरह की बहस यहां पर भी शुरू हो जाएगी, जैसे रब ने बना दी जोड़ी पर भी बहस हुई। मैने शाहरुख खान से पूछा कि इस तरह की फिल्म आप क्यों कर रहे हो, तो वह कहने लगा कि लोग यही देख रहे हैं, ऐसी ही फिल्मों की मांग है और आप देखना कि यह फिल्म जरूर चलेगी और वे सारी फिल्में चलीं।

जहां हम इस बहस में पड़ेंगे कि यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह अश्लील है, यह अश्लील नहीं है अथवा क्या सवाल उठ रहे हैं, तब आप इस चक्कर में बेवजह फंस जाएंगे। इसलिए मंत्री जी को एक रैगुलेटरी अथॉरिटी के गठन की घोषणा अवश्य करनी चाहिए, जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो। मैं वृंदा जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि खाली मीडिया या ब्रॉडकास्टर इसको लागू नहीं कर सकते हैं। न्यूज़ के बारे में देख लिया गया है कि उसके लिए सेल्फ रैगुलेटरी का सिस्टम बना, एक ने उल्लंघन किया तो दूसरे ने भी उसे नहीं माना। इस तरह कितनी ही बातें कही जाती हैं, लेकिन आपस में भी वे उन्हें नहीं मानते और एक-दूसरे को डिफाई कर देते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। कहीं न कहीं इसके लिए रैगुलेटरी अथॉरिटी बिठानी चाहिए। हो सके तो उसमें जुडीशियरी के, सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड या फॉर्मर जज को चेयरमैन बना दिया जाए अथवा जो कुछ भी किया जाए, उसको कुछ पावर्स दी जानी चाहिए।

वेंकैया जी का जो सुझाव है कि इसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह होना चाहिए, यह बात थी तब थी जब सुषमा जी थी। उस समय मीडिया काउंसिल की बात आई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ज्यादा इनइफेक्टिव कोई बॉडी नहीं है। तीन साल तक मैं उसका मैम्बर रहा हूं।

4h/psv पर जारी

श्री राजीव शुक्ल(क्रमागत): सर, उसमें ऐसे-ऐसे प्रतिनिधि हैं, जिनका खुद ही वजूद होना चाहिए कि वे पत्रकार हैं भी या नहीं और फिर भी वे यह तय करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ज्यादा बेकार कोई बॉडी नहीं है। इस चक्कर में पड़ कर आप इस पूरे विषय को, जिस पर आज इतनी गम्भीर और सार्थक बहस शुरू हुई है, उसको खत्म कर देंगे। इसलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी कोई बॉडी बनाकर उसे इस चीज़ को रेफर करने का कोई मतलब नहीं है। या तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को यह पावर दीजिए कि जो गड़बड़ करेगा, उसको सरकार के DAVP का विज्ञापन बंद हो जाएगा। तब तो कुछ नुकसान से फर्क पड़ेगा, बाकी इन सब से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसमें रेग्यूलेटरी अथॉरिटी वाली जो बात है, उसका सबसे ज्यादा असर होता है।

एक बात रवि शंकर जी ने उठाई और बाकी लोगों ने भी उठाई। ...(समय की घंटी)... सर, यह मेरा लास्ट प्वायंट है। यह बात टी0आर0पी0 को लेकर है। यह सारा झंझट शुरू होता है, TAM नाम की एक एजेंसी से, जोकि एक प्राइवेट एजेंसी है, जिसके पीछे advertisers हैं। एक बड़ी advertising agency इसको स्पोंसर करती है। उसका वेस्टेड इंटरेस्ट चाहे जो भी हो, वह हर हफ्ते-- क्या टाइम्स ऑफ इंडिया की हर हफ्ते सर्कुलेशन की रिपोर्ट आती है? क्या हिन्दुस्तान टाइम्स या दैनिक जागरण अथवा अन्य अखबारों की हर हफ्ते सर्कुलेशन की रिपोर्ट आती है कि इस हफ्ते कितने अखबार बेचे? अगर नहीं, तो फिर न्यूज चैनल की हर हफ्ते क्यों आती है कि इतना देखा गया या इतना नहीं देखा गया? इससे क्या होता है कि कम्पीटीशन होता है। कुछ दिनों में आप देख लीजिएगा, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, कि संसद का एक भी कवरेज नहीं होगा, प्रधान मंत्री या नेता-विपक्ष किसी का कोई कवरेज नहीं होगा। हम तो न्यूज चैनल नहीं चलाते, वृंदा जी ने कहा vested interest, लेकिन यह सही है कि हमारी पत्नी यह चलाती हैं। उसमें शुरू में यह हुआ कि पूरी न्यूज दो, न्यूज दिखाओ, न्यूज दिखाओ। बाद में यह हुआ कि बजट की TRP एक आई है, अगर वह TAM की rating सही है। TAM के बहुत कम मीटर हैं। बिहार, बंगाल आदि जगहों में वह कहते हैं कि साहब, यहाँ के लोग गरीब हैं, इनमें

परचेजिंग पावर नहीं है, इसलिए वहाँ मीटर मत लगाओ। मुम्बई और गुजरात में बहुत-सारे मीटर लगाओ, क्योंकि वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर बहुत है। उन्होंने उसमें पाँच, छः या सात हजार मीटर लगा रखे हैं। उनमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, किसकी रिपोर्ट देते हैं? वे कहते हैं कि कुत्ता और साँप की लड़ाई हुई, नाग-नागिन का प्रेम हुआ, इसकी TRP ज्यादा आ रही है। उसे वे दिखा रहे हैं। इस तरह इसमें TAM एक बहुत बड़ा विलेन है, यह जो TRP का सिस्टम TAM है। जैसा उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट एजेंसी को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह इस देश के हजारों करोड़ का बिजनेस तय करे, इस देश की संस्कृति तय करे कि इस देश में कैसे लोग रहेंगे, क्योंकि वही जिम्मेदार हैं। अगर यह न हो, तो कोई इस तरह के प्रोग्राम्स भी न दिखाए, जिनकी आप आलोचना कर रहे हैं। उसकी मजबूरी में, क्योंकि इस चैनल की रेटिंग गिर गई, दूसरे की बढ़ गई ...(समय की घंटी)... और उनको यह करना पड़ता है। इसलिए इस पर रोक लगा कर मेरे ख्याल से एक कमिशन बनाना चाहिए, जो कम-से-कम एक लाख मीटर लगाए, देश के हर राज्य में मीटर लगे और वह छः महीने या साल-भर में अपनी यह रिपोर्ट दे कि इस चैनल की रेटिंग यह रही और उस चैनल की यह रही। न्यूज चैनल के मामले में तो यह जरूर कर देना चाहिए या न्यूज चैनल को आप TAM की परिधि से, उसकी ambit से बाहर निकालिए। उनकी रिपोर्ट छः महीने बाद दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में भी यह करना चाहिए कि उसके लिए एक independent commission होना चाहिए। उसमें ब्रॉडकास्टर्स भी हों, गवर्नमेंट के लोग भी हों और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज हो। उसके एक लाख मीटर्स भी हों। वह यह रिपोर्ट दे कि कौन-सा प्रोग्राम कैसा है। तब तो आप इसे सम्भाल पाएँगे, वरना कुछ दिन में ऐसा होने वाला है कि आप सब लोगों की कोई कवरेज नहीं होगी, पार्लियामेंट का कोई कवरेज नहीं होगा, देश का कोई कवरेज नहीं होगा। दूरदर्शन के बारे में वे बताते हैं कि वह बिल्कुल तीन दिखाई देता है, जो तीन उसकी टी0आर0पी0 रेटिंग है, जबकि पूरे देश में उसका कवरेज है, मतलब वह हर जगह, नॉर्थ ईस्ट आदि सभी जगहों पर देखा जाता है। इस तरह यह TAM agency ही है, जो ये सारी चीज़ें तय करती है। इसके विरुद्ध पूरे सदन को एक होना पड़ेगा, सरकार को यह करना पड़ेगा। वे आकर यह बताते हैं कि नहीं-नहीं, इसमें फिर कहाँ से रेटिंग आएगी? ये क्या हैं? ये सब vested interests हैं।

हजारों करोड़ का निर्णय लेने का अधिकार किसी एक प्राइवेट एजेंसी को, जिसकी लगाम advertisers के हाथ में है, advertising agency के हाथ में है, नहीं देनी चाहिए। यही मेरी सरकार से मांग है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

DR. JANARDHAN WAGHMARE (MAHARASHTRA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I think that legislators are the keepers of the conscience of the society and the country, and therefore, we have a role to play. The Government has a very meaningful role in this particular matter. Legislation is necessary, regulatory body is also very essential. Sir, all this is done in the name of art and culture. But art and culture ennoble your minds, elevate your minds at higher level, but the expression of vulgarity and obscenity degrades your mind, and that is what we are seeing in various serials and advertisements and various things that are shown on TV.

(contd. by 4j)

4J/MKS-HMS/5.40

DR. JANARDHAN WAGHMARE (CONTD.): This has already crossed the laxman rekha. It has completely abolished it. I do not blame all the media persons; they have contributed a lot to our country, to our cultural values. The Government, the people, responsible people, of our society are the custodians of cultural ethos of the country, and we have to preserve it. "Freedom of expression" does not mean "freedom of obscenity and vulgarity". We can define what is "vulgarity"; we can define what is "obscenity". Therefore, we should not be very vague about it and we should not create a feeling that the Government cannot do anything in this matter. Government may not be hundred per cent

effective, but Government has a role to play in this particular matter. The language, the dialogue, the gestures, all these things are meant for sexual gratification, and the ulterior motive is commercialism. This has to be understood -- Constitution has imposed certain duties and obligations on the legislators and the parliamentarians, and on the Government also, and we have to do that. Our cultural ethos have to be protected at any cost. Thank you very much, Sir. (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Kalraj Mishra.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं आप का आभार व्यक्त करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस संबंध में अपने सभी साथी, सम्मानित सदस्यों द्वारा प्रकट विचारों के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं तथा यह अनुभव करता हूं कि जो विषय हमारे सामने आया है, वह निश्चित रूप से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को अवमूल्यित करता है।

महोदय, इस बारे में निश्चित रूप से मीडिया के लोगों को और सदन को भी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हमारी पार्टी के श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने भी इस विषय में विस्तार से सारी बातें कही हैं।

महोदय, सीरियल "सच का सामना"के माध्यम से आज जिस विषय पर चर्चा की जा रही है, यह सही मायने में अमेरिका में प्रसारित एक सीरियल "The Moment of Truth"पर आधारित है, जोकि बहुत ही विवादित था, लेकिन लोकप्रिय भी था। उस कार्यक्रम पर आधारित इस सीरियल "सच का सामना" को प्रसारित किया जा रहा है। महोदय, अमेरिका में बहुत ही विवादित कार्यक्रम होने के बावजूद उस कार्यक्रम की टी0आर0पी0 बहुत बढ़ गयी थी। संभवत: इस बात का आंकलन कर के इस चैनल ने यह विषय चुना और "सच का सामना" कार्यक्रम बनाया। महोदय, अभी माननीय सदस्य बेनेगल साहब ने कहा कि उस के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ चरण - कुल 6 चरण हैं और षष्ठ चरण तो इतना भयंकर चरण है कि लोग उसे न देख सकते हैं और न सुन सकते हैं। इसलिए इस सीरियल से यह चर्चा उभरकर आयी है।

महोदय, सीरियल "सच का सामना" तो केवल एक symbolic है, अगर इसे आधार मानकर देखें तो पाएंगे कि आजकल टी0आर0पी0 प्राप्त करने की होड़ में चैनल्स किन-किन प्रकार के विषयों को उजागर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस बारे में लोगों ने अपने-अपने ढंग से वर्णन किया है। वृंदा कारत जी ने इस का वर्णन किया है, वसन्ती स्टान्ली जी ने भी किया है और कहा है कि आज महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन हो गयी हैं। सीरियल "सास बहू" के विषय पर आधारित कई सीरियल बने हैं जिन में एक महिला, दूसरी महिला को नीचा दिखाने के लिए क्या-क्या काम करती है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आज Reality Show के माध्यम से ये चीजें दिखायी जा रही हैं। हालांकि उन में talent hunt भी हो रहा है, प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, जोकि एक अच्छी बात है, लेकिन साथ-ही-साथ युवाओं के लिए बन रहे सीरियल्स "Roadies" है, "Split Villa" है, उन में लड़कियों के इतने कम वस्त्र होते हैं कि कोई टी0वी0 की तरफ देख ही नहीं सकता है।

(4 के/डीएस पर क्रमश:)

-hms/ds-tmv/4k/5.45

श्री कलराज मिश्र (क्रमागत): कोई बैठ ही नहीं सकता है। एक बड़ा वीभत्स स्वरूप दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों है? केवल वह स्वरूप ही नहीं, बल्कि जो आपस की वार्ता होती है, जो आपस के संवाद होते हैं, जो आपस की चर्चाएं होती हैं, ये vulgarity से इतनी पूर्ण होती हैं कि आप उनको सुन भी नहीं सकते। गाली से भरी हुई ये चर्चाएं भयंकर हैं। एक-एक चीज जो सामने आती जा रही है, ये सारी चीजें, जो टीआरपी को बढ़ाने की होड़ में की जा रही हैं, यह दु:खद है। मैंने एक गैर-सरकारी विधेयक रखा था, जिसमें सारी चीजों का वर्णन किया गया था।

आज जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं, उनको आप नहीं देख सकते। बच्चे उन विज्ञापनों को बड़े चाव से देखते हैं और कहते हैं कि हमें और कोई सीरियल नहीं देखना है, बल्कि वह विज्ञापन वाला सीरियल ही देखना है। चाहे वह विज्ञापन गर्भ-निरोध का हो या जांघिया और बनियान का हो। जांघिया और बनियान का जो विज्ञापन है, उसमें क्या जरूरत है कि सारा स्वरूप उत्तेजक दिखाया जाए? संदेश तो अन्य तरीके से भी दिया जा सकता है, लेकिन उत्तेजक स्वरूप दिखाए जाने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसी अनेक चीजें हैं। मैंने

एक गैर-सरकारी विधेयक "इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर वाणिज्यिक विज्ञापन विनियमन विधेयक, 2005" दिया था। उस समय के मंत्री श्री मुंशी जी ने जवाब देते हुए मुझे बताया था कि "श्री मिश्र जी, our Government is actively seized of this matter and hopefully in this year itself I am going to bring forward a Bill on Content Regulatory Mechanism Authority in the country." उन्होंने यह उस समय कहा था। ये सारी बातें तो पहले आई हुई हैं, लेकिन इस पर होना क्या चाहिए? अब प्रैस के बंधुओं ने भी टीवी चैनल्स को नियंत्रित करने के लिए, self regulation के लिए 'Ombudsman' नाम की एक संस्था बनाई। उसका चेयरमैन रिटायर्ट चीफ जस्टिस श्री जे.एस. वर्मा को बनाया गया। उनके क्या अधिकार हैं, यह माननीया मंत्री जी स्वयं बताएंगी। उन्होंने किस तरीके से नियंत्रण किया है, यह स्वयं उनको जानने का प्रयत्न करेंगी ..(समय की घंटी).. ये सारी चीजें बड़ी तेजी के साथ चल रही हैं। मैं इसके लिए निश्चित रूप से सुझाव देना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से, चाहे वे चैनल्स हों या प्रिन्ट मीडिया हो, ये सारी चीजें तो की जा रही हैं, लेकिन ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं। हम किसी भी प्रकार से यह नहीं कहना चाहते कि संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार का नियमन किया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए। Freedom of Speech और Freedom of Expression को नियंत्रित करने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, लेकिन उसकी मान्यता सुनिश्चित की जाए। Decency of morality के बारे में संविधान ने भी कहा है कि उसके आधार पर चार नियम बनाना चाहिए। इसके बारे में भी विचार किया जाए। मंत्री जी इस संबंध में National Cultural Policy बना सकती हैं, जो सब के लिए और विशेषकर मीडिया के लिए लागू हो सके। अभी पूर्व मंत्री जी ने regular Authority बनाने की जो बात कही है, इसके बारे में वे क्या विचार कर सकती हैं? इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहूँगा कि इतनी सारी चीजें जो हो रही हैं और आपकी तरफ से गाइडलाइंस भी दी गई हैं, तो क्या आपके विभाग के स्तर पर जो अधिकारीगण हैं, वे इन सारी चीजों को देख नहीं पाते हैं? ..(समय की घंटी).. अगर वे देख पाते हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए वे क्या प्रयत्न करते हैं? ये सारी चीजें हैं, जिनके बारे में जानकारी दी जाए तो शायद हम सदन के माध्यम से देश को यह संदेश दे सकेंगे कि हम गंभीरतापूर्वक विचार करके इन सारी चीजों को नियंत्रित करते हुए एक सकारात्मक

दिशा में विकास हो सके, इस दिशा में हम सोच रहे हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान): धन्यवाद, उपसभापति जी। बड़े महत्वपूर्ण विषय पर यह चर्चा हो रही है। जो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, वे देश में अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम हैं। देश की आजादी के दौरान भी जो प्रिन्ट मीडिया है, जो समाचारपत्र हैं, उनकी बड़ी अच्छी भूमिका रही है। इस देश में जब टीवी चैनल्स आरंभ हुए, सबसे पहले दूरदर्शन पर तो बड़े अच्छे-अच्छे सीरियल्स आये, जिनके लिए ट्रैफिक रूक जाती थी। मुझे पता नहीं कि उनकी क्या टीआरपी हुआ करती थी। "हम लोग", "बुनियाद", "रामायण", "महाभारत" और "भारत की खोज" जैसे कुछ सीरियल्स थे।

(4एल/एकेए पर क्रमश:)

aka-vk/4l/5:50

डा0 प्रभा ठाकुर (क्रमागत) : जो कि एक संदेश भी देते थे, जिनको पूरा देश एकजुट होकर देखा करता था। वे मनोरंजन भी देते थे और जानकारी भी। आज जो TV Channels हैं वे हमारे गाइड भी हैं, कहीं समाज के गुरु भी हैं, समाज का आइना भी हैं और वे कहीं न कहीं समाज को एक मार्गदर्शन देने की, आलोचना करने की, उसको उपदेश और संदेश देने की शक्तियां रखते हैं। इसलिए मीडिया की या TV Channels की जितनी शक्तियां हैं, उतनी ही उनकी जिम्मेदारी भी है। सर, इस सदन में जहां न्यायपालिका के कार्यकरण पर चर्चा होती है, जहां कार्यपालिका या विधायिका के कार्यकरण पर चर्चा होती है, जहां संसद सदस्य द्वारा अगर कहीं मर्यादाविहीन होकर आचरण होता है तो उन पर भी कार्यवाही होती है, इसलिए कोई भी संस्था इस देश में सामाजिक व्यवस्था, देशहित, राष्ट्रहित और समाजहित से ऊपर नहीं है और इसीलिए जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इस सदन में चर्चा होती है। आज जिस तरह से सदन को चिंता हुई है तो हम कहीं न कहीं आम आदमी की अभिव्यक्ति को, जो हम तक पहुंची है, हम उसको इस सदन के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। चिंता यह है कि मनोरंजन पहले भी मिला है, समाचार पहले भी मिले हैं, लेकिन अब एक ऐसी होड़ क्यों हो गई है। अगर इस होड़ की जड़ TRP है, TRP और

advertisement जगत की मिलीभगत के कारण अगर इस तरह की होड़ लगी हुई है कि अमर्यादित कार्यक्रम, जो समाज में किशोर मन हैं, जो बच्चों के या युवा दिमाग़ हैं, उनको कहीं न कहीं गलत प्रेरणा देते हैं या गलत राह पर डालते हैं, गलत दिशा में प्रेरित करते हैं, तो इससे एक चिंतनीय स्थिति पैदा होती है। मीडिया खुद लोकतंत्र का चौथा शक्तिशाली स्तम्भ है, इसलिए पहले तो उनको खुद ही अपनी लक्ष्मण रेखा का ज्ञान होना चाहिए। इस देश, इस राष्ट्र और समाज के प्रति उनको अपनी जिम्मेदारी का अह्मबोध स्वयं ही होना चाहिए, ताकि यह स्थिति न आए कि इस तरह की चर्चा सदन में करनी पड़े।

महोदय, हमारे कई माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही हैं, चिंता और चिंतन के बाद कही हैं, चाहे वह किसी कार्यक्रम के बारे में कही गई हों या सच का सामना के बारे में कही गई हों। सर, अगर आप सच का सामना देखेंगे, तो आप उस सच का सामना नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें उसमें कही और पूछी जाती हैं, मैं समझ नहीं सकती हूं कि किस तरह से वह allowed है। किसी TV Channel के नीचे अगर यह लिख दिया जाए कि यह केवल वयस्कों के लिए है, बच्चों के लिए इसे देखना मना है, यह तो फिल्म की तरह हो गया, जो ठीक भी नहीं है क्योंकि घर-घर में TV Channels लगे हुए हैं और parents हर वक्त तो घर पर होते नहीं हैं, हर वक्त तो वे बच्चों को रोक भी नहीं सकते। वहां पर तो किसी तरह से कोई adults वाला formula चल ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के हित के लिए, समाज के हित के लिए इसे सरकार को ही देखना पड़ेगा। महोदय, हम जानते हैं कि माननीय मंत्री महोदया स्वयं एक महिला हैं, संवेदनशील हैं, अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझती हैं। महोदय, मैं मंत्री महोदया से कहना चाहती हूं कि दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से जो कार्यक्रम आते हैं, वे मर्यादित हैं और उस तरह की कोई न कोई guidelines औरों के लिए भी होनी चाहिए। दूरदर्शन पर जो समाचार आते हैं, वे सचमुच में समाचार होते हैं, जैसे कि समाचार होने चाहिए। अब यह कोई बात नहीं है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम इसे दिखा रहे हैं। लोग तो पसंद अच्छे-अच्छे कार्यक्रमों को भी कर रहे हैं, भारत एक खोज को भी इसी देश ने पसंद किया है, आज भी कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पसंद किया जा रहा है। तो ऐसी कोई लोगों की रुचि नहीं है, हम लोगों की

रुचि का गलत आकलन न करें। भारतीय संस्कृति के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी है। महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि NEWS Channels NEWS के लिए थे, लेकिन आज वे सुषुप्त मनोरंजन दे रहे हैं और मनोरंजन से भी ज्यादा दे रहे हैं, जैसे सनसनी। सनसनीखेज़ कार्यक्रमों के नाम पर रेप तथा ऐसे-ऐसे हिंसक व भयानक क्राइम उन पर दिखाए जाते हैं - पहले तो उनको रिपीट कर-करके दिखाया जाना, फिर एक कार्यक्रम की कल्पना करके कार्यक्रम बनाकर फिर उसका प्रस्तुतीकरण करना, इससे क्या मिल रहा है समाज को। कई बच्चों के दिमाग पर इसका बड़ा विपरीत असर पड़ता है और उन्हें लगता है कि यह कोई बड़ी जबर्दस्त चीज हो रही है और उनका मन होता है उसे करने का। हम कई बार पढ़ते हैं कि इन-इन बच्चों ने फलां फिल्म या सीरियल देखकर इस तरह के अपराध को अंजाम दिया, वहां से वे सीखते हैं। कई बार TV में हम देखते हैं कि विधि बताई जाती है - नकली दूध बनाया जा रहा है, नकली घी बनाया जा रहा है, नकली दवाएं बनाई जा रही हैं, वह तो थी, ...।

('4m/nb' पर जारी)

NB/4M/5.55

डा. प्रभा ठाकुर (क्रमागत) : लेकिन उनकी विधि भी बताई जा रही है कि कैसे बनाया जाता है। इससे कई लोग सीखेंगे, उसको बनाने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि अगर एक जगह बिक रहा है, तो सारे देश में बेचेंगे। अब कई जगह हम देखते हैं कि अगर किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के साथ कोई हादसा होता है या घटना होती है, तो आज टी.वी. चैनल्स से ज्यादा बढ़िया जिम्मेदारी कौन निभा सकता है कि वह उस आग पर पानी डालता है या उस आग में घी डालता है। वह चिंगारी आग बनती है, भड़कती है, वह देश के एक कोने में लगती है, लेकिन टी.वी. चैनल्स के माध्यम से वह आग पूरे देश में फैल सकती है। आज उनकी एक अहम जिम्मेदारी है और वह बोध उनको होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह इस दिशा में देखे और जैसे माननीय सदस्यों ने विचार रखा है कि इस तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हो, लेकिन यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी तरह की स्वतंत्रता का हरण न करे, समाज की जो संस्कृति है, उसका हरण न करे और सामाजिक मर्यादा का हरण न करे। इसके लिए जरूरी है कि भूत-प्रेत, जादू-टोने, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले

कार्यक्रमों पर रोक लगे। आज इस तरह के कार्यक्रम आ रहे हैं कि गायें गायब हो रही हैं, गायें कहां जा रही हैं, वे बता रहे हैं कि गायें उठ रही हैं और आसमान में जा रही हैं, कोई रॉकेट में उनको खींच रहा है। ऐसी कल्पना से कार्यक्रम बनाकर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। नरबलि जैसी चीजों को इस रूप में दिखाया जा रहा है। अपराध जगत और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को ग्लोरिफाई किया जा रहा है, डॉन, अंडरवर्ल्ड का बादशाह, माफिया किंग - ऐसे टाइटिल उनको दिए जा रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी इन सबको देखकर प्रेरित हो। उनको कंडम करने के बजाय, उनको ग्लोरिफाई करने वाले शब्दों का इस्तेमाल होता है।

अंत में मैं यही कहूंगी कि सरकार इसके लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जरूर बनाए, जैसे फिल्मों में सेंसरशिप होती है, वरना वहां भी क्या जरूरत है, वहां तो लोग फिर भी टिकट लेकर जाते हैं। इसलिए इस बारे में कुछ न कुछ व्यवस्था हो, कुछ नीति हो, कुछ अथॉरिटी हो, सरकार उसकी कुछ गाइडलाइन सुनिश्चित करे। जैसे दूरदर्शन पहले काम करता था, न्यूज़ चैनल काम करते थे, सारे चैनल उसी तरह से काम करें, उसी दिशा में काम करें और इस देश के समाज और संस्कृति को, देश की एकता और अखंडता को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करें, मैं यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : उपसभापति जी, यह सदन बहुत गंभीरता के साथ इस सवाल पर चर्चा कर रहा है और मुझसे पहले बोलने वाले सदस्यों ने विस्तार से इस पर अपनी बातें रखी हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा जोड़ने की गुंजाइश मेरे पास नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि टी.वी. चैनल वालों का यह कहना है कि लोग देखना चाहते हैं, इसलिए हम दिखाते हैं। मैं यह मानता हूं कि sex and violence - ये दोनों चीजें ऐसी हैं, जिनके प्रति इंसान की उत्सुकता बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे-वैसे मनुष्य ने समझा कि यदि sex and violence को मर्यादित नहीं किया गया, यदि उसको अनुशासित नहीं किया गया, संयमित नहीं किया गया, तो इंसान और समाज चल नहीं सकता है। इसलिए धीरे-धीरे sex and violence को अनुशासित बनाने के लिए समाज ने नियम और कायदे बनाए। सभ्यता के विकास के दौर में जिस ढंग से sex and violence

को संयमित करने का प्रयास हुआ है, अनुशासित करने का प्रयास हुआ है, उसको फिर से अराजक बनाने की आज जो चेष्टा हो रही है, उस पर सदन की चिंता बिल्कुल जायज़ है। मैं श्याम बेनेगल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए, लेकिन सरकार के हाथ में उसको रेगुलेट करने का अधिकार दिया जाए, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। हमको याद है कि बिहार में एक बार हमारे यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और पंडित जगन्नाथ मिश्र जी उसके मुख्य मंत्री हुआ करते थे, वे एक Press Bill लेकर आए थे और यह भ्रम पैदा हुआ था कि उस Press Bill के जरिए, प्रैस की आज़ादी को नियंत्रित करने की कोशिश होगी और हम सब लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया था, उस आंदोलन में हमने लाठी खाई थी और हम करीब डेढ़ महीने तक जेल में रहे थे। इसलिए हम प्रैस की आज़ादी के पक्षधर हैं और यह मानते हैं कि प्रैस को नियंत्रित करने का कोई भी अधिकार सरकार के हाथ में नहीं रहना चाहिए। उस मामले में श्याम बेनेगल जी ने जो सुझाव दिया है, मैं उस सुझाव के साथ सहमत हूं कि इसमें सिविल सोसायटी के लोगों को, प्रैस के प्रतिनिधियों को रखा जाना चाहिए और सरकार के प्रतिनिधि भी उसमें रहें।

4N/VNK पर क्रमश:

4n/6.00/vnk-ks

श्री शिवानन्द तिवारी (क्रमागत) : ऐसी एक Regulatory Body बननी चाहिए, लेकिन वह दंत-विहीन और नख-विहीन नहीं होनी चाहिए। आज जैसे Press Council of India है, आप उसके सामने कोई शिकायत कीजिए, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे वृंदा जी ने जिस अखबार का कतरन आपको दिखाया, आप उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरे दिल्ली शहर के लोगों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि तुम सार्वजनिक जगहों पर औरतों को पीछे से च्यूंटी काटो, अगर काटते हो, तो तुम बहादुर हो और तुमको तमगा मिलेगा। एक राष्ट्रीय अखबार के द्वारा इस तरह से भड़काना, जिसका बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, उस तरह का अखबार इस तरह का विज्ञापन और इस तरह का competition चलाता है और हम लोग इसको चुपचाप दखते रहें! मैं तो अम्बिका जी को कहूंगा कि सबसे पहले यह जो आपके सामने चुनौती है कि जिस तरह के कार्यक्रम का और प्रतियोगिता का विज्ञापन इस अखबार ने निकाला है, इसके खिलाफ

मुकदमा चलना चाहिए। इसके Editor और प्रकाशक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करते हुए कि एक Regulatory Body बने और उसको ताकत दिया जाए और यह अधिकार दिया जाए कि वह जो फैसला करे, वह फैसला लागू हो। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Gireesh Kumar Sanghi; you have only five minutes.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I hope there is no conflict of interest.

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI: I run a newspaper. I don't run a TV channel. (Interruptions) Still, if you have any objection, I will...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: It was a lighter comment. Come on, Gireesh. Take it easy.

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI (ANDHRA PRADESH): Sir, an appeaser is one who feeds the crocodile hoping it will eat him in the last. सर, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जो पूरे समाज से संबंध रखता है और यह एक बहुत ही सामाजिक मुद्दा है। पता नहीं क्यों इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई वक्ताओं ने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें रखीं और कुछ वक्ता इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो एक हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, उसको उन्होंने रखा। कल क्या होगा? क्या टेलिवीजन चैनल वाले हमको बताएंगे या नहीं बताएंगे? अगर नहीं बताएंगे तो क्या होगा? मैं नहीं समझता कि यह सदन उनकी मेहरबानी पर चलता है। अगर वह हमें उनके चैनल से बताएं या नहीं बताएं, उनके बताने या नहीं बताने से पूरा समाज हमारे performance का जजमेंट करता है, जजमेंट तो वह यही करेगा कि अगर हम किसी मुद्दे पर सही बात करते हैं और अपनी बात निर्भय होकर रखते हैं, तो उसको सराहना जरूर मिलेगी।

सर, हमारी जो संस्कृति है, वह दुनिया में अपनी एक विशेषता रखती है। लॉर्ड मैकाले ने 1935 में कहा था, "I have travelled the length and breadth of this country and I did not find a single deceit, a single beggar, a single

cheat. Such is the high morale and ethos and culture of this country. And unless we change the whole perception, we cannot rule this country. And, I think, that is what is going to happen; it is happening gradually. अगर हम आने वाले बीस साल, पच्चीस साल या पचास साल देखें और कुछ आंकड़े यह बताते हैं कि 2050 में हमारे देश की आबादी 175 करोड़ हो जाएगी और विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देश हो जाएगा, वह हम अभी भी हैं। हमारा देश 2050 में आबादी में विश्व का सबसे बड़ा देश होगा।

(4O/MP पर जारी)

MP-TDB/4O/6.05

श्री गिरीश कुमार सांगी (क्रमागत) : और 2060 तक विश्व की करीब एक-तिहाई आबादी हमारे देश में होगी। इसलिए यह तो हम सबको मिलकर तय करना है कि इस जनता को, इस आबादी को, इस समाज को किस दिशा में हम ले जाएं? क्या सीख हम उनको सिखाएं? हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को हम क्या सिखाएं, क्या दिखाएं, उनको क्या समझाएं? A child tells in the street what his father and mother say at home. हमारा बच्चा जब बाहर जाता है तो हमारा जो आचरण होता है, हम उसको जो सीख देते हैं, उसकी ही वह बाहर बात करता है और हम सब जानते हैं, हमारे देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हर घर में पांच-दस टी.वी. या पांच-दस rooms हों। करीब 90 प्रतिशत से ज्यादा आबादी झुग्गी-झोंपड़ियों में रहती है या 2 room, 3 room set में रहती है और उनके पास बैठने के लिए एक ही room होता है, सोने के लिए एक ही room होता है, खाने के लिए एक ही room होता है और उसी रूम में बैठकर पोता टी.वी. देखता है, बाप देखता है, दादा देखता है। सकुटुंब उसी drawing room में बैठकर वे सब टेलीविज़न देखते हैं, जैसा कि कई वक्ताओं ने बताया। जब हम बैठकर वह देखते हैं और कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है, तो रिमोट हमें अपने हाथ में रखना पड़ता है, तुरंत चैनल बदलना पड़ता है क्योंकि बहू-बेटियां साथ में बैठी रहती हैं - तो यह हमारी संस्कृति है ! इस संस्कृति को हमें पूरे विश्व को देना है, यह नहीं कि पूरी पश्चिमी सभ्यता को हमें सीखना है। इसलिए यह जो मुद्दा है, यह बहुत अहम मुद्दा है और इस मुद्दे को मैं नहीं

समझता, कोई नया कानून, कोई नया रेग्युलेटर और कोई....आप चाहे कितने कानून बना लो, अम्बिका जी, चाहे कितनी सख्ती बरतें, बाद में विवाद आ जाएगा स्टेट एंड सेंटर का। अम्बिका जी अगर डायरेक्शन देंगी, तो इंप्लिमेंट कौन करेगा? स्टेट को करना पड़ेगा, स्टेट पुलिस को करना पड़ेगा। हमारी स्टेट पुलिस किस तरह से काम करती है, हमारे पास कितने कानून हैं, कहां-कहां क्लब चलते हैं, कहां-कहां डिस्को चलते हैं, कहां-कहां नाइट क्लब चलते हैं, यह सबको पता होता है और क्या action लिया जाता है, हम सबको पता है। इस चीज़ पर हमको बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचना है, इसलिए समाज को इंट्रोस्पैक्शन करना होगा, टी.वी. चैनल वालों को इंट्रोस्पैक्शन करना होगा कि हम जो बता रहे हैं, वह समाज के लिए सही है या नहीं है। अगर हम सही नही बता रहे हैं, उसमें हमारा कोई लालच है, किसी पैसे कमाने के इरादे से वह बता रहे हैं, तो उससे समाज distort होगा, समाज में बुराइयां आएंगी। इसलिए उनको इंट्रोस्पैक्शन करके, आपस में चर्चा करके उस चीज़ को खुद बंद करना पड़ेगा। जब तक यह नहीं होगा, सामाजिक दबाव नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई कानून, कोई रूल्स या रेग्युलेशन, कोई नया एक्ट इसको कर सकता है।

महोदय, एक छोटी सी बात और मैं इस सदन के माध्यम से रखना चाहूंगा। मैं इस सदन में 2004 में आया हूं। एक से एक महान वक्ताओं को मैंने सुना है। बहुत कमिटेड लोग हैं, पर जब बाहर नेताओं के बारे में बताया जाता है कि नेता ऐसा है, नेता वैसा है, तो दुख होता है। कामकाज छोड़कर लोग समाज सेवा में जुटे हुए हैं, कामकाज छोड़कर लोग प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं और सैक्रिफाइस करते हैं और ऐसे-ऐसे लोग सैक्रिफाइस करते हैं, जिसकी कोई चर्चा ही नहीं होती है। दूसरी ओर नेताओं की दूसरी ही छवि बताई जा रही है, इसलिए उसको भी हमें देखना है, उसके ऊपर भी विचार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

(समाप्त)

श्री उपसभापति : लास्ट स्पीकर श्री भारतकुमार राऊत हैं। ...(व्यवधान)...

श्री भगत सिंह कोश्यारी : सर, मेरा भी नाम है।

श्री उपसभापति : नहीं, आपका नाम नहीं है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी : सर, मेरा नाम है। मेरा नाम प्रस्ताव में दिया हुआ है।

श्री उपसभापति : बिलकुल नहीं है.... मेरे पास नहीं है। ...(व्यवधान)... प्रस्ताव का नहीं है। इस two and a half hours के शॉर्ट ड्यूरेशन डिसकशन में प्रस्ताव की बात नहीं होती है। राऊत जी, सिर्फ तीन मिनट बोलिए।

(4P/SC पर आगे)

-mp/sc-kgg/6.10/4p

श्री भारतकुमार राऊत : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि लास्ट मिनट में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने सारी चर्चा बहुत गौर से देखी और सुनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं...(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : मैं पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि daily हम bulletin में यह repeat कर रहे हैं कि डिबेट शुरू होने के आधा घंटा पहले जो भी नाम आएंगे, जिनका भी टाइम होगा, वही नाम लिए जाएंगे। हम repeat कर रहे हैं, यह decision हो चुका है कि कोई भी डिबेट में आखिरी moment में हाथ उठाकर participate नहीं कर सकता है। ..(व्यवधान).. आपकी पार्टी से नहीं दिया गया है। इसलिए मैं सदन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन रूल्स का हम पालन करें।

श्री भारतकुमार राऊत (महाराष्ट्र) : महोदय, जो चर्चा यहां पर दो घंटे से ज्यादा समय से हो रही है, उसे मैंने बड़ी रुचि से और गौर से सुना। मुझे यह बताना है कि जिस तरह से मीडिया हो रही है, उसे लेकर हम जरूरत से ज्यादा चिंतित हो गए हैं। मैं इस मीडिया का एक सदस्य हूं। मेरे सब ज्येष्ठ सदस्य मुझसे गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि जो-जो इल्जाम सबने मीडिया के ऊपर, विशेषतया electronic media के ऊपर लगाए हैं, ये सब मानने के बावजूद भी मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए इलाज गवर्नमेंट की regulatory authority नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट की regulatory authority लाएंगे तो अन्य जो regulatory authorities हैं, उनका जो परिणाम हुआ, वही परिणाम इसका होगा। इससे हमें जो परिणाम चाहिए, वह नहीं मिलेंगे। इसलिए If at all we are interested in bringing in a better and civilised society, there should be self-restraint. वृंदा जी ने कहा कि महिला को कम दर्शाने वाले विज्ञापन

आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ऐसा होता है और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। लेकिन वृंदा जी और यहां पर बैठे सब लोग बाहर की दुनिया में लीडर्स हैं। They are social, political and cultural leaders. अगर हमें इसके ऊपर कंट्रोल करना है, तो अम्बिका सोनी जी की गवर्नमेंट से कुछ नहीं होने वाला। ये जो लोग हैं, इनको जनता मानती है, इनके पीछे लोग हैं, इनके पीछे संगठन हैं। ये लोग ऐसा कोई campaign करें कि लोग प्रोग्राम नहीं देखें। लोग क्यों ये प्रोग्राम्स देखते हैं? वे इसलिए देखते हैं क्योंकि इनमें उनकी रुचि है, अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन उनकी रुचि होती है। अगर हम इनको बोलेंगे कि यह सब मत दिखाओ तो कोई कानून बनेगा। महोदय, कानून तोड़ने की natural प्रवृत्ति होती है, लोग कानून तोड़ेंगे। इसलिए इस तरह से कुछ करना चाहिए जिससे लोग इन्हें न देखें। यह जो आयुद्ध है, यह आयुद्ध सरकार के पास या कानून के पास नहीं है, यह social education के पास, cultural education के पास है और यह cultural education, यह social education हमारे नेताओं के बीच में है। ..(समय की घंटी).. सर, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। यहां बहुत से लोग बोल रहे थे कि यहां पाश्चात्य संस्कृति लायी जाती है। सर, यह विश्व नज़दीक आ रहा है। We are coming very close to each other. हम technology की वजह से, scientific progress की वजह से नज़दीक आ रहे हैं। We cannot be selective. अगर वहां पर मोबाइल आता है तो वह मोबाइल हमें चाहिए, वहां विज्ञान की प्रगति होती है तो विज्ञान की प्रगति हमें चाहिए, वहां के विचार चाहिए, लेकिन वहां के कोई प्रोग्राम आएं तो यहां पर नहीं चलेंगे - ऐसा selective attitude हमें नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो जनता यह नहीं मानेगी। जैसे श्याम बेनेगल साहब ने बताया कि एक प्रोग्राम जो वहां पर चला है, वही प्रोग्राम, वैसे का वैसा अगर इंडियन चैनल पर भी दिख रहा है तो उससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जब वह दूसरे नाम से, हिन्दी नाम से यहां आता है तो हमें आपत्ति होती है। We cannot be that selective. मेरी एक ही गुजारिश है कि self regulatory होना चाहिए। मैं न्यूज़पेपर में काम करता हूं। जैसे हर न्यूज़पेपर में अपना खुद का code of conduct होता है, कभी लिखित होता है, कभी अलिखित होता है लेकिन खुद का code of conduct होता है। वैसे ही चैनल्स में भी होता है। उस conduct को ठीक करने की

कोशिश करो, उससे ही कुछ फायदा होगा, आपकी regulatory authority से मुझे नहीं मालूम कितना फायदा होगा। इसलिए मेरी मंत्री जी से दरखास्त है कि आप इस तरह की एक convention बुलाओ, एक seminar बुलाओ, जिसमें सबको बुलाकर उनकी राय लो और उनको खुद को regulate करने के लिए प्रेरित करो। धन्यवाद।

(समाप्त)

(4क्यू पर क्रमश:)

KLS/4Q-6.15

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI AMBIKA SONI): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am indeed very happy that we have had an instructive and a very extensive विस्तार से यहां चर्चा हुई। चर्चा का विषय हम सब लोगों ने जैसे बार-बार दोहराया है That the impact which today's some of the television programmes, which have excessive violence and are excessively obscene, the impact, the adverse impact they have on our social values, on our family values and more especially on the young formative mind. Across the House Members have expressed their anguish and deep concern and I have very methodically noted the points of every single Member who spoke here today. I just want to assure the House that I am not any different. I may be a Minister today but I am a woman and I am a grandmother, I am as concerned as anyone of the Members who spoke and those who did not speak when we see that the values we have grown up with are getting eroded. We all worry about our children seeing too much of television, even Cartoon TV is not good, we have been told. The increasing violence in society sometimes all of us think that the viewing of TV channels, TV shows and cinema are causing violence to increase in the society. But, as Mr. Shyam Benegal pointed out and some

others, including, we, as public representatives, are conscious of the fact that there some sections of the people, many of them are young, who, probably, may not be sharing our concerns in the same degree as we have voiced them today. Then, of course, all us have directly or indirectly, placatingly or apprehensively talked of media. And the sensitivity of the media to any kind of control, any type of attempts, much more so by a Government to arbitrarily deal with them, regulate them or even to control them, we all realise that it is an extremely sensitive subject. There are competing priorities. On the one hand, the right under article 19 of the Freedom of Expression and, on the other hand, equally important the concerns of civil society, parliamentarians, NGOs, parents, weaker sections, courts have given directives and - Mr. Venkaiah Naidu has gone - the 32nd Report of the Rajya Sabha Petitions Committee dealt with it extensively. We all want to ensure that salutary community standards for broadcasting, etc. are established. These discussions are not new, I am new, I have been for seven weeks in this Office and, please, believe me when I tell you that from 1997, when it all began, in 1995 when we put the Cable Regulatory Act in place, in 1994 we made the rules, and in 1997 when the Government of that time brought a Bill for Contents and Advertisement Control, a Bill to put in a mechanism in the Lok Sabha, the Lok Sabha was dissolved and the Bill fell. I have with me the entire chorology of what happened at different times under different Governments and as Rajeev Shuklaji rightly said, all of us have been either directly or indirectly in the Government of India since 1997 till date. I do not want to read out the tabulation. The meaning of my mentioning this is that we have all been concerned and

yet this being such a sensitive subject that each time any government or any group of people or a Ministry has taken up, made up its mind to put in place a mechanism, technology, mushrooming of television channels, uplinking and downlinking rules have changed the scenario.

(Contd by 4R/SSS)

SSS/4R/6.20

SHRIMATI AMBIKA SONI (CONTD.): The whole thing has to be discussed, interacted and spoken of with the stakeholders all over again. I am making no excuses, but, realising the sensitivity all of us have condoned interaction, discussion, the evolving of a consensus on what to put in place. I would like to mention that I am so happy to hear so many of our hon. Members, in fact, almost everyone has spoken of the need to put in place some mechanism, credible, maybe self-regulatory, but, certainly independent to deal with Content Code and to deal with so many other issues concerning the various stakeholders. All over the world and probably India is one of the few countries -- I have again a list of all the countries of the world -- which have some regulator in place. Their powers, their terms of reference may be different. But there are in place, regulators. India is probably one of the very few countries which do not have. The most popular model which most people have, not today, but, on earlier occasions in our interactions, have referred to is OFCOM which is what guides the BBC. But there are several countries all over the world that have these regulators in place. We in India also in the last few years have developed some mechanism, maybe it is not effective, maybe it does not have any statutory power but the effort has been there and we should appreciate it. There is the National

Broadcasters Association, the NBA; the Indian Broadcasters Federation, the IBF. We are not happy with ISKY, as Brindaji rightly said, because it takes long. The advertisements go on and they are not able to stop them. They all and we all have to work within the rules and the framework which we have around us. We cannot ourselves violate something which has not yet given us the permission to deal with it effectively and quickly. But these organisations have also established their own codes. I welcome this for the simple reason, we may feel that they have not been able to do very much, but I welcome this because the desire on the part of broadcasters to give a content which is not obscene, which is not violence prone, which can be seen by families together. That desire is there somewhere. Let us recognise it. Maybe it has not been effective and we still have aberrations like what the channels have been mentioned in both Houses. In the course of one week there were two channels referred to and two programmes referred to. I would not like to limit this debate to any individual programme but I would like to say that even though they have set up these, they also realise that there are 480 channels today. I have the record of how many are uplinked and how many are downlinked. They don't have a universal membership. It is difficult for any Body which exists today, any association, no matter how correct their intention or how deep their desire to conform to our standards of social norms may be to represent all 480 channels. Therefore, it has been felt increasingly, as years went on, to put in place a mechanism in the way of a Broadcasting Bill which would in its place put up a Broadcasting Regulatory Authority of India. The Government has not been sitting absolutely inactive and when I say

Government I don't mean the one which came into office in 2009. I don't mean even the one which came earlier in power in 2004. I mean Government since 1997. All of us have tried to put in place committees, to have these discussions, to bring about Content Code regulations, to discuss with the broadcasters and other stakeholders.

(Contd. by NBR/4S)

-SSS/NBR-ASC/4S/6.25.

SHRIMATI AMBIKA SONI (CONTD.): But, we have not arrived at anything, because anything which is initiated by the Government turns out to be suspect. People feel that we are trying to control and that is not the intention of anyone of us.

I would also like to say -- even though the Government should not -- in the absence of this mechanism, unfortunately, it has been the role of the Ministry of I & B, with the help of some of the self-regulatory bodies or associations, with the help of an Inter-Ministerial Committee which was specially put in place by the Government, headed by officer, with a definite proviso that the Ministry of Women and Child Development must be represented, to look into all these aberrations of violations referred to by Shri Naik and others of our Cable (Regulatory) Act, 1995 and the Uplink and Downlink Rules. So, all these things are looked into by this Committee. I would say that it is an interim arrangement. The Government has also put in place, a year-or-so ago, a mechanism to monitor electronic media. We have increased channels from 150 to 300. But, what I am trying to say is, we are not sitting हाथ के ऊपर हाथ रखकर। ये attempts वीक जरूर होंगे, मगर प्रयास जरूर हो रहा है कि हम कहीं न कहीं कुछ रोक तो लगा सकें। यह मामला इतना संवेदनशील है कि जो हमारे फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो

हमारी संस्कृति है, जो हम कल्चरल डायवर्सिटी की बात करते हैं, जो हम लोगों की सामूहिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं, किसी को भी ठेस न पहुंचे, तो इस दृष्टिकोण से हमारा मंत्रालय कोशिश करता है। शायद आपको सुनने में हैरानी होगी कि पिछले तीन-चार सालों में 278 नोटिस दिए गए, 160 सिर्फ एडर्वटाइमेंट के लिए नोटिस दिए गए और शायद 119 में हो सकता है, एक-दो ज्यादा या कम हों, 119 में से आगे बढ़कर भी कुछ कार्यवाही की गई हो। कुछ चैनल्स को बंद कर दिया गया था कि उनका content कुछ साल पहले भारत में बिल्कुल चल नहीं सकता था, लेकिन इसके अलावा आप यह सब जानते हैं कि मुझ से पहले भी मंत्री रहे हैं और उनसे पहले भी रहे हैं। जब content बदला नहीं गया, या जिसके कारण नोटिस मिला हो या उस नोटिस को लापरवाही के कारण नजर अंदाज किया हो, तो कई दफ़ा भले ही अच्छा नहीं भी लगता हो, लेकिन एक नियम का पालन करने के लिए जो भी कोड है, उसके अंतर्गत काम करने के लिए, चैनल्स भी कुछ अर्से के लिए बंद कर दिए गए। यह तरीका बहुत समय तक नहीं चल सकता है। आज चैनल्स 480 हैं, कल 550 चैनल्स हो जाएंगे और आगे ये 600 हो जाएंगे। मैं विशेष तौर पर रवि शंकर प्रसाद जी से यह कहना चाहती हूं कि ये भी इस मंत्रालय में मंत्री रहे हैं और ये मुझ से ज्यादा जानते हैं। इन्होंने जो TRP का मुद्दा उठाया है, राजीव शुक्ल जी ने भी उठाया है तथा और सदस्यों ने भी इसका जिक्र किया है, एक बहुत अहम बात है कि TRP बहुत मोटिवेटिंग फोर्स है और यह जो टैम बाडी है, यह इंडस्ट्री और एडर्वटाइजेज की एक राय से बनी है। हमारी तरफ से कोशिश हुई कि एक ई-मैप भी बने, लेकिन वह चल नहीं सकी। एक BARC है, जो इसी मामले को देखना चाहती है। हम विशेष तौर पर TRP के मामले में ध्यान देने के लिए ट्राई के पास भी गए। उन्होंने कहा कि BARC कोई ऐसा इंतजाम करे, जिसमें सरकार के दो नुमाइंदे भी हों, बेशक उनको वोट देने का अधिकार न हो, लेकिन नुमाइंदे रहने चाहिए। उन्होंने सरकारी नुमांइदे रखने के लिए साफ इंकार कर दिया, कोशिश जरूर हो रही है। एक बात और है कि हम लोगों को और भी ध्यान देना पड़ेगा। आज 480 चैनल्स हैं, कल 550 आगे 600 चैनल्स होंगे, जब आपका हिट सिस्टम, HD Tv सिस्टम होगा और आज टेक्नॉलोजी इस रफ्तार से आगे बढ़ रही है.....।

(क्रमश: 4T/LPपर)

श्रीमती अम्बिका सोनी (क्रमागत) : दो सौ से अधिक न्यूज चैनल्स हमारे देश में हैं। लोगों को न्यूज चैनल्स से खबर नहीं मिलती तो टी.आर.पी. एक कारण है। जब खबर नहीं मिलती तो मैं देखती हूं कि हम लोग खबर बनाने पर विवश हो जाते हैं। हमारे नौजवान बच्चे ही तो एंकर्स हैं। वे बेचारे टेलीविजन कैमरा लिए जर्नलिस्ट बनकर खबर की तलाश में घूमते हैं। जब हम यह कहते हैं कि मीडिया ने रोजगार उपलब्ध करवाने का एक बहुत बड़ा रास्ता हमें दिखाया है, तो हमें सोचना पड़ेगा। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूं, कारण बता रही हूं कि कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण हम कई ऐसी खबरें देखते हों, सुनते हों या कई कंटेन्ट ऐसे बनते हों, जो न भी बनने पर लोग बनाना चाहते हों। वह कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि एक रेग्युलेटरी बॉडी बनाना बहुत अनिवार्य है। एक "कॉमन कॉज" एन.जी.ओ. है, शायद अरुण शौरी के पिताजी, ए.जी.शौरी उसके अध्यक्ष होते थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पी.आई.एल. दर्ज की थी, वह चल रही है। पिछले आठ-नौ सालों में सुप्रीम कोर्ट में हमने खुद चार, पांच एफिडेविट्स फाइल किए हैं। NBA वहां गए हैं, IBF वहां गया है, सिविल सोसायटी के नुमांइदे बुलाए हैं। उन्होंने 2007 में, जब गुज्जर आंदोलन हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट had suo motu put up two committees. One of them was under the distinguished legal luminary, Mr. Nariman, to look into the role of the media. We all had attended their meetings. We all had responded to their calls to give our points of view. They also came out strongly for a self-regulatory body. What I am saying is that this self-regulatory body seems to be the only way out. I am very happy to tell the House that for the last seven weeks, my colleagues, in the Ministry, and I myself had three meetings with the NBA, the IBF, the ASCII and other individual stakeholders on how to move forward. We cannot have these debates in Parliament and have Members of Parliament anguished and angry, and rightly so; have the news channels express their concerns and apprehensions. So, we have

had three meetings so far. They want to talk, they want to discuss and interact and they wanted us to nominate somebody, from the Ministry, who would take this process further. We had, in the third meeting, named the Secretary, I&B, and his colleagues, whoever he wants to take with him, to have these discussions. And, I do hope that at the end of it, we will be able to arrive at a way of putting a regulatory body in place. There is a fear. And, the fear is, as many of you, especially, Mr. Benegal, said, that if this regulatory body will only be control-content, and if Government is a Member, who will be appointing the Chairman, who will be appointing the Members. There is an apprehension. So, we will try our best to not only make it credible, self-regulatory, independent, but we would also like to put in place stakeholders of the media, members of the civil society; maybe as ex officio members, the concerned officials of the Government, just to keep abreast. And, the self-regulatory body is that what we have in mind. We have had discussions with the State Governments. Most of the State Governments have replied in support of this move. But the fear that our people have about, it being a controlled body, is what we are trying to dispel in the process. We have started to arrive at a clear format of what we are going to do.

(Contd. by 4u -- PB)

PB-AKG/4u/6.35

SHRIMATI AMBIKA SONI (CONTD.): Mr. Venkaiah Naidu had mentioned about the Rajya Sabha Committee. I did want to tell him that the Ministry has taken some action on his report. But that is also on the same thing.

Some other suggestions have come up from civil society; and they are being implemented by channels, like parental locks. But then that doesn't work. It doesn't work in the sense that when we live in one room or one family having a single TV, it doesn't work. You watch a TV together, but parental locks are something which are increasingly being put in. Defusing, blurring of images of the dead, victims of violence, discrimination, exploitation, especially, women, are being increasingly blurred by channels. We are being conscious. Watershed system has been talked of that all borderline programmes should be permitted only from 11.00 p.m. to 4.00 a.m. A greater emphasis and care is being put by channels themselves in a self-regulatory mode to show live only what is live and not to have replay being shown as live. The Election Commission has come out with its own suggestions of do's and don'ts during elections. All these concerns, in my frank opinion, can be put in place only if we are able to work towards this self-regulatory body. I agree that the Press Council of India may not have teeth. But I don't think, in recent years, anyone has said that the Press Council of India is controlled by Government. Maybe, we have to look at it all afresh, visit these institutions and mechanisms once again. If the teeth are needed, what kind, this can only be done by discussion and by interaction. So, I am very happy that the Members, by and large, were all for putting in place this body.

Believe me, the debate, the speeches, the points all of you have made, are going to be by themselves quite a pressure on all of us who are trying to define a way forward and to put in place this mechanism which I have referred to several times.

Brindaji, I am extremely surprised to hear about it; I don't know how I missed it. I do read newspapers quite thoroughly. But I did miss this item on Delhi. I will take it out and send it to the Press Council of India for whatever they can do. But I do agree with Mr. Raut that something has to also be like a social movement by all of us. We need to switch off channels. I am not putting it all on you, please. I have already accepted that what we have to do, we have to do. But we have to also think a little out-of-the-box while all this mechanism is being formulated, while we keep you informed of all what we are doing and the progress we are achieving and keeping in mind that this process has been going on for the last 12 years. I do feel that it is a welcome idea if we start some kind of social movements which will increase the voice of the people, especially, of all of us who don't want to see programmes which hurt our sensitivity.

रवि शंकर प्रसाद जी और राजीव शुक्ल जी ने TRP के बारे में कहा था। हम लोगों ने इसमें काफी कुछ काम किया है। हम लोग TRAI के पास गए। TRAI ने यह बात BARC के सुपुर्द की कि वह इसमें गवर्नमेंट के दो nominees रखे, लेकिन BARC सरकार के साथ बिल्कुल तालमेल नहीं रखना चाहता। इसके अलावा एक Standing Committee of Parliament on Information Technology ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की और पार्लियामेंट में रखी थी। ... (व्यवधान) ...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam Minister, will you yield for a minute?

SHRIMATI AMBIKA SONI: Yes.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam Minister, you may recall, I did not at all talk of content regulation, and, I hope with your wide experience, you would know that TRP management has nothing at all to

do with content. It is a private body which has acquired this right as a prop up of advertisers. Now, if we have 400 channels, mass viewing, why don't you come with a proper legislation making an autonomous body to monitor TRP? What is the problem there? There is no content conflict at all.

(Followed by 4w/SKC)

4w/6.40/skc-sch

SHRIMATI AMBIKA SONI: I am sorry, I did not say that TRP and content are the same. In seven weeks, I have, at least, learnt that much! I told you that TRP is a privately run organisation between the industry and advertising houses. It has got nothing to do with content. But you did say rightly that there is freedom of media; that there is right to creativity; there is responsibility, and creativity in advertisements should not dilute society. You said something like that. I am only upholding what you said.

श्री कलराज मिश्र: मैडम, आपने ...(व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैं उनके सवाल का भी जवाब दे रही हूं। हम लोगों ने सरकार की तरफ से टीआरपी के मामले में भी काफी कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। हम TRAI के पास भी गए, उन्होंने भी हमें अपने कुछ सुझाव दिए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी है और ये सब एक ही दिशा की ओर चल रहे हैं कि वहां भी एक इंडिपैंडेंट बॉडी बनाई जाए, जो हफ्ते के हफ्ते अपनी टीआरपी रेटिंग न दे। हम सब लोगों को इस बात का एहसास है कि ये मीटर कहां-कहां लगाए जाते हैं। जो जम्मू-कश्मीर इत्यादि दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं या फिर नॉर्थ-ईस्ट की स्टेट्स में रहते हैं, उनकी इच्छा के बारे में उन्हें कोई कन्सर्न नहीं रहता है। टीआरपी उनकी इच्छा को नहीं दिखाता है ..(व्यवधान) जी हां, बिहार, यूपी, जहां भी आप जाएं, हम लोगों को सदा इन इलाकों की ज्यादा चिंता रही है। इसलिए मैं आपको कहना चाह रही हूं कि न तो मेरा

दिमाग बंद है, न मेरे कान बंद हैं और न ही मेरी आंखें बंद हैं। इसमें मैंने सिर्फ आपको बताना चाहा था कि जो काम हम कर रहे हैं ..(व्यवधान)

श्री शिवानन्द तिवारी: उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। पूरे हाउस ने यूनानिमस ढंग से जो कन्सर्न शो किया है, उसको कैसे मीट किया जाए, यह उनको और उनकी सरकार को देखना है।

श्री उपसभापति: वही तो वह बता रही हैं।

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, I welcome the interventions of all the Members, and I specially underline that I felt strengthened and supported that everyone, in one way or the other, had suggested that there should be some regulatory body, independent, credible and with some teeth, which would take care of violations by anyone, whether they be advertisers or content creators, if they violate either the code or the regulatory act, or the up-linking and down-linking rules, that would look after that. I have already welcomed that. I have told you that you must give me a little more time. You have taken 12 years; I am not asking for that much! This is the way to go forward.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, let her complete.

SHRIMATI BRINDA KARAT: The confusion is there because you are constantly talking about self-regulation when self-regulation has miserably failed. So, what we are unanimously suggesting in this House, Sir, is that an independent regulatory authority should be set up through an appropriate legislation by Parliament. This is what we are suggesting. Don't leave it to them to set up their own bodies.

SHRIMATI AMBIKA SONI: I would like to inform the hon. Member that I did inform -- and I do not want to repeat what I have said -- that in the

last couple of years, in the absence of anything else, and not wanting Government to perform the role of a regulatory, self-regulation...

SHRIMATI BRINDA KARAT: We do not want Government regulation, Madam.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, let her complete. (Interruptions) Let the hon. Minister complete.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I have to make this point. It is not about Government regulation. We want an independent regulator.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may intervene later. Let the hon. Minister complete.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, it is not only Government that has to regulate. (Interruptions) Sir, it is not only Government control on the one hand and control of media barons on the other. These are not the only two alternatives in this country. We should have an independent regulator.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, let the hon. Minister complete.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, I am extremely sorry that I have not been able to convey what I am saying, in an articulate manner, to a very articulate MP, Shrimati Brinda Karat. I just said that I appreciate the self-regulatory bodies which have come up in the absence of anything else, which all of us had felt, should be put in place in the last 12 years, that is, an independent regulatory authority. I welcome this move. It should be viewed as a move towards adhering to the regulatory code and all that. We are talking about it with them. I have said that we are trying; the Broadcast Bill has been discussed with States.

(Contd. by hk at 4x)

HK/4x/6.45

SHRIMATI AMBIKA SONI (CONTD.): The draft Bill made by my Ministry is on the Ministry's website. The idea of putting it on the website was to get more inputs and have a national debate. These things have to be talked out. The situation is always an evolving situation with technology moving daily at a fast pace. Whatever we arrive at finally by legislation or by an Act of Parliament, it should have the maximum consensus around it. That is what we are trying to work out. I have only asked for some more time from the House. I hope the hon. Members would give me this time.

(Ends)

श्री कमाल अख्तर: सर, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: वह हो गया। ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं। अब इनसे सवाल-जवाब बहुत हो गया ...(व्यवधान)... बहुत लम्बा डिस्कसन हो गया। ...(व्यवधान)... Message from Lok Sabha ...(व्यवधान)... अब आप बैठ जाइए।

MESSAGE FROM LOK SABHA

CONSTITUTION OF THE JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Monday, the 27th July, 2009, adopted the annexed motion regarding Constitution of the Joint Committee on Offices of Profit.
>
> I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the members of Rajya Sabha appointed to the Joint Committee, may be communicated to this House."

MOTION

"That a Joint Committee of the Houses to be called the Joint Committee on Offices of Profit be constituted consisting of fifteen members, ten from this House and five from the Rajya Sabha, who shall be elected from amongst the members of each House in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote:

That the functions of the Joint Committee shall be --

to examine the composition and character of all existing "committees" [other than those examined by the Joint Committee to which the Parliament (Prevention of Disqualification) Bill, 1957 was referred] and all "committees" that may hereafter be constituted, membership of which may disqualify a person for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament under article 102 of the Constitution;

to recommend in relation to the "committees" examined by it what offices should disqualify and what offices should not disqualify;

to scrutinize, from time to time, the Schedule to the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, and to recommend any amendments in the said Schedule, whether by way of addition, omission or otherwise;

That the Joint Committee shall, from time to time, report to both Houses of Parliament in respect of all or any of the aforesaid matters;

That the members of the Joint Committee shall hold office for the duration of the present Lok Sabha;

That in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of members of the Committee;

That in other respects, the rules of procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

That this House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in the said Joint Committee and do communicate to this House the names of the Members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee."

(Ends)

SPECIAL MENTIONS

CONCERN OVER THE HORRENDOUS SCENARIO OF WITCH-HUNTING IN THE COUNTRY

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (RAJASTHAN): It is an irony that within the country, where women are worshipped like goddesses, there is another India where 'Ghar-ki-Lakshmi' is branded a 'witch' and mercilessly slaughtered. There are endless instances where women have been called witches, stripped, shaven and made to make rounds of village and even eat and drink their own urine and excreta. In many parts of Rajasthan, particularly Dungarpur, Banswara, Udaipur, Tonk, Chittorgarh, Kota and Bhilwara it has been seen that women are branded as witches. If not killed, such women often commit suicide. Witch-hunting is prevalent in the tribal heartland of Central Gujarat,

comprising Vadodara, Panchmahals and Dahod districts. Branded as 'dakan', about 100 cases are reported in these three districts every year. Most of these cases go unrecorded or are registered under mental or physical harassment.

A woman guilty of refusing advances, reluctance to sell land or bearing girl children, is likely to be branded a 'witch' and have her breasts chopped off, teeth broken, limbs amputated, eyes gouged out and then killed. Such cases abound especially in tribal-dominated belts.

Above alarming scenario of 'witch-hunting' is a crying shame and every State has its own horror stories. Hence, I would urge the hon. Minister for Home Affairs to take remedial steps on war footing.

(Ends)

DEMAND TO CONFER BHARAT RATNA ON THE VETERAN CLASSICAL VOCAL MUSICIAN GANGUBAI HANGAL POSTHUMOUSLY

श्री शिवानन्द तिवारी(बिहार): उपसभापति महोदय, पिछले 22 तारीख को कर्णाटक के हुबली में हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की लब्ध-प्रतिष्ठित गायिका पद्मविभूषण गंगूबाई हंगल का निधन हो गया। गंगूबाई का जीवन कथा-कहानी की नायिका की तरह है। केवट जाति-जैसी पिछड़ी जाति में पैदा हुई गंगूबाई अपने खून में संगीत लेकर पैदा हुई थीं। यह वह जमाना था, जब गाने वाली लड़कियों को समाज में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, लेकिन गंगूबाई ने समाज की मान्यताओं और वर्जनाओं के विरुद्ध संघर्ष किया तथा कभी समर्पण नहीं किया।

गुरबत, सामाजिक अपमान और भूख से संघर्ष करते हुए गंगूबाई ने उस समय के विख्यात संगीतज्ञ, किराना घराना के उस्ताद, सवाई गंधर्व से संगीत सीखा। इसके लिए 30 किलोमीटर रेल की यात्रा और उसके बाद लम्बी पैदल यात्रा भी की। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी इनके गुरु-भाई थे। दोनों ने साथ-साथ संगीत की शिक्षा प्राप्त की। दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा संगीत का पंडित है, यह कहना कठिन है।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस महान संगीतज्ञ और एक आदर्श महिला, जिसने अपनी मान्यताओं और निष्ठा के लिए सतत् संघर्ष किया, को मरणोपरान्त भारत रत्न से सम्मानित करे। हालाँकि यह सम्मान उनको जीवन-काल में ही मिल जाना चाहिए था। (समाप्त)

श्री राजनीति प्रसाद(बिहार): सर, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक(गोवा): सर, मैं भी अपने आपको इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूँ। (Followed by 4y/KSK)

4Y/KSK-HMS/6.50

CONCERN OVER RE-APPOINTMENT AND EXTENSION OF TERM OF RETIRED OFFICERS AND EMPLOYEES

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (ORISSA): Sir, nowadays, retired officers and employees are getting extension in the name of vast experience. Civil servants are in a very advantageous position to get extension or get different postings before their retirement. Especially, all the State Chief Secretaries, Police DGPs, Principal Secretaries to the Government of India or State Governments usually find a suitable job for themselves before retirement. Now, the retirement age of the Doctors, Professors, Lecturers and civil servants has been increased. Even the private sector companies also prefer to appoint retired Government officers. Then, what will happen to the young civil servants, doctors, engineers, diploma holders and ITI diploma holders? Their future is blocked.

For example, in Punjab, recently, the Punjab State Electricity Board has decided to re-appoint the retired employees, having lot of experience, on consolidated salary of Rs.7000 for SSO and Rs.5000 for SSA thereby ignoring 20,000 diploma holders and ITI trained youngsters.

If the financial condition of PSEB is not good, the Government should ask them to work on a consolidated salary. But, giving fresh employment to retired employees, who are also getting pension, and denying the right of employment to poor young people may create explosive situation in all the State Governments and the Central Government. I urge upon the House and the Government that the space for youngsters should not be encroached upon by the retired personnel. They have already enjoyed their share of the cake. Let others should get their share and the re-appointment of retired Government officers and employees should be stopped.

(Ends)

DEMAND TO SET UP MONITORING COMMITTEES FOR IMPLEMENTATION OF LAWS RELATING TO LAND MANAGEMENT IN THE COUNTRY

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़) : उपसभापति महोदय, वन भूमि व्यवस्थापन अधिनियम के लागू होने के बाद भी कई राज्य सरकारें राजनीतिक आधारों पर या तो कार्य-गति को धीमा किये हैं या फिर भेदभाव कर रही हैं। यहां तक कि आवेदन फार्म जमा करने में भी भेदभाव बरता जा रहा है। अतः राज्य स्तरीय निगरानी समितियों का गठन जरूरी है। इन्हें अधिकार संपन्न करने के लिए कानून में प्रावधान हेतु संशोधन आवश्यक होगा।

महोदय, वन भूमि का व्यवस्थापन एक समय सीमा में होना था, लेकिन भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश के बाद भी अब तक अनेक राज्यों में भूमि व्यवस्थापन का काम पूरा नहीं हुआ है। यह समिति समूचे राज्य का दौरा कर इस कार्य को संपन्न कराएगी। इस समिति के सचिव, वन सचिव होंगे तथा समिति को समस्त आवश्यक कागजात व सुविधाएं राज्य शासन उपलब्ध कराएगी। इस के खर्च का वहन भारत सरकार करेगी। प्रत्येक 2 माह में समिति अपनी कार्य सूचना केन्द्रीय वन मंत्री को देगी। महोदय, वन भूमि व्यवस्थापन आदिवासी राज्यों के जिलों में होना है, जिन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान,

असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडूचेरी व अन्य राज्यों के जिले हैं।

महोदय, वन भूमि पर व्यवस्थापन का कार्य अत्यंत धीमी गति से चलाया जा रहा है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि प्रत्येक राज्य में अब तक भूमि व्यवस्थापन का कार्य कितना शेष है, इस की जानकारी समस्त राज्यों से मंगाए और निर्देश जारी करे कि भूमि व्यवस्थापन में ढील बरतने वाले राज्यों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। वन भूमि व्यवस्थापन पूरे तौर पर नहीं होने के कारण आदिवासियों में रोष है। (समाप्त)

(4 जेड/डीएस पर आगे)

GSP-DS-6.55-4z

DEMAND TO GIVE INCENTIVES TO SUGAR INDUSTRY FOR ITS REVIVAL

SHRI N. R. GOVINDARAZAR (TAMIL NADU): Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to request the Government to consider the following demands of sugar industry. The sugar industry in our country is facing crisis. There is a steep drop in sugar output to 14.5 million tonnes in 2008-09 season against 26.4 million tonnes in 2007-08. It is due to deficit rains, which it has resulted in a surge in sugar prices in the open market. Many sugar mills are not able to utilize their crushing capacities sufficiently.

The sluggish progress of the South-West monsoon and likelihood of further reduction in sugarcane production may affect profit margins of sugar mills in the next season. Hence the sugar industry deserves incentives from the government. The sugar industry should be allowed duty free import of sugarcane harvesting equipment. To purchase sugarcane harvesters, 3.5 per cent subsidy should be given to the Farmers' Cooperative Societies and also soft loan for the balance

amount. The industry is asking for permanent withdrawal of tax on self-generated electricity to encourage captive power generation. The government should provide special facilities for letters of credit to sugar factories to enable them to import raw sugar to tide over the shortage of domestic sugar production.

The excise duty on molasses should be rationalized to Rs. 250 per tonne which is not at Rs. 750 per tonne. Tax Holiday for the revenue earned from co-generated power should be extended for another ten years and thus will encourage more investment in this sector. "Declared goods" status should be granted to ethanol.

Therefore, I urge upon the Government to pass necessary orders in this regard. (Ends)

SHRI S. ANBALAGAN (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DEMAND TO INCREASE SEATS IN VARIOUS MEDICAL COLLEGES IN BIHAR

डा. सी.पी. ठाकुर (बिहार): उपसभापति महोदय, 2008-2009 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश की बढ़ती हुई आवश्यकता और वित्तीय संसाधन को देखते हुए यह सुझाया गया है कि हमारे पास जो भी पुराने संसाधन और आधारभूत संरचनाएं हैं, उनका समुचित दोहन किया जाए। इसी सुझाव के तहत मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूँ कि वह पटना में 80 एकड़ में फैले और स्वयं के निर्मित भवन में कई वर्षों से चल रहे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आई.जी.आई.एम.एस.) में 100 छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति प्रदान करे। साथ ही, बिहार के अन्य सभी मेडिकल कॉलेजों, यथा पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, गया मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, भागलपुर मेडिकल कॉलेज आदि में प्रत्येक में 50-50 सीटें बढ़ाई जाए, जिससे बिहार के छात्रों को इस प्रयोजनार्थ अन्यत्र न भटकना पड़े और इस देश में

चिकित्सकों की जो कमी है, उसकी भी भरपाई हो सके। सदन में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने भी स्वास्थ्य परिचर्चा में भाग लेते हुए इस आशय का वक्तव्य दिया था।

(समाप्त)

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार): सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

DEMAND TO STOP SUPPLY OF READY TO USE THERAPEUTIC FOODS IN THE COUNTRY

SHRI SYED AZEEZ PASHA (ANDHRA PRADESH): Sir, I would like to draw your attention to the recent information that international agencies like UNICEF have been importing some kind of branded 'Ready to Use Therapeutic Foods' for the treatment of severely malnourished children and this has been used and distributed without the permission of the Government of India. This is highly objectionable.

International agencies and vested interests are attempting to push these foods in contravention of the Government policy. I believe that indiscriminate distribution of such foods will commercialize young child feeding through market driven approaches. This would change the feeding patterns of young children in the villages and simplify the management of malnutrition. This will also destroy local solutions developed by the people; even the Indian Academy of Pediatrics recommends a modified family pot approach for this.

The Government of India's letter no. Z-28020/50/2003-CH, Ministry of Health and Family Welfare stated as follows:

"The Ready to Use Therapeutic Foods is plum peanut, from France @ US $ 60 per child. RUTFs are not an accepted strategy of the Government of India, neither under RCH nor ICDS."

I am astonished how this food were procured and distributed by UNICEF in some of the States without any knowledge or approval of the Ministry of Women and Child Development, Government of India.

I demand that this RUTF procurement and supply should immediately be stopped (Ends)

(Followed by SK-5a)

aka-sk/5a/7:00

DEMAND TO TAKE STEPS TO FACILITATE EARLY CONSTRUCTION OF DADRI POWER PROJECT IN UTTAR PRADESH

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश) : सर, मेरा Special Mention UP में power crises और shortage से मुताल्लिक है।

सर, 21 जुलाई को हिन्दुस्तान टाइम्स में इश्तिहार के ज़रिए उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें सारे पावर प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा दिया है। इस पत्र में दादरी पावर प्रोजेक्ट का नाम-ओ-निशां नहीं है। 2003 में सरकार ने 2500 एकड़ किसानों की उपजाऊ ज़मीन उनसे हासिल करके कम्पनी को उपलब्ध करा दी थी। आज 2009 में यह प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर पर ही है। किसानों का बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था और वे जेल भी गए थे। उत्तर प्रदेश की जनता बिजली की समस्या से बेहाल है, तो क्या केन्द्रीय सरकार को यह प्रोजेक्ट NTPC को नहीं दे देना चाहिए या उत्तर प्रदेश सरकार को इसे खुद बना लेना चाहिए।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि दादरी (उ0प्र0) में पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए सरकार अधिगृहीत की गई जमीन को अपने अधिकार में लेकर उस पर पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की कार्यवाही तत्काल शुरु करे, जिससे प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। (समाप्त)

جناب محمد ادیب (اتر پردیش) : سر، میرا اسپیشل مینشن، یو۔پی۔ میں پاور کرائسس اور شورٹیج سے متعلق ہے۔

سر، 21 جولائی ہندوستان ٹائمس میں اشتہار کے ذریعے اتر پردیش نے گھوشنا پتر جاری کیا ہے، جس میں سارے پاور پروجیکٹس کا بیوا دیا ہے۔ اس پتر میں دادری پاور پروجیکٹ کا نام و نشان نہیں ہے۔ 2003 میں سرکار نے 2500 ایکڑ کسانوں کی اپجاؤ زمین ان سے حاصل کرکے کمپنی کو اپلبدھ کرا دی تھی۔ آج 2009 میں یہ پروجیکٹ صرف پیپر پر ہی ہے۔ کسانوں کا بہت بڑا آندولن ہوا تھا اور وہ جیل بھی گئے تھے۔ اترپردیش کی جنتا بجلی کی سمسیہ سے بےحال ہے تو کیا کیندریہ سرکار کو یہ پروجیکٹ این۔ٹی۔پی۔سی۔ کو نہیں دے دینا چاہئے یا اترپردیش سرکار کو اسے خود بنا لینا چاہئے۔

آخر میں، میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ دادری (اترپردیش) میں پاور پروجیکٹ استھاپت کرنے کے لئے سرکار ادھیگرہت کی گئی زمین کو اپنے ادھیکار میں لے کر اس پر پاور پروجیکٹ کے نرمان کی کاروائی تتکال شروع کرے، جس سے پردیش کی اورجا آوشیکتاؤں کی پورتی ہو سکے۔

(ختم شد)

DISCRIMINATION IN EDUCATION LOAN FOR AGRICULTURIST'S CHILDREN

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (TAMIL NADU): Sir, education loan for students from the Nationalised Banks are available on various terms according to the amount needed. Even though the Government promised to give loan for the students to the tune of Rs. 3 lacs without any security, on the basis of the earnability after completion of the course, the banks are demanding security and not accepting agricultural land. When the agriculturist's children are trying to pursue education in the USA, the UK and other countries, it costs more than Rs. 15 lacs for the course. But the banks totally reject the request saying that

agricultural lands are not acceptable as security. It is a clear discrimination and exclusion of rural students who cannot possess commercial properties. Hence I request the hon. Minister for Finance to direct the banks to accept the agricultural land as security for education loan and disburse the amount quickly so that the rural students can benefit in global market.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (GOA): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SYED AZEEZ PASHA (ANDHRA PRADESH): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI (ANDHRA PRADESH): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : महोदय, मैं श्री नाच्चीयप्पन जी के स्पेशन मेंशन को ऐसोसिएट करता हूं।

DEMAND TO GIVE STATUS OF SCHEDULED TRIBES TO MUSLIMS BELONGING TO MEV AND MEVASI CASTES

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : महोदय, मेरा विशेष उल्लेख मेवों को मीणा जाति के समान अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के संबंध में है।

महोदय, ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक मेव और मेवासी जातियां मेवाती की तरह आदिवासी समूह हैं। मेवातियों को जहां जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, वहीं मुस्लिम होने के कारण मेव और मेवासी इस सुविधा से वंचित हैं। महोदय, ये तीनों जातियां मीणों की तरह जनजातियां हैं। अकबर के काल तक तो मेव और मीणों में विवाह संबंध भी होते थे। चन्दबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में मेवासी जाति का उल्लेख किया है। इमरत खां ने "तारीख-ए-मेव" में लिखा है कि मेव और मीणा कौम के पूर्वज एक ही थे, जिनका पेशा नाव चलाना था। अंग्रेजों ने जनजाति अपराध कानून के तहत मेव और मीणा दोनों जातियों को अपराधी जनजातियों की सूची में डाला था। आजादी के बाद यह कानून रद्द हो गया। मीणों को

जहां जनजातियों की सुविधा दी गई, वहीं मुस्लिम होने के कारण मेव और मेवासियों को यह लाभ नहीं मिला। यह खेदजनक और दुखद है कि एक समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ के बावजूद जहां एक ओर मीणा जनजाति का दर्जा पाकर सरकारी सेवा में विभिन्न पदों पर आसीन हैं, वहीं दूसरी ओर मेव अभी भी घोर सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें विकसित करने के लिए, समान आर्थिक-राजनैतिक अवसर दिए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकार गैर हिन्दुओं को भी आरक्षण का लाभ दे सकती है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेव और मेवासी जाति के पिछड़ेपन को देखते हुए उन्हें भी संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए।

(समाप्त)

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : महोदय, मैं श्री अंसारी जी के स्पेशल मेंशन से अपने आपको ऐसोसिएट करता हूं।

SHRI SYED AZEEZ PASHA (ANDHRA PRADESH): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

(Followed by 5B-ysr)

-SK/YSR-NB/7.05/5B

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at five minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 28th July 2009.